के. सी. वसंत कुमार और एक और।

1 .

कर्नाटक राज्य

8 मई, 1985

[ वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., डी. ए. देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, ए. पी. सेन और ई. एस. वेंकटरमैया, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 29 (2), 338 (3) और साधनों की 340 वैधता का परीक्षण कर्नाटक राज्य के दिनांक 22.2.1977 आदेश में किया गया है।जैसा कि 1 मार्च, 1979 और 27 जून, 1979 के सरकारी आदेश द्वारा संशोधित किया गया है-नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए दिशानिर्देश और नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान, जो राज्य की राय में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवा में प्रवेश के मामले में "मेनिटोरियम सिद्धांत और भेदभाव के" "प्रतिपूरक सिद्धांत" के बीच संघर्ष, कैसे हल किया जाए-"पिछड़े वर्ग" शब्द का सांविधिक निर्माण एक समाज के लिए न्याय या नियम का निर्माण, समझाया गया-अनुच्छेद 338 (3) और 34 का निर्माण। और 16 (4) और आरक्षण की सीमा जिसे समझाया जा सकता है-शब्द और वाक्यांश-"पिछड़ेपन" "पिछड़े वर्गों" का अर्थ, "सामाजिक रूप से औरशैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग "।

पूर्व-स्वतंत्र काल में, मैसूर की पूर्व रियासत जो अब कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रणाली शुरू की गई थी। 1918 में, मैसूर के महाराजा की सरकार ने पिछड़े वर्गों की समस्या की जांच और रिपोर्ट देने के लिए मैसूर के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर लेस्ली सी. मिलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उस समिति को भेजे गए प्रश्न थे: (i) लोक सेवाओं में भर्ती के तत्कालीन मौजूदा नियमों में आवश्यक परिवर्तन; (ii) पिछड़े वर्गों के सदस्यों के बीच उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं और (iii) कोई अन्य विशेष उपाय जो दक्षता को भौतिक रूप से प्रभावित किए बिना लोक सेवा में पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं। 'पिछड़े वर्ग' और 'पिछड़े समुदाय' वाक्यांशों का उपयोग लगभग एक दूसरे के स्थान पर किया गया था और यह कि संविधान के अनुच्छेद 335 में निहित है कि किसी भी आरक्षण से दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए, संविधान के अधिनियमित होने से तीन दशक से अधिक समय पहले अनुमान लगाया गया था। समिति ने 1921 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसकी राय थी कि ब्राह्मणों के अलावा राज्य के सभी समुदायों को पिछड़े समुदायों के रूप में समझा जाना चाहिए जिनके बारे में उसने कुछ सिफारिशें की थीं। उस रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए सरकारी आदेश जारी रहे।1956 तक अर्थात पाँच एकीकृत इकाइयों को एक साथ लाने वाले राज्यों का संगठन-पूर्व मैसूर राज्य (बेल्लारी जिले सहित), कुर्ग और चार राज्य।बॉम्बे के जिले, हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से और सोग कनारा जिला और कोल्लेगल तालुक जो पहले बॉम्बे का

हिस्सा थे।मद्रास राज्य। पिछड़े समुदायों की अलग-अलग सूचियाँ थीं पाँच एकीकृत इकाइयाँ और उन्हें कुछ समय के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई राज्यों का पुनर्गठन।

एकरूपता अनबाक लेल राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कयलक।1959 की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य के लिए पिछड़े वर्गों की सूची। उस अधिसूचना की वैधता और उसी विषय पर उसके बाद जारी की गई एक अन्य अधिसूचना की वैधता राज्य सरकार को ब्राह्मणों, बनियों और कायस्थों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को पिछड़े समुदायों के रूप में माना गया था, जिसे मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष राम कृष्ण सिंह बनाम में चुनौती दी गई थी। मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1950 मैसूर 338। इन दोनों अधिसूचनाओं को उच्च न्यायालय ने (क) के रूप में अभिनिर्धारित करते हुए निरस्त कर दिया था। जहाँ तक विवादित अधिसूचनाओं में पिछड़े वर्गों की सूची थी, जिसमें राज्य की 5 प्रतिशत आबादी और ब्राह्मणों, बनिया और कायस्थों के अलावा सभी हिंदू समुदाय और एंग्लो-इंडियंस और पारसी को छोड़कर राज्य के अन्य सभी गैर-हिंदू समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में माना गया था, इसके परिणामस्वरूप सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान करने के बजाय कुल आबादी के लगभग 5 प्रतिशत वाले कुछ बहिष्कृत सामुदायिक समुदायों के साथ अधिक भेदभाव किया गया; (बी) उन समुदायों के लिए प्रावधान करना जो तथाकथित आगे के समुदायों के लिए थोड़ा पिछड़े थे, उन समुदायों के लिए प्रावधान करने के बराबर नहीं था जो कुल आबादी का लगभग 5 प्रतिशत थे।

संविधान के अनुच्छेद (15 (4) के तहत वास्तव में आवश्यक संरक्षण; (सी) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को कुछ मामलों में जातियों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

इसलिए राज्य सरकार ने 8 जनवरी को एक समिति का गठन किया।

1960 डॉ. आर. नागन गौड़ा की अध्यक्षता में

राज्य में पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित संदर्भों के साथ करना। सीई: ( i) यह निर्धारित करने में अपनाए जाने वाले मानदंडों का सुझाव देना कि राज्य में लोगों के किन वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जाना चाहिए और (ii) यह सुझाव देना कि इस प्रकार बताए गए मानदंडों का सटीक तरीके से पालन किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार उन व्यक्तियों को निर्धारित कर सके जिन्हें तकनीकी संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली वरीयता प्राप्त करनी चाहिए। उक्त समिति ने 19 फरवरी, 1960 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने 9 जून, 1900 को व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए 22 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्गों के लिए, 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के संबंध में एक आदेश पारित किया और शेष 60 प्रतिशत सीटों को योग्यता के आधार पर भरने की अनुमति दी गई। सरकार के आदेश को एस. ए. पार्थ और अन्य में मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। वी. मैसूर राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1961 माई. 220. उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकारी आदेश में निहित निर्देश इस आशय का है कि यदि कोई सीट या सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं तो 354

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

और अनुसूचित जनजातियाँ खाली रह गईं, उन्हें उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

अन्य पिछड़े वर्ग असंवैधानिक थे। इसने कुछ निर्देश भी दिए आरक्षण के कोटे की गणना के तरीके के बारे में

बनाया जाए। इसके बाद नागन गौड़ा द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

16 मई, 1961 को समिति। उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 10 जुलाई, 1961 को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य के लिए एक आदेश जारी किया। उस आदेश द्वारा, राज्य सरकार ने 81 वर्गों के लोगों को पिछड़े वर्गों के रूप में और 135 वर्गों के लोगों को अधिक पिछड़े वर्गों के रूप में निर्दिष्ट किया और 30 प्रतिशत सीटें-पेशेवर और तकनीकी संस्थानों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया। 15 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः प्रतिशत और 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं और शेष 52 प्रतिशत सीटों को योग्यता के आधार पर भरने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश को एम. आर. बालाजी और अन्य में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

वी. मैसूर राज्य [1963] पूरक। 1 एससीआर 439।

उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय में, अनुच्छेद 15 (4) में आने वाले "सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग" शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया गया था कि "अनुच्छेद 15 (4) के तहत पिछड़ेपन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का होना चाहिए।

शैक्षिक। यह या तो सामाजिक या शैक्षिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और शैक्षिक दोनों है।

शिक्षात्मक "। यह समझाने के बाद कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को कैसे निर्धारित किया जाना है, और उन वर्गों के निर्धारण का सवाल जो शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, अदालत ने माना कि सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों की सूची में लिंगायत समुदाय का होना गलत था। आरक्षण की सीमा के प्रश्न पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

" आम तौर पर और व्यापक रूप से, एक विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रचलित परिस्थितियाँ। और इस प्रकार अनुमति दी

याचिका।

इसके बाद सरकार ने 26 जुलाई, 1963 को एक और आदेश पारित किया।

जिसने निर्देश दिया कि पेशेवर और तकनीकी में 30 प्रतिशत सीटें

कॉलेजों और संस्थानों को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि उस क्रम में परिभाषित किया गया है और 18 प्रतिशत सीटें योजना के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नेतृत्व किया। उस क्रम में निर्धारित मानदंड

सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का निर्धारण दो गुना था-आय और पेशा। इसमें कहा गया है कि जो लोग कृषि के व्यवसायों का पालन करते थे,

लघु व्यवसाय, घटिया सेवा, शिल्प या अन्य व्यवसाय जिनमें शारीरिक श्रम शामिल है और जिनकी पारिवारिक आय रुपये से कम थी। 1,200 प्रति वर्ष पिछड़े वर्गों से संबंधित माना जाना था। इस आदेश पर डी. जी. विश्वनाथ बनाम में उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था। मैसूर सरकार और अन्य। ए. आई. आर. 1964 माई. 132 विभिन्न आधारों पर कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जाति के संदर्भ के बिना पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूरी तरह से सही नहीं था और इसने उम्मीद व्यक्त की कि

राज्य एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण करेगा ताकि उसके वास्तविक होने की संभावना न रहे।

पूछताछ की जाए। आर. चित्रलेखा और अन्र में इस फैसले के खिलाफ दायर अपील में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। [ 1964 ] 6 एस. सी. आर. 368 सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

में निर्णय के साथ उच्च न्यायालय के फैसले के बीच असंगति

बालाजी का मामला और उन्होंने कहा कि "355 से दो सिद्धांत प्रमुखता से सामने आते हैं।

के. सी. वी. कुमार पी. कर्णकारा

बालाजी, अर्थात्, (i) नागरिकों के एक समूह की जाति उनके सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में एक प्रासंगिक चौकस रुख हो सकता है; और (ii) हालांकि यह नागरिकों के वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक, कारक है, लेकिन यह उस ओर से एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं हो सकती है-जाति एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने में केवल एक प्रासंगिक परिस्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संबंधित प्राधिकरण को नागरिकों के एक समूह के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकता है यदि वह जाति के संदर्भ के बिना ऐसा कर सकता है। यद्यपि इस न्यायालय ने नागरिकों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने से जाति को बाहर नहीं किया है, लेकिन इसने इसे मजबूर करने वाली परिस्थितियों में से एक नहीं बनाया है, जो एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

इसके बाद राज्य सरकार ने कर्नाटक पिछड़े को नियुक्त किया।

श्री एल. जी. हवानूर की अध्यक्षता में वर्ग आयोग ने एक विस्तृत जांच के बाद 19 नवंबर, 1975 को चार बड़े खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्ति को तीन समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए-(ए) 15 जातियों से युक्त पिछड़े समुदाय, (बी) 128 जातियों से युक्त पिछड़ी जातियाँ और (सी) 62 जनजातियों से युक्त पिछड़ी जनजातियाँ। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए, आयोग ने पिछड़े वर्गों को (ए) 9 जातियों से युक्त पिछड़े समुदायों (बी) 115 जातियों से युक्त पिछड़ी जातियों और (सी) 61 जनजातियों से युक्त पिछड़ी जनजातियों में विभाजित किया। आयोग के अनुसार, पिछड़े समुदाय की इकाइयाँ वे जातियाँ थीं जिनके छात्रों का औसत एस. एस. एल. सी. उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत था।

1972 में प्रति हजार जनसंख्या पर परीक्षा राज्य के औसत से कम थी। ( जो 1.69 प्रति हजार था) लेकिन राज्य के औसत के 50 प्रतिशत से अधिक और

पिछड़ी जातियाँ और पिछड़ी जनजातियाँ वे जातियाँ और जनजातियाँ थीं जिनका छात्र औसत राज्य के औसत के 50 प्रतिशत से कम था।

डोम्बर और वोद्दार और जो खानाबदोश और अधिसूचित जनजातियाँ थीं।

इन पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या (अनुसूचित जातियों को छोड़कर)

और अनुसूचित जनजाति), आयोग के अनुसार, लगभग 45 प्रतिशत था

राज्य की कुल जनसंख्या। दोनों सूचियों के बीच का अंतर-एक नीचेसंविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुच्छेद 15 (4) और दूसरा

कुछ समुदायों, जातियों और जनजातियों का बहिष्कार जो सामाजिक और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े लेकिन जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था।

अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजन के लिए तैयार की गई सूची से। आयोग ने पुनः अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए दोनों की सराहना की गई

आरक्षण की अवधिः ( (i) पिछड़े समुदाय 16 प्रतिशत; (ii) पिछड़े समुदायजाति 10 प्रतिशत; और (3) पिछड़ी जनजाति 6 प्रतिशत और कुल 32 प्रतिशत।

अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत के साथ 32 प्रतिशत आरक्षण जाति और अनुसूचित जनजाति कुल राशि का 50 प्रतिशत थे।

यदि पिछड़े जनजातियों को आवंटित कोटे में सीटें/पद खाली रहते हैं, तो वे इसे पिछड़े समुदायों और पिछड़ी जातियों को सौंपा जाना चाहिए। इसी तरह

यदि पिछड़ी जातियों को आवंटित कोटे में सीटें/पद खाली रहते हैं, तो वे

इसे पिछड़े समुदायों और पिछड़ी जनजातियों को सौंपा जाना चाहिए। अगर,

हालाँकि, उन तीनों में से किसी को भी आवंटित कोटे में सीटें/पद खाली रहते हैं।

श्रेणियां, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित में बदला जाना चाहिए

जनजातियाँ। इनमें से किसी भी श्रेणी द्वारा सीटें खाली रहने की स्थिति में।

उन्हें सामान्य पूल, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

एस सी आर।

356

उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 22 फरवरी, 1977 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत उसने पिछड़े समुदायों को सूचीबद्ध किया। पिछड़ी जातियाँ और पिछड़ी जनजातियाँ जिन्हें पिछड़ी माना जाएगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए वर्ग। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि (क) केवल इन पिछड़े वर्गों के ऐसे नागरिक जिनकी परिवार की सभी स्रोतों से प्रति वर्ष आय रु। 8000 ( केवल तुम) और उससे नीचे के लोग इन अनुच्छेदों के तहत विशेष व्यवहार के हकदार होंगे और (बी) पाँच श्रेणियां, अर्थात्; एक वास्तविक कृषक, एक कारीगर, एक छोटा व्यवसायी, जो सरकारी सेवा में या आकस्मिक श्रम सहित निजी रोजगार के तहत संबंधित सेवाओं में नियुक्ति रखता है; और कोई भी व्यक्ति जो स्वयं नियोजित है या नागरिकों के शारीरिक श्रम से जुड़े किसी भी व्यवसाय में लगा हुआ है, उसे एक विशेष समूह के रूप में माना जाएगा, इस विशेष समूह के ऐसे नागरिक जिनकी पारिवारिक आय रु। 4,800 ( केवल चार हजार आठ सौ रुपये) और प्रति वर्ष से कम दो अनुच्छेदों के तहत विशेष उपचार के लिए पात्र होंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि (i) पारिवारिक आय का अर्थ है नागरिक और उसके माता-पिता की आय और यदि माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो उसकी आय।

कानूनी संरक्षक; और (ख) संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों और नागरिकों के विशेष समूह के संबंध में 40 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना, जिसमें पिछड़े समुदाय (20 प्रतिशत), पिछड़ी जातियाँ (10 प्रतिशत), पिछड़ी जनजातियाँ (5 प्रतिशत) और विशेष समूह (5 प्रतिशत) शामिल हैं। सरकारी आदेश में उल्लिखित पिछड़े समुदायों की सूची में राज्य सरकार ने मुसलमानों को इस प्रकार शामिल किया

कुल 16 पिछड़े समुदाय। पिछड़ी जातियों की सूची में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से दूसरी पीढ़ी तक ईसाई धर्म में परिवर्तित 129 जातियां और 62 अनुसूचित जनजातियां थीं। पिछड़े वर्गों के लिए

आरक्षण 40 प्रतिशत था और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत के साथ, सीटों/पदों का कुल आरक्षण 58 प्रतिशत हो गया और योग्यता पूल के लिए केवल 42 प्रतिशत बचा।

22 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेश और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए 4 मार्च, 1977 को जारी एक अन्य अधिसूचना को भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।

एस. सी. सोमशेखरप्पा और अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। ( 1977 की रिट याचिका संख्या 4371 और 9 अप्रैल, 1979 को निपटाई गई संबंधित रिट याचिका)। याचिकाओं को अनुमति देना; उच्च न्यायालय ने (i) अरासु समुदाय को 'पिछड़े समुदायों' की सूची में शामिल करने को रद्द कर दिया।

दोनों अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए; (2) (ए) बालिजा (बी) देवाडिगा (सी) गनिगा (डी) नयिंडा (ई) राजपूत और (एफ) सतानी को पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल करना और (ए) बन्ना (बी) गोरखा (सी) जाट (डी) कोंगा (ई) कोटारी (एफ) कोयावा (जी) मलयाली (बी) मणियानानी या (मुनियानी) (आई) पडट्टी (जे) पडियार (के) पांडवकुल (1) रावल और (एम) रावत को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना।

और (iii) अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य सिविल सेवाओं में पिछड़े समुदायों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण, कानून के अनुसार आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को स्वतंत्रता आरक्षित करना। अन्य मामलों में वर्गीकरण और आरक्षण को बरकरार रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 136,357 के तहत उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ 1979 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6656 और 9854/1979 दायर की गई हैं।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका

उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के बाद, मई के एक आदेश द्वारा

1 , 1979 , अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था। 27 जून, 1979 के एक आदेश द्वारा राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) दोनों के उद्देश्यों के लिए विशेष समूह के लिए आरक्षण को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके 22 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेश को संशोधित किया। इस प्रकार आज की तारीख में, अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्यों के लिए कुल आरक्षण 68 प्रतिशत है और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए 66 प्रतिशत है। पेशेवर और तकनीकी कॉलेजों में केवल 32 प्रतिशत सीटें और सरकारी सेवाओं में 34 प्रतिशत पद हैं जिन्हें योग्यता के आधार पर भरा जा सकता है। भारत के संविधान

के अनुच्छेद 32 के तहत दायर ये रिट याचिकाएं राज्य सरकार के 22 फरवरी, 1977 के आदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं, जैसा कि 1 मई, 1979 और 27 जून, 1979 के सरकारी आदेशों द्वारा संशोधित किया गया था।

विशेष अनुमति द्वारा याचिकाओं और अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

उन्होंने निम्नलिखित राय व्यक्त की,

चंद्रचूड़ के अनुसार, सी. जे.

आरक्षण के मुद्दे पर निम्नलिखित प्रस्ताव इस प्रकार काम कर सकते हैं -

आयोग के लिए दिशानिर्देश जिसे कर्नाटक सरकार नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है, बेहतर रोजगार प्रदान करने के प्रश्न की जांच करने के लिए और

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक अवसर जो आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है।

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण

प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए, एक साधन परीक्षण के आवेदन के बिना, पंद्रह साल से अधिक की अवधि के लिए। संविधान के आने के पचास साल बाद और पंद्रह साल होंगे, जो कि उत्पीड़ित वर्गों के लिए सामाजिक उत्पीड़न, अलगाव और अपमान के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए एक उचित रूप से लंबी अवधि होगी। [ 376 सी-डी]

2. मतलब की परीक्षा, यानी आर्थिक पिछड़ेपन की परीक्षा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए

उपरोक्त (1) में उल्लिखित अवधि के बाद की जनजातियाँ। यह आवश्यक है कि निजी

वंचित समाज के नेतृत्व वाले वर्ग को अनिश्चित काल के लिए तरजीही लाभों पर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [ 376 ई-एफ]

3. जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गों का संबंध है, दो परीक्षण

रेसर के उद्देश्य से उनकी पहचान करने के लिए संयुग्म रूप से लागू किया जाना चाहिए

रोजगार और शिक्षा में निवेश: एक, कि वे तुलनीय होने चाहिए

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके पिछड़ेपन के मामले में

नेस; और दो, कि उन्हें राज्य सरकार जैसे साधन परीक्षण को पूरा करना चाहिए

इसे प्रचलित आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

[ 376 एफ-जी]

4. रोजगार, शिक्षा और विधायी क्षेत्रों में आरक्षण की नीति

संस्थानों की समीक्षा हर पाँच साल में की जानी चाहिए। यह तुरंत खर्च कर देगा

एक अवसर (i) राज्य को विशेष रूप से उत्पन्न होने वाली विकृतियों को दूर करने के लिए

आरक्षण नीति के तथ्य और (ii) पिछड़े और गैर-358 लोगों के लिए

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

पिछड़े, के व्यावहारिक प्रभाव पर एक सार्वजनिक बहस में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए

आरक्षण की नीति। [ 376 एच; 377 ए]

प्रति देसाई। जे.

साढ़े तीन दशकों की अवधि के लिए, पहचान की अंतहीन खोज

नीति निर्माता, कानून या कार्यपालिका में परिलक्षित नीति की व्याख्या करने वालेप्रशासनिक आदेशों और विपरीत दिशा में एक उछाल जोड़ा है, अर्थात्,

जिन्होंने सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर की ओर (प्रतिलोम) जाने का प्रयास किया है

आंदोलन को रिवर्स गियर में रखें ताकि नीचे की ओर (अनुलोम) क्रम में आगे बढ़ सकें सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के एक समूह या वर्ग के रूप में पहचाना जाना

पीछे की ओर। संविधान ने एक समतावादी समाज का वादा किया था; यह एक जाति थी।

संविधान के कार्यकरण को असहमति या संवाद के बिना स्वीकार किया गया था कि जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने के लिए एक कार्यशील मानदंड प्रस्तुत करती है

अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजन के लिए नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। [ 377 डी-जी]

अनुच्छेद 15 (4) की भाषा 'वर्ग' को संदर्भित करती है न कि जाति को। वरीयता

ऐसा व्यवहार जिसे भेदभावपूर्ण के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता था, दिया जाना था

वर्ग, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ दिखाया गया है और नहीं

एक जाति के सदस्य जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से माना जा सकता है

पीछे की ओर। [ 378 ए-बी]

उच्चतम न्यायालय के फैसलों से यह स्पष्ट है कि वही उथल-पुथल

न्यायपालिका की ओर से इस सवाल पर कि क्या जाति होनी चाहिए

पिछड़ेपन की पुनरावृत्ति के लिए आधार। न्यायपालिका ने अपनी पारंपरिक व्यवस्था को बरकरार रखा

उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी और इस तरह कथित वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया। अभिव्यक्ति

' पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए न्यायालयों में कमोबेश

जाति लेबल पर आधारित नहीं होने वाले अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण

यह विचार कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होने के लिए, समूह के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान संकेत होने चाहिए।

[ 378 ई; 384 ई-एफ]

मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती चंपकम दोराईराजद और अन्र। [ 1951 ] एससीआर

525 ; एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य [1963] पूरक। 1 एस. सी. आर. 439; टी. देवडेसैन वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ 1964 ] 4 एस. सी. आर. 680; आर. चित्रलेखा और अन्र। वी.

मैसूर राज्य और अन्य। [ 1964 ] 6 एस. सी. आर. 368; त्रिलोकी नाथ और अन्र। वी. की स्थिति

जम्मू और कश्मीर और अन्य। [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 265; त्रिलोकी नैश और अन्र। वी. की स्थिति

जम्मू और कश्मीर और अन्य। [ 1969 ] 1 एससीआर 103; ए. पीरियाकरुप्पन आदि। तमिलनाडु राज्य [1971] 2 एस. सी. आर. 430; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. यू. एस. वी. बलराम

आदि. [1972] 3 एससीआर 247; जानकी प्रसाद परिमू और अन्य। आदि। वी. जम्मू राज्य& कश्मीर और ओआरएस। [ 1973 ] 3 एस. सी. आर. 236; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। प्रदीप टंडन और

ओआरएस। [ 1976 ] 2 एस. सी. आर. 761; केरल राज्य और अन्र। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। [ 1976 ) 1 एससीआर 906; कुमारी के. एस. जयश्री और अन्र। वी. केरल राज्य और अन्र। [ 1977 ]

1 एससीआर 194; और अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) ने प्रतिनिधित्व किया।

एसोसिएशन की ओर से इसके सहायक महासचिव द्वारा v. भारत संघ

& ओआरएस। [ 1981 ] 2 एस. सी. आर. 185, संदर्भित।

जाति समाज का एक क्षैतिज विभाजन है जो एक वर्ग में फैला हुआ है।

किसी क्षेत्र या पूरे राज्य का जिला और कभी-कभी इसके बाहर भी। द 359

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका

शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा जाति व्यवस्था की अवधारणा है। वहाँ हैं।

जाति व्यवस्था की चार आवश्यक विशेषताएं जो होमो पदानुक्रम में बनी रहती हैं

चीकस चरित्र; (i) पदानुक्रम (ii) समानता (iii) विवाह पर प्रतिबंध और (iv) वंशानुगत व्यवसाय। अधिकांश जाति अंतर्विवाही समूह हैं। दो समूहों के बीच अंतर-विवाह की अनुमति नहीं है। लेकिन 'प्रतिलोम' विवाह पूरी तरह से अज्ञात नहीं हैं। इसी तरह शहरीकरण के आगे बढ़ने के साथ, विभिन्न जातियों के सदस्य धीरे-धीरे हार मान रहे हैं, पारंपरिक व्यवसायों और शुद्ध अशुद्ध व्यवसायों को श्रम की गरिमा की धारणा विकसित करके अस्वीकार किया जा रहा है। चूंकि स्वतंत्रता के फल समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमान रूप से वितरित किए गए थे, इसलिए प्रत्येक जाति में जाति के सदस्यों के बीच आर्थिक पुनरुत्थान के आधार पर एक तिहरा विभाजन अस्तित्व में आया।जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उन्होंने एक उच्च वर्ग हासिल कर लिया है

स्थिति (वर्ग चेतना) और नीचे वाला मध्यम वर्ग है और तीसरा जाति के गरीब वर्ग से संबंधित है। इससे यह एहसास हुआ कि जाति संस्कृति आर्थिक हित में मदद नहीं करती है। वास्तव में एक ही जाति के ऊपरी वर्ग पर वास्तव में उसी जाति के निचले स्तर का शोषण करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए, जाति व्यवस्था का आधार, अर्थात् शुद्धता और प्रदूषण धीरे-धीरे विभिन्न लोगों की आर्थिक स्थिति से विस्थापित हो रहा है। एक ही जाति के वर्ग। यह लगभग सभी हाथों से माना जाता है कि जाति संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरोत्तर क्षरण का सामना कर रही है। नया संगठन, तथाकथित जाति संगठन, पारंपरिक जाति संरचना और जाति परिषदों से काफी अलग है। जाति के सदस्यों के बीच आर्थिक अंतर तेज हो गया है, लेकिन इतना तेज नहीं है कि जाति की भावनाओं और संबंधों को दफन कर दिया जाए। जाति संरचना के इस परिवर्तन के सामने, जाति के लेबल को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्ग या सामाजिक समूह की जांच की जानी चाहिए [385 सी-एच; 386 ए-डी]

ग्रामीण समाज में जाति अक्सर आर्थिक रूप से प्रतिबिंबित नहीं होती है।

इसके द्वारा संचालित शक्ति और इसके विपरीत। सामाजिक अनुसंधान और आर्थिक स्थिति एक निर्विवाद पारस्परिकता प्रदर्शित करती है। जाति जितनी निचली होगी, उसके सदस्य उतने ही गरीब होंगे। जाति के सदस्य जितने गरीब होंगे, जाति उतनी ही नीची होगी। जाति और आर्थिक स्थिति, एक-दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए, जिस सामाजिक स्थिति पर कब्जा कर लिया गया है और किसी व्यक्ति या वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आर्थिक शक्ति है।

ग्रामीण समाज। सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति इस तरह से बुनी और जुड़ी हुई हैं।

भारतीय ग्रामीण समाज में कैट प्रणाली जो कोई भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता है कि यदि गरीबी इसका कारण है, तो जाति सामाजिक पिछड़ेपन का प्राथमिक सूचकांक है, ताकि सामाजिक पिछड़ेपन को अक्सर व्यक्ति की जाति के संदर्भ में आसानी से पहचाना जा सके। दुख की बात है कि हमारे देश में जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसने धर्म की बाधाओं को भी पार कर लिया है। जाति व्यवस्था ने अन्य धार्मिक और असंतुष्ट हिंदू संप्रदायों में प्रवेश किया है, जिनके लिए जाति का अभ्यास अभिशाप होना चाहिए और आज हम पाते हैं कि अन्य धार्मिक आस्थाओं के अनुयायी और हिंदू असंतुष्ट कभी-कभी रूढ़िवादी हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था के कठोर अनुयायी होते हैं। [ 336 ई-एच]

आर्थिक पदानुक्रम, जाति वर्गीकरण, व्यवसाय में साझा स्थिति,

निवास, उपभोग की शैली, साक्षरता का स्तर और ऐसे कई अन्य कारक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर जाते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार एक जाति सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. पी. एल. से संबंधित होने के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पागल भीड़ है।

एस सी आर।

360

जिसे इसके नामकरण द्वारा सामाजिक और सामाजिक सूची में शामिल किया जाएगा।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। कुछ जातियों को कई लोगों द्वारा जाना जाता है -

पर्यायवाची शब्द जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है और उन्हें पूर्ण बनाता है

कवरेज लगभग असंभव है। ऐसी स्थिति में बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है

मान लीजिए, यदि किसी विशेष जाति को पिछड़े के रूप में माना गया है, तो उसके सभी पर्यायवाची शब्द

चाहे राज्य सूचियों में उल्लिखित हो या पिछड़े के रूप में नहीं। एक बार फिर कुछ

केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से वापस माने जाने के लिए जातियाँ वार्ड, ने खुद को इस हद तक नीचा दिखाया है कि उन्हें कोई संकोच नहीं था

विभिन्न प्रकार के दोषों को इंगित करने और अन्य कारकों को जोड़ने में

पिछड़ेपन का, अपनी जातियों के साथ। इस तरह की बीमारी का एकमात्र उपाय हैसामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने के लिए एक विधि तैयार करना।

जाति के संदर्भ के बिना, लोगों के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद

जिस जाति से वे संबंधित हैं। [ 387 बी-एच; 388 ए]

सामाजिक पहचान के आधार के रूप में जाति को अस्वीकार करने के लिए कुछ अन्य पहलू

और शैक्षिक पिछड़ेपन इस प्रकार हैं: ( i) यदि पसंदीदा उपचार के लिए राज्य संरक्षण

सामाजिक और शैक्षिक निर्धारण के लिए जाति को एकमात्र प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है

पिछड़ेपन; खतरा बहुत बड़ा है कि केवल यह दृष्टिकोण ही जाति व्यवस्था को वैध बनाएगा और उसे कायम रखेगा। यह हमारे घोषित धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ ठीक नहीं है जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यह धारणा कि किसी जाति के सभी सदस्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान रूप से पिछड़े हैं, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। इस तरह का दृष्टिकोण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने की एक जटिल समस्या का अति सरलीकरण प्रदान करता है (ii) यह मान्यता प्राप्त है कि आरक्षण को उसी जाति में आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति वाले वर्ग द्वारा हड़प लिया गया है; और (iii) जाति, जैसा कि हिंदू समाज में समझा जाता है, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि के लिए अज्ञात है। इस प्रकार, जाति मानदंड उपरोक्त समुदायों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूह की पहचान करने के लिए एक विश्वसनीय मानदंड प्रदान नहीं करेगा, हालांकि आर्थिक पिछड़ेपन होगा।

[ 388 एफ-जी; 389 ए; एफ]

इसलिए, एकमात्र मानदंड जिसे यथार्थवादी रूप से तैयार किया जा सकता है वह है

आर्थिक दुर्बलता। इसमें कुछ प्रासंगिक मानदंड जोड़े जा सकते हैं जैसे कि समूह का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, आजीविका कमाने के लिए इसका अवसर आदि, लेकिन बड़े पैमाने पर आर्थिक पिछड़ेपन बोझ-सितारा होना चाहिए। [ 389 एफ]

दीर्घकालिक गरीबी भारतीय समाज का अभिशाप है। बाजार अर्थव्यवस्था और

मुद्रा कताई संस्कृति ने अपने सदस्यों के प्रति समाज के सामान्य व्यवहार को बदल दिया है। उच्च जाति को ग्रामीण क्षेत्रों में भी पारंपरिक, स्वैच्छिक या जबरन दर्जा या सम्मान नहीं मिलता है, जो कि अत्यधिक पश्चिमीकृत शहरी समाज की बात है। बैंक संतुलन, संपत्ति धारण और धन शक्ति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है और शीर्ष स्तर तक पहुंचने के अवसरों की गारंटी देती है। धन कैसे अर्जित किया जाता है, इसका बहुत महत्व है। महात्मा गांधी के साथ साधनों की शुद्धता गायब हो गई और हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां लक्षय साधनों का निर्धारण करते हैं। चाहे कोई इसे पसंद करे या न करे, यह वर्तमान परेशान करने वाली स्थिति है। [ 389 जी-एच; 390 ए-बी]

किसी न किसी रूप में आरक्षण दशकों से रहा है। अगर एक सर्वेक्षण

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले विभिन्न जातियों के परिवारों के संदर्भ में, पसंदीदा उपचार के लाभों के बारे में, यह 361 होगा।

के. सी. वी. कुमार वी, कर्नाटक

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आरक्षण के लाभ छीन लिए जाते हैं

पिछड़ी जातियों की शीर्ष मलाईदार परत। इससे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए।

[ 390 ई]

प्रतिपूरक भेदभाव या सकारात्मक के लिए अवैध आर्थिक मानदंड

कार्रवाई स्वीकार की जाती है, यह सामाजिक और शैक्षिक के मूल उद्देश्य पर प्रहार करेगी पिछड़ेपन, और साथ ही साथ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना

जाति संरचना का विनाश जो बदले में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आगे बढ़ाएगा

राष्ट्र का। यह दृष्टिकोण वास्तविकता में जुड़वां को बदलने का प्रयास करता है।

संवैधानिक लक्षय: एक, भारतीय समाज के जातिगत स्तरीकरण को कायम रखने के लिए हड़ताल करना ताकि प्रगतिशील आंदोलन को रोका जा सके और एक ठोस कदम उठाया जा सके।

अनुसूचित जनजातियाँ। भेदभाव और शोषण के हजारों साल एक पीढ़ी में मिटा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी आर्थिक मानदंड है

उन लोगों के लिए पसंदीदा उपचार से इनकार करके आवेदन करने के लायक है जो

इससे पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर चुके हैं। और अंत में आरक्षण की एक समय अवधि होनी चाहिए अन्यथा रियायत बन जाती है।निहित स्वार्थ। [ 391 ई-एच; 392 एजे

पर चिन्नाप्पा रेड्डी जे।

आरक्षण प्रणाली का विरोधाभास जो इसके तहत किया जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) को 29 (2) के साथ पढ़ा जाता है।

लाल लोगों के बीच आत्म-अपमान की भावना। दुनिया में कहीं और जातियाँ, वर्ग या समुदाय धन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं खड़े होते हैं।

पिछड़ेपन की स्थिति। दुनिया में कहीं और पिछड़ेपन का दावा करने और यह दावा करने की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि 'हम आपसे अधिक पिछड़े हैं। यह एक दुखी और परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। [ 392 ई-एफ]

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनमें से सभी शानदार रहे हैं

'लोगों के कमजोर वर्गों' के रूप में वर्णित, समाज को अव्यवस्थित बनाने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है; उन्हें सुविधा की आवश्यकता है; उन्हें प्रक्षेपण की आवश्यकता है; उन्हें प्रणोदन की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकताएँ उनकी माँगें हैं। मांगें अधिकार के मामले हैं न कि परोपकार के। वे समानता की माँग करते हैं, दान की नहीं। वे स्थिति और अवसर की समानता के अपने संवैधानिक अधिकार का दावा करते हैं और

आर्थिक और सामाजिक न्याय। कई पुलों को खड़ा करना पड़ता है, ताकि वे रूबिकॉन को पार कर सकें। राज्य के तहत व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार को ऐसे दो सेतु माना जाता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत पदोन्नति और आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है। [ 393 सी-डी]

3. अदालतें आवश्यक रूप से पहचान करने के लिए सबसे सक्षम नहीं हैं

पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए व्यापक और बहुत सामान्य तरीके को छोड़कर दिशा-निर्देश निर्धारित करना। अदालतें इसके लिए सुसज्जित नहीं हैं; अदालतों के पास सामाजिक पिछड़ेपन को मापने के लिए कोई कानूनी बैरोमीटर नहीं है और वास्तव में लोगों से, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों से, स्तर दर स्तर श्रेणीकरण और क्षरण के आधार पर हटा दिए जाते हैं। और, भारत इतना विशाल देश है कि इसकी स्थिति 362 है।

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। 9.सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह राज्य से राज्य, क्षेत्र से क्षेत्र, जिले से जिले और एक से दूसरे तक भिन्न होता है। जातीय धार्मिक, भाषाई या जाति समूह से दूसरे में। वापस पहचानने के लिए एक परीक्षण

वार्ड वर्ग जो एक समूह पर लागू होने पर उपयुक्त प्रतीत हो सकते हैं

लोग पूरी तरह से अनुचित और अनुचित हो सकते हैं यदि दूसरे पर लागू किया जाए

लोगों का समूह। कोई सार्वभौमिक परीक्षण नहीं हो सकता है; कोई अनन्य नहीं हो सकता है।परीक्षण; कोई निर्णायक परीक्षण नहीं हो सकता है। वास्तव में, इसे लागू करना व्यर्थ हो सकता है और

कठोर परीक्षण। इसकी व्यापकता और समग्रता को देखा जा सकता है।

स्थिति। [ 398 ए-सीजे

4. के उद्देश्य के लिए किसी भी दिशानिर्देश को निर्धारित करने का प्रयास करने से पहले

सामाजिक रूप से पहचान करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का निर्धारण करना औरशैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नुकसान से बचना चाहिए

सवाल के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण, जो आम तौर पर बेहतर, अभिजात्यवादी रहा है

और, इसलिए, अस्पष्ट। परिणाम यह है कि अनुसूचित जातियों का दावा

और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को समानता के लिए

मानव और संवैधानिक अधिकारों को भुला दिया गया है और उनके अधिकार डूबे हुए हैं।

जिसे "तरजीही सिद्धांत" या "सुरक्षात्मक या संयोजन" के रूप में वर्णित किया गया है निंदनीय भेदभाव "। जब तक कि ये श्रेष्ठ, पितृसत्तात्मक और पैतृकवादी न हों

मनोवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। इसमें शामिल समस्याओं को सही मायने में समझना मुश्किल है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े लोगों के दावे में उनके संबंधित होने से उत्पन्न होने वाले लाभों के उनके वैध हिस्से के लिए वर्ग

मानवता और एक ऐसे देश के लिए जिसका संविधान न्याय, सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक और सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता। [ 393 ई-एच]

5. इसका समर्थन करने के लिए न तो सांख्यिकीय आधार है और न ही विशेषज्ञ साक्षय है

यह धारणा कि यदि आरक्षण अधिक है तो दक्षता अनिवार्य रूप से प्रभावित होगी

50 % , यदि आरक्षण को आगे बढ़ाया जाता है या यदि आरक्षण को प्रोमो तक बढ़ाया जाता हैराष्ट्रीय पद। दक्षता शब्द न तो पवित्र है और न ही गर्भगृह।

कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए। ' दक्षता 'एक मंत्र नहीं है जो फुसफुसाया जाता है

शिष्य के कान में गुरु। केवल एक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना

जरूरी नहीं कि एक अच्छे प्रशासक को चिह्नित किया जाए। एक कुशल प्रशासक,

एक व्यक्ति इसे लेता है, वह होना चाहिए जिसके पास अन्य गुणों के अलावा क्षमता होसहानुभूति के साथ समझें और इसलिए, बहादुरी से समस्याओं से निपटने के लिए

आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो लोगों के कमजोर वर्गों का गठन करता है।

अध्ययन में केवल सर्वश्रेष्ठ को ही प्रवेश दिया जा सकता है। यदि ऐसा है तो नियम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं।ऐसे पदों पर नियुक्ति और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। नियम हैं।

चयन की एक उपयुक्त विधि प्रदान कर सकते हैं। यह निश्चित हो सकता है कि पदों के लिए बहुत उच्च स्तर के कौशल या दक्षता और कुछ पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है

अध्ययन के लिए उच्च स्तर के उद्योग और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा है, तो नियम हो सकते हैंएक उच्च न्यूनतम योग्यता मानक और एक उपयुक्त विधि निर्धारित करें

चयन करें। विभिन्न न्यूनतम मानक और चयन के विभिन्न तरीके हो सकते हैं

पदों और अध्ययन के पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। लेकिन, दक्षता को ऊपरी हिस्से को छोड़ने के लिए छलावरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

वर्ग सेवाओं, विशेष रूप से उच्च पदों और पेशेवरों पर एकाधिकार रखते हैं।

व्यावसायिक संस्थान। अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) को ध्यान में रखते हुए, तथाकथित 363

के. एच. वी. फुमार वी. कर्नाटका

मेरिटोरियम और क्षतिपूर्ति सिद्धांतों के बीच विवाद का कोई महत्व नहीं है। [ 395 डी; जी-एच; 396 सी-जी; 397 एफजे

6. सामाजिक असमानता के तीन आयाम वर्ग, स्थिति और शक्ति हैं।

इन तीनों आयामों में से प्रत्येक अंतरंग और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति। इन तीन आयामों में से किसी से भी देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि आर्थिक कारक पिछड़ेपन के सबसे निचले स्तर पर है और गरीबी दोषी कारण और प्रमुख विशेषता है। आर्थिक शक्ति का जाति व्यवस्था, भूमि और शिक्षा के साथ दृढ़ संबंध है, भारत में आर्थिक शक्ति के दो प्राथमिक स्रोत उच्च जातियों का एकाधिकार रहा है। सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था में इस तरह बुनी और एकीकृत की गई है कि कोई भी बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता है कि यदि गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन का प्राथमिक कारण है, तो जाति सामाजिक पिछड़ेपन का प्राथमिक कारण है।

पिछड़ेपन को अक्सर किसी व्यक्ति की जाति के संदर्भ में आसानी से पहचाना जा सकता है।

आर्थिक पदानुक्रम, जाति वर्गीकरण, व्यवसाय में साझा स्थिति,

निवास, उपभोग की शैली, साक्षरता का मानक और इस तरह की विविधता

अन्य कारक सामाजिक और शैक्षिक दिशा में योगदान करते प्रतीत होते हैं। पिछड़ेपन। [ 398 एफ; 399 सी-एच 400 जी-एच)

7. " अनुच्छेद 16 (4) में निर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग,

संक्षिप्त विवरण के बावजूद, सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान हैं

नागरिकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़े वर्ग '

अनुच्छेद 15 (4) में पूरी तरह से वर्णित है। फिर से "के लिए विशेष प्रावधान

एडवांसनेंट 'एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें इसके अलावा कई और चीजें शामिल हो सकती हैं।

रियायती या मुफ्त आवास, आवश्यकताओं से छूट पर जोर दिया गयाअन्य वर्गों आदि का मामला। अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण दिया जाना है।

उन पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करने के लिए, जो सरकार की राय में हैं

सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं। इसलिए, आरक्षण होना चाहिए

इसका उद्देश्य पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करना है। इसका पालन करना चाहिए कि

आरक्षण को प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता से मेल खाना चाहिए। कोई कारण नहीं हैस्वयं संविधान द्वारा प्रस्तुत यह दिशानिर्देश भी क्यों नहीं होना चाहिए

अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजनों के लिए भी अपनाया गया। सीटों का आरक्षण

पेशेवर कॉलेजों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है

प्राप्त किया, आरक्षण की सीमा इससे थोड़ी अधिक भी हो सकती है पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत। [ 403 एच; 404 ए-एफ]

8. वैधानिक व्याख्याओं के सामान्य नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है

संवैधानिक साधनों की व्याख्या करें जो सुई जेनरिस हैं और जिनसे संबंधित हैं

महत्व और परिणाम की स्थितियाँ। संविधान को दिया जाना चाहिए

उदार व्याख्या ताकि अपने सभी नागरिकों को न्याय का पूरा पैमाना दिया जा सके

वादा किया था। [ 406 डी-ई]

अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को संकुचित करने का कोई कारण नहीं है।

16 ( 1 ) और इसमें सामाजिक न्याय और समानता की व्यापक अवधारणाओं को पढ़ने से इनकार करते हैं।

वास्तव में अनुच्छेद 16 (1) को पढ़ना आवश्यक है ताकि किसी भी संघर्ष में न आए।

[ 1984 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 46 और 335 के साथ। एक संवैधानिक दस्तावेज को पढ़ा जाना चाहिए ताकि

इसके प्रावधानों को संश्लेषित करें और वैमनस्य से बचें। यह कहने का मतलब है कि समानता

भी। यह सच है कि पहली नज़र में अनुच्छेद 16 (4) राज्य की शक्ति को बचाता प्रतीत होता है। नियुक्तियों और पदों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करना

एक पूर्व-विद्यमान शक्ति को प्रकट करता है और एक जोरदार तरीके से मान्यता को व्यक्त करता हैऐसा न हो कि उस शक्ति पर जाति का कोई संदेह हो। ऐसा कोई उपकरण नहीं है

विधायिकाओं और संविधान बनाने वाले निकायों के लिए अज्ञात। अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) के निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए व्याख्या के नियम की प्रकृति में अधिक है। अनुच्छेद 16 (1) की व्याख्या करने की संभावना ताकि

अधिक समानता के बजाय संकीर्ण समानता को अनुच्छेद 16 (4) द्वारा बाहर रखा गया है।

( 425 - सीई]

9. अनुसूचित के अस्तित्व की स्थितियों के निकटता का परीक्षण

जातियाँ व्यावहारिक रूप से सामाजिक और सामाजिक आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर देंगी।शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अन्य फिर अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ,

यह मौजूदा उच्च वर्गों के प्रभुत्व को पूर्ववत कर देगा, और पिछड़े वर्गों की श्रेणी से उच्च वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच के वर्गों के पर्याप्त बहुमत को बाहर कर देगा

निकाय सभी 'खुले' पदों और सीटों और आरक्षित पदों पर कब्जा कर लेगा।और सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों और उन लोगों को मिलेंगी जो

अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ। इनमें से अधिकांश 'प्रबुद्ध' वर्गों के पीछे और निकट अनुसूचित जातियों और जनजातियों से आगे उच्च और सूखे रह जाएंगे, जिसमें कभी भी खुद को सुधारने का मौका नहीं होगा। [ 406 जी-एच; 407 एजे

10. सिद्धांत रूप में, पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है।

और अधिक पिछड़े वर्ग, यदि दोनों वर्ग केवल थोड़े पीछे नहीं हैं, लेकिन

सबसे उन्नत वर्गों से बहुत पीछे। वास्तव में ऐसा वर्गीकरण होगा

अधिक पिछड़े वर्गों को रखने के लिए आवश्यक; अन्यथा पिछड़े वर्गों के जो अधिक पिछड़े वर्गों की तुलना में थोड़े अधिक उन्नत हो सकते हैं

सभी सीटों के साथ चले जा सकते हैं, जैसे कि आरक्षण तक ही सीमित था

अधिक पिछड़े वर्ग और थोड़ा अधिक के लिए कोई आरक्षण नहीं बनाया गया था

उन्नत पिछड़े वर्ग, सबसे उन्नत वर्ग साथ चले जाएँगे

सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध सभी सीटें पिछड़े वर्ग के लिए कोई नहीं छोड़ती हैं।

कक्षाएँ। [ 409 ए-डी]

11. परीक्षण औसत छात्र आबादी को अपनाने के बारे में

राज्य के सभी उच्च विद्यालयों की अंतिम तीन उच्च विद्यालय कक्षाओं में उस समुदाय के एक हजार नागरिकों के संबंध में सापेक्ष पीठ के वार्डनेस का आकलन करने के आधार के रूप में, कम आधार को अपनाना एक गलत तस्वीर दे सकता है। आखिरकार, अगर

एक पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के सवाल पर विचार कर रहा है या

पदों पर नियुक्ति, आधार संभवतः औसत संख्या होनी चाहिए

उस समुदाय के छात्र जिन्होंने निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है

तीन साल और शायद उस समुदाय के व्यक्तियों की औसत संख्या जो पिछले तीन वर्षों में स्नातक किया है, क्योंकि स्नातक आम तौर पर, मिनी है

संभवतः अधिकांश पदों के लिए अधिकतम योग्यता, आरक्षण की सीमा

यहां तक कि पद के वर्ग के संदर्भ में भी भिन्न होता है। [ 490 डी-एच] 365

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका

12. आरक्षण का प्रतिशत एक कारक नहीं है जिस पर एक न्यायालय

हाथ में कोई सामग्री के बिना उच्चारण कर सकते हैं। अदालत के लिए यह कहना कि आरक्षण 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत मनमाना होगा और संविधान हमें मनमाना होने की अनुमति नहीं देता है। [ 410 ई-एफ]

13. जाति और वर्ग की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से

आरक्षण और आरक्षण विरोधी बयानबाजी के पीछे का दर्शन, कारण और बयानबाजी, संवैधानिक प्रावधान और अलग-अलग न्यायिक रुख, निम्नलिखित उभरते हैं; (क) स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं जो एक तरफ जमींदार, विद्वान, पुजारी और व्यापारी वर्ग जैसे अग्रगामी वर्गों और दूसरी तरफ बहिष्कृत और दलित वर्गों के बीच खड़े हैं, अर्थात। दूसरी ओर अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ; (ख) गरीबी, जाति, व्यवसाय और निवास प्रमुख कारक हैं जो एक वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में चिह्नित करने में योगदान करते हैं, वे जिन रीति-रिवाजों का सम्मान करते हैं और पालन करते हैं, जिन अनुष्ठानों से वे डरते हैं और उन आदतों का पालन करते हैं जिन्हें वे अपनाते हैं और पालन करते हैं, जिन त्योहारों का वे आनंद लेते हैं और मनाते हैं और यहां तक कि जिन देवताओं का वे सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं, वे उनके सामाजिक स्तर और पिछड़ेपन को पहचानने में हल्के तत्व हैं; (ग) सामाजिक रूप से हीन माने जाने वाले कई वर्गों और समुदायों के बीच, बाल विवाह बना रहता है, सप्तपदी के शासन का पालन नहीं किया जाता है; जाति पंचायत द्वारा तलाक दिए जाते हैं; (घ) पोशाक और कार्य की आदत एक और संकेत है कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अक्सर एक-दूसरे को दर्शाती है।

पिछड़े वर्ग; (च) इन कारकों से जुड़ा वजन मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो केवल विचारशील, मर्मस्पर्शी जांच और विश्लेषण से ही सामने आ सकता है। यह गणितीय माध्यम से नहीं किया जा सकता है।

सूत्र लेकिन केवल गोल में देखने या पूरी स्थिति पर एक नज़र डालने से। कभी-कभी कुछ जातियों या सामाजिक जातियों की आसानी से पहचान करना संभव हो सकता है।

सामूहिक रूप से सामाजिक रूप से अग्रगामी या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। गरीबी, निश्चित रूप से, बुनियादी है, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मूल कारण होने के साथ-साथ दुखद परिणाम भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल गरीबी ही पर्याप्त नहीं है।

लोगों के विशाल बहुमत के कारण संवैधानिक ब्रांडिंग को आमंत्रित करें

हमारा देश गरीबी से ग्रस्त है लेकिन उनमें से कुछ सामाजिक और

शैक्षिक रूप से आगे और अन्य पिछड़े। भारत जैसे देश में जहाँ80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, यहां तक कि अधिकांश लोग

सामाजिक रूप से अगड़े वर्ग गरीब हो सकते हैं। ग्रामीण सामाजिक सीढ़ी में वे हैं

वास्तव में उच्च और बड़े वर्गों के आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद

उन्हें सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में ब्रांड नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, वहाँ

कई जातियाँ या अन्य सामाजिक समूह हैं जिन्हें केवल नामित किया जाना है

तुरंत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में पहचाने गए, पहचान

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में स्थापित। [ 431 एफ-एच; 432 ए-एफ; 433 ए-ई}

आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, [1964] 6 एस. सी. आर. 368; राजेंद्रन बनाम। राज्य

मद्रास, 1968] 1 एस. सी. आर. 721; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। पी. सागर, [1968] 3

एससीआर 595; त्रिलोकी नाथ बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, [1969) 1 एस. सी. आर. 103; ए.

पीरलाकरुप्पन बनाम। तमिलनाडु राज्य, [1971] 1 एस. सी. सी. 38; आंध्र प्रदेश राज्य

देश वी। बलराम ए. आई. आर 1972 एस. सी. 1375; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन

[ 1975 ] 2 एससीआर 761; के. एस. जयश्री बनाम केरल राज्य [1976] 3 एस. सी. सी. 730; राज्य केरल बनाम

. एन. एम. थॉमस [1976] आई. एस. सी. आर. 906; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वी. भारत संघ और अन्य। [ 1981 ] 1 एस. सी. आर. 185 संदर्भित, 366

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

( छ) यह सच है कि उन जाति या सामाजिक समूहों के कुछ सदस्यों ने काफी प्रगति की होगी और आगे बढ़े होंगे ताकि अग्रणी के साथ अनुकूल तुलना की जा सके।

आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगतिशील वर्ग। ऐसे मामलों में, प्रति वर्ग और उच्च आय सीमा आरक्षण का लाभ उस वर्ग के ऐसे सदस्यों को सुनिश्चित करेगी जो वास्तव में इसके हकदार हैं; (ज) अगड़े वर्गों के गरीब वर्गों के मामलों में, राज्य को उनकी सहायता करने के साधनों की खोज करनी होगी- और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत आरक्षण के अलावा अन्य साधनों की खोज करे। [ 433 जी-एच)14. अंतिम विश्लेषण में, आर्थिक समानता की प्राप्ति ही संकटग्रस्त समस्याओं का अंतिम और एकमात्र समाधान है। एक खतरा भी है

पीठ के सदस्य की पहचान करने के लिए मानदंड के रूप में व्यक्तिगत कहावत को अपनाना

वार्ड कक्षाएँ। वास्तव में निम्न वर्ग जिन्हें साबित करने के लिए प्रमाण पत्र की सबसे अधिक आवश्यकता होती हैउनकी गरीबी के लिए अधिकारी या अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा।

विधायक या कोई नामित व्यक्ति। [ 434 बी-सी)

15. इसलिए वर्ग गरीबी, व्यक्तिगत गरीबी नहीं, प्राथमिक परीक्षा है। अन्य सहायक परीक्षण जीवन शैली, जीवन स्तर, सामाजिक पदानुक्रम में स्थान, आदतें और रीति-रिवाज आदि हैं। व्यक्तिगत अपवादों के बावजूद, सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करना संभव और आसान हो सकता है

जाति, निवास के संदर्भ में, व्यवसाय या किसी अन्य प्रमुख विशेषता के संदर्भ में। जाति और उप-क्षेत्रवाद के प्रति हमारी घृणा के बावजूद, ये जीवन के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि वे गरीबी को दर्शाते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का प्राथमिक स्रोत है, तो उन्हें अन्य कम प्राथमिक स्रोतों के साथ फिर से पहचाना जाना चाहिए। चाहे आप इसे एक जाति समूह, एक उप-क्षेत्रीय समूह, एक व्यावसायिक समूह या किसी अन्य वर्ग के रूप में देखें, गरीबी को पहचानने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। एक बार जब प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए यह विचार करने का प्रश्न है कि रेखा कैसे और कहाँ खींची जाए क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ क्षेत्र-दर-क्षेत्र भिन्न होती हैं। एक बार जब प्रासंगिक शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और लोगों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाता है, तो इस मामले में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा टिक नहीं पाएगी

बहिष्कृत। [ 334 डी-जी]

प्रति ए. पी. सेन, जे.

1. अवधारणात्मक रूप से, अनुच्छेद के तहत नागरिकों के पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना। 15 ( 4 ) और अनुच्छेद द्वारा परिकल्पित नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की प्रणाली। 16 ( 4 ) जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है, हमारे देश में सदियों पुरानी सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई आरक्षण की नीति जाति-उन्मुख है, जबकि नीति आर्थिक मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। फिर कला के तहत इस तरह के विशेष प्रावधान या आरक्षण बनाने में जाति का तत्व। 15 ( 4 ) और 16 (4) कर सकते हैं

हटा दिया जाए। [ 435 बी-डी]

2. यह सच है कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन से संतुष्टि नहीं होगी।

अनुच्छेद 15 (4) के तहत शेष शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े लोग, और केवल 367 हैं।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका

अपनाए जाने वाले कई परीक्षणों में से एक। अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष प्रावधान करने या अनुच्छेद के तहत पदों और नियुक्तियों के आरक्षण के लिए प्रमुख और एकमात्र कारक। 16 ( 4 ) गरीबी होनी चाहिए, और जाति या उप-जाति या समूह का उपयोग केवल व्यक्तियों की पहचान के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए दृष्टान्त, जब तक कि पिछड़े वर्ग के ऐसे सदस्य ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते हैं और उनके बीच गरीबी का उन्मूलन नहीं हो जाता है और वे हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नई सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदार बन जाते हैं। [ 435 एच; 436 सी-डी}

3. पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा।

सेवाओं में जनसंख्या में उस वर्ग के प्रतिशत और समग्र रूप से सेवा की कुल संख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। प्रतिनिधित्व का ठीक उसी प्रतिशत के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है।

जनसंख्या में वर्ग; यह बस पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा, के मामले में

सेवा में उस वर्ग के सदस्यों की संख्या का हिसाब रखें, क्या वे हैंआरक्षित या अनारक्षित पद धारण करना। [ 436 ई-एफ]

4. राज्य को दोहरे समझौते को उचित महत्व और प्रभाव देना चाहिए

दक्षता और अवसर की समानता बनाए रखने के लिए संवैधानिक आदेश सभी व्यक्तियों के लिए एकता। आरक्षण की प्रकृति और विस्तार तर्कसंगत होना चाहिए।

और तर्कसंगत। नागरिकों के किसी भी वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति एक तथ्य है

ऐसी स्थिति जिसके लिए तथ्य खोजने वाले निकाय द्वारा जांच और निर्धारण की आवश्यकता होती है

जिसके पास प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए विशेषज्ञता और तंत्र है। द.संविधान ने पीठ के लिए इस तरह के आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया है

कला के तहत राष्ट्रपति द्वारा वार्ड वर्ग। 340 सिफारिशें करना और

यदि राज्यों को ऐसी प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए छोड़ दिया जाता है

पिछड़े वर्ग। यह हो सकता है, और अक्सर, न्यायालय के लिए आकर्षित करना मुश्किल है

पहले से रेखा जिसे राज्य को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कभी भी मुश्किल नहीं है

न्यायालय को यह जानने के लिए कि सीमा पार आक्रमण, चाहे कितना भी गलत परिभाषित क्यों न हो,

हुआ है। न्यायालयों के पास न तो विशेषज्ञता है और न ही समाजशास्त्रीय ज्ञान हैसामाजिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या हैं, यह निर्धारित करने के लिए मानदंडों को परिभाषित या निर्धारित करना।

कला के अर्थ में नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। 15 ( 4 )

जो राज्य को प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है

कला के आदेश के बावजूद ऐसे वर्ग। 15 ( 2 ) कि राज्य नहीं करेगा

किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव करना,

वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से कोई भी। सुप्रीम कोर्ट बीमार है

यह निर्धारित करने के कार्य को करने के लिए सुसज्जित है कि क्या नागरिकों का एक वर्ग है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, लेकिन, हालांकि व्याख्या करने का कर्तव्य

संविधान और यह देखने के लिए कि इसका क्या अर्थ और इरादा है जब यह प्रावधान करता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति। विचार में

इस स्थिति में अदालतों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह संविधान है

वे व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा, न्यायालय का बहुत कम या कोई कार्य नहीं है।

[ 436 जी-एच; 437 ए-डी]

5. हमारे संविधान की प्रस्तावना सुरक्षा के लिए राष्ट्र के संकल्प को दर्शाती है

अपने सभी नागरिकों के लिए: न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राज्य का उद्देश्य

सामाजिक न्याय लाने और बनाए रखने के लिए उचित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए सभी के हितों का ध्यान रखना। द्वारा तर्कहीन और अनुचित कदम

राज्य धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाज के ताने-बाने को तोड़ देगा। यह मुख्य रूप से 368 है

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

लिए गए निर्णयों में संयम लाने का राज्य का कर्तव्य और कार्य

कला के तहत। 15 ( 4 ) और 16 (4), क्योंकि न्याय मनुष्यों के दिलों में रहता है और अन्याय और विपरीत भेदभाव की बढ़ती भावना, मूर्खतापूर्ण राज्य द्वारा प्रेरित है।

कार्रवाई, सामाजिक न्याय को नष्ट कर देगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। यदि राज्य कला के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करता है। 16 ( 1 ) एआरडी कला। 335 , सर्वोच्च न्यायालय का होगा बेशक, अपना कर्तव्य निभाना होगा। [ 437 एफ-जी]

6. कला के तहत आरक्षण की सीमा। 15 ( 4 ) और कला। 16 ( 4 ) अनिवार्य रूप से राज्य से राज्य और राज्य के भीतर क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होना चाहिए,

किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की प्रचलित स्थितियों के आधार पर। चूंकि आरक्षण से संबंधित समस्याएं कभी नहीं हो सकतीं।न्यायालयों में मुकदमेबाजी के माध्यम से हल, केंद्र सरकार चाहिए

एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की व्यवहार्यता पर विचार करें पिछड़े वर्ग जिन्हें लगातार समाजशास्त्रीय और आर्थिक कार्य करते रहना चाहिए

एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक राज्य के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अध्ययन। द.

कला को लागू करके संविधान के निर्माता। 340 पिछड़े वर्गों के लिए इस तरह के एक उच्च शक्ति वाले राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई

केंद्र। [ 437 एच; 438 ए-बी]

7. रक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत कला में सन्निहित है। 15 ( 4 ) और 16 (4) और अनुच्छेद का अधिदेश। 29 ( 2 ) इसे एक पक्षीय सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राज्य अपने लोगों की सेवा करने के लिए अस्तित्व में है। कुछ सेवाएँ हैं

जहाँ विशेषज्ञता और कौशल महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा सेवाएँ सीधे जनता के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं और उनसे निपटती हैं। पायलटों और विमानन इंजीनियरों के लिए ज्ञान और अनुभव से उत्पन्न पेशेवर विशेषज्ञता, उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान और परिचालन कौशल की आवश्यकता होती है। नागरिकों का जीवन ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मानसिक गतिविधि को नियंत्रित करने के अन्य समान क्षेत्र हैं जहाँ पेशेवर, तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। संघ या राज्यों के तहत ऐसी सेवाओं या पदों में, पदों के आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है; नियुक्तियों के लिए केवल योग्यता ही एकमात्र और निर्णायक विचार होना चाहिए। [ 438 सी-ई]

पर वेंकटरमैया, जे।

1. अवसर की समानता दो प्रमुख सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती है

( (i) अवसर की समानता का पारंपरिक मूल्य; और (ii) परिणामों की समानता का नया विचार, जिसकी नई कल्पना नहीं की गई है। जो समाज समानता के आदर्श को संजोता है, उसे समानता के समूह के अर्थ

और सहमति को परिभाषित करना होगा और एक समतावादी समाज लाने के लिए उसके लिए विकल्प हमेशा राजनीतिक होंगे। लेकिन अदालतों को विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि जिस समाज के लिए उन्हें जवाब देना है, वह मांगों का प्रसार जारी कर रहा है। अतीत में कई असमानताएँ प्रकृति के क्रम का हिस्सा प्रतीत होती हैं। हालाँकि, न्यायालय उन समस्याओं से निपटते हैं जो समाज प्रस्तुत करता है। विशेष ऐतिहासिक कारणों से अलग-अलग समय पर जागरूकता के स्तर और ग्रिक वेंस की संबंधित इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं जो अक्सर एकजुट होने के बजाय समानता की श्रेणियों के बीच अंतर करने की प्रवृत्ति रखती हैं।

उन्हें। वर्ग, नस्ल, धर्म और लिंग की असमानताओं ने खुद को विभिन्न अवधियों में प्राथमिक शिकायतों के रूप में प्रस्तुत किया है। अदालतों को खुद को याद दिलाना चाहिए कि जो लोग अपरिहार्य अधिकारों से वंचित हैं, उनके लिए क्रमिक शिक्षा कभी भी पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है। हमारा एक 'दर्जे के लिए संघर्ष' है, एक संघर्ष के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक

369

लोकतंत्र को चर्मपत्र से उतारने और उसे जीवन देने के लिए। ' सामाजिक अन्याय हमेशा अपनी पुस्तकों को लाल स्याही से संतुलित करता है। न तो व्यक्तिगत रुचि की सनक और न ही निहित स्वार्थों की सुरक्षा किसी भी उचित रूप से योग्य व्यक्ति के अवसरों को सीमित करने के कारणों के रूप में खड़ी हो सकती है। ये ऐसे विचार हैं जो कभी-कभी विरोधाभासी हो सकते हैं जिन्हें समानता के सिद्धांत से उत्पन्न मामलों से निपटने के दौरान अदालतों के साथ तोलना चाहिए। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि अदालतें अपने आप में समानता की अवधारणा को सार्थक कार्रवाई में लाने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार के लोगों और विधायकों की इच्छा से उनका समर्थन किया जाना चाहिए। ये मानव समाज के सभी वर्गों की ओर से एकजुट कार्रवाई का उदय होना चाहिए। यही सब कुछ नहीं है। मौजूदा आर्थिक स्तर के तहत समानता लाने की केवल इच्छाशक्ति स्थिति को और खराब कर सकती है। साथ ही राष्ट्रीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समानता का संचालन कम बोझिल हो और समाज के प्रत्येक सदस्य को उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ले जाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति उस न्यूनतम स्तर से नीचे न रह जाए जो समाज के प्रत्येक सदस्य की सभी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करता है। यदि कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं होती है तो अदालतों द्वारा की गई घोषणाएं खोखले शब्द बन जाएंगी क्योंकि संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय में दिए गए कई उच्च सिद्धांत कई कारकों के कारण निकले हैं। [ 440 बी-एच; 441 ए)

2. पर्यावरण के कारण सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता है।

संबंधित व्यक्तियों के कारक और जीवन की स्थिति। व्यक्तिगत योग्यता के सिद्धांत का अनुप्रयोग, अन्य विचारों से अप्रभावित, अक्सर अमानवीय परिणामों का कारण बन सकता है [441 जी]

3. भारतीय पृष्ठभूमि के प्रश्न की जांच

सामाजिक स्थितियाँ-जाति-ग्रस्त वातावरण से पता चलता है कि संविधान में उपयोग की जाने वाली "पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति केवल उन लोगों को संदर्भित करती है जो विशेष जातियों में थे, या जो विशेष जातियों या जनजातियों या धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित थे जो पिछड़े थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक जाति विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, कभी-कभी यह एक वर्ग, एक नस्ल या एक जातीय इकाई हो सकती है और किसी व्यक्ति की जाति परिवार में उसके जन्म से नियंत्रित होती है। [ 459 ई; 457 एफ]

यह महत्वपूर्ण है कि भाग XVI में "पिछड़े वर्ग" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

संविधान और विशेष रूप से अनुच्छेद 338 (3) का उपयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियन समुदाय के साथ किया जाता है। इसलिए, "पिछड़े वर्गों" का अर्थ इससे पहले के अन्य शब्दों के साथ निकाला जाना चाहिए। [ 462 जी]

यह वैधानिक निर्माण का एक नियम है कि जहां सामान्य शब्द हैं

विशेष और विशिष्ट शब्दों के बाद, सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक सीमित होना चाहिए जो निर्दिष्ट हैं। यह सच है कि इस नियम को, जिसे इजस्डेम जेनेराइज़ रूल या रूल नोसिटर ए सोसाइटिस कहा जाता है, बहुत दूर नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन उस नियम को लागू करना उचित है जहां विशिष्ट शब्द एक अलग वंश या श्रेणी को संदर्भित करते हैं। [ 462 एच; 463 ए]

संविधान का भाग XVI कुछ रियायतों से संबंधित है जो

कुछ जातियाँ, जनजातियाँ और जातियाँ जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ हैं जनजातियों और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए। इस संदर्भ में यदि अनुच्छेद 338 (3) और (1985) एसयूपीपीएल।

एस सी आर।

370

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 340 का अर्थ लगाया गया है, 'पिछड़े वर्ग' अभिव्यक्ति का केवल उल्लेख किया जा सकता है शेदू के अलावा कुछ जातियाँ, नस्ल, जनजातियाँ या समुदाय या उसके कुछ हिस्से

नेतृत्व वाली जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और एंग्लो-इंडियन समुदाय, जो हैं

पीछे की ओर। के उद्देश्यों और उद्देश्यों के संबंध में संकल्प का खंड (6)

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को संविधान पेश किया गया और

संविधान द्वारा संविधान के भाग XVI के अधिनियमन का इतिहास

विधानसभा इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पिछड़े वर्ग केवल वही जातियाँ हैं,

जातियाँ, जनजातियाँ या समुदाय, जो जन्म से पहचाने जाते हैं, जो पिछड़े हैं। इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो

केवल गरीबी के कारण पिछड़े जो आर्थिक कारणों से पता लगाया जा सकता है अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्ग के रूप में भी माना जा सकता है और

संविधान का भाग XVI। [ 463 सी-डी; 466 जी-एच]

"नागरिकों का वर्ग" अभिव्यक्ति को अर्हता प्राप्त करके मसौदा समिति

विभिन्न दृष्टिकोण और एक व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो था सभी के लिए स्वीकार्य, तीन दृष्टिकोण हैं (i) कि होना चाहिए

सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता और प्रत्येक व्यक्ति एक के लिए योग्य है विशेष पद परीक्षा में बैठने के लिए उस पद के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और

उसकी योग्यताओं का परीक्षण कराना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह इसके लिए योग्य था या नहीं। पोस्ट करें या न करें और कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं होनी चाहिए

अवसर की समानता के सिद्धांत के संचालन में बाधा; (ii)

कि यदि अवसर की समानता का सिद्धांत लागू होना था तो वहाँ होना चाहिए

किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए

यदि नागरिक योग्य हैं तो उन्हें समानता के समान आधार पर रखा जाना चाहिए

जहाँ तक लोक सेवाओं का संबंध है; और (iii) यद्यपि

अवसर की समानता सैद्धांतिक रूप से अच्छी थी, साथ ही साथ होनी चाहिए

कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए किया गया प्रावधान जो अब तक

प्रशासन के बाहर। संविधान में चर्चा का पूरा सार

विधानसभा ने अल्पसंख्यक आबादी के लिए आरक्षण देने की ओर इशारा किया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित जो सामाजिक रूप से

पीछे की ओर। [ 465 जी-एच; 466 ए-बी]

4. बालाजी के मामले में और चित्रलेखा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के उद्देश्य। का संयोजनसंविधान के अनुच्छेद 15 में 'पिछड़े वर्ग' और 'अनुसूचित जाति' की अभिव्यक्ति

संविधान, उपरोक्त दो निर्णयों के अनुसार, एक उचित

यह अनुमान लगाते हुए कि 'वर्ग' अभिव्यक्ति 'जाति' का पर्याय नहीं थी। अदालत ने

इन टिप्पणियों को करते हुए बुराइयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया

जाति व्यवस्था जो सी. आर. से संबंधित लोगों के पिछड़ेपन का कारण बनी थी

भाग XVI के अधिनियमन से पहले की जातियों और बहसों को कम करना और

संविधान का अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)। वास्तव में क्या खत्म हो गया था

भारतीय सामाजिक संस्थानों का इतिहास देखा गया। के निर्माताओं भारतीय संविधान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कई जातियाँ थीं

जिनके सदस्यों की शर्तें लगभग मेम की शर्तों के समान थीं

उनकी प्रगति के रास्ते में कठिनाइयाँ जो प्रोवर्ट के कारण इतनी अधिक नहीं थीं लेकिन एक विशेष जाति में उनके जन्म के कारण। भाग XVI को 371 के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका

गरीब वर्गों की स्थितियों को कम करने का उद्देश्य जिसका ध्यान संविधान के भाग IV के प्रावधान द्वारा रखा गया था और विशेष रूप से

अनुच्छेद 46 और संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) द्वारा जो विशेष उद्देश्यों के लिए आर्थिक आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण की अनुमति देता है।

सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार, हालांकि बाद में संशोधित किए गए।

निर्णय लेते हैं। [ 466- डी-एच; 467 ए-बी]

नाबालिग पी. राजेंद्रन बनाम। मद्रास राज्य और अन्य। [ 1968 ] 2 एससीआर 786; राज्य

आंध्र प्रदेश और अन्र. वी. पी. सागर [1968] 3 एससीआर 595; त्रिलोकी नाथ और अन्र। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। [ 19691 1 एससीआर 103; ए. पीरियाकरुप्पन आदि। तमिलनाडु राज्य और अन्य। [ 1971 ] 2 एस. सी. आर. 430; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. यू. एस. वी. बलराम आदि [1972] 3 एस. सी. आर. 247 संदर्भित।

5. यदि यह विचार कि जाति या समुदाय एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक है

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने में, कई विकृतियों के होने की संभावना है और वे एकमात्र उद्देश्य से दूर हो सकते हैं जिसके लिए ये

संवैधानिक प्रावधान लागू किए गए। शारीरिक अक्षमता, गरीबी, निवास स्थान, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से संबंधित होने का तथ्य, सशस्त्र बलों के किसी सदस्य के परिवार से संबंधित होने का तथ्य जैसे कई कारक अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य के लिए एकमात्र कारक बन सकते हैं।

जिनका ऐसे मामलों में राहत देने के उद्देश्य से राज्य द्वारा सहारा लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जबकि ऐसे मामलों में राहत दी जा सकती है

अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) वर्गीकरण के तर्कसंगत सिद्धांत को अपनाते हुए,

उन पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16′4 लागू नहीं किया जा सकता है। लेख

15 ( 4 ) और अनुच्छेद 16 (4) उन लोगों के लाभ के लिए है जो संबंधित हैं

जातियाँ/समुदाय जो 'पारंपरिक रूप से नापसंद हैं और जिन्होंने अतीत में सामाजिक भेदभाव को कम किया है'। ऊपर वर्णित अन्य कारक थे -

अधिनियमित करते समय संविधान निर्माताओं की अवमानना में कभी नहीं

इन खंडों। [ 472 ए-डी]

डी. एन. चंचला बनाम मैसूर राज्य और अन्य। आदि। [1971] पूरक। एससीआर 608;

जयश्री और अन्र। वी. केरल राज्य और अन्र। [ 1977 ] 1 एस. सी. आर. 194; उत्तर राज्यप्रदेश बनाम. प्रदीप तानियन और ओ 1 एस। [ 1975 ] 2 एस. सी. आर. 761; सुभाष चंद्र बनाम। द.

यू. पी. और अन्य का राज्य। ए. आई. आर. 1973 ऑल। 295 ; दिलीप कुमार बनाम। यूपी की सरकार।

& ओआरएस। ए. आई. आर. 1973 ऑल। 592 संदर्भित किया गया।

6. संविधान के अनुच्छेद 14 के दो भाग हैं। यह राज्य से पूछता है

किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करना। यह राज्य से यह भी कहता है कि

कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करना। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है -

कानून में कोई भी भेदभाव। समान सुरक्षा की अवधारणा के लिए राज्य की आवश्यकता थी

विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों के लिए अंतर उपचार को पूरा करने के लिए ताकि

सबके बीच एक संतुलन स्थापित करें। यह उस नियम का आधार है जो बराबर है

समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए यदि

समानता का सिद्धांत जो हमारे संविधान की आधारशिलाओं में से एक है

प्रतिपूरक या सुरक्षात्मक भेदभाव का सहारा लें। अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4)संविधान के प्रावधानों को बाध्यकारी या सुरक्षात्मक उपायों के रूप में अधिनियमित किया गया था 372

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एससीके।

सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के व्यक्तियों को राहत देने के लिए भेदभाव

शैक्षणिक संस्थान में और ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं में पदों काकेवल। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों से संबंधित नहीं हैं

और अल्पसंख्यक लेकिन जो अन्यथा गरीबी के कारण कमजोर वर्गों से संबंधित हैं,

निवास का स्थान, समान अवसर की कमी आदि सवाल उठते हैं कि क्याइस तरह का आरक्षण उनके पक्ष में किसी अन्य प्रावधान के तहत किया जा सकता है।

संविधान जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (1), अनुच्छेद 16 (1) या अनुच्छेद 46।

थॉमस के मामले के अनुसार, (क) पदों का कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों सहित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाएं और

अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16,1 के तहत अनुसूचित जनजातियाँ, और (बी) तरजीही व्यवहार

जैसा कि इस मामले में वर्गीकरण के आधार पर किया गया था, सामान्य रूप से हो सकता है

अनुच्छेद 16 (1) के तहत केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं कर सकते थेसमान लाभ दिया और उनकी एकमात्र आशा अनुच्छेद 16 (4) थी

संविधान। [ 477 ए-ई; 485 जी-एच]

7. आरक्षण देने की सरकार की शक्ति के बारे में

संविधान का अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4): प्रश्न का निर्धारण

चाहे वे सदस्य किसी जाति या समूह या समुदाय से संबंधित हों

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य के लिए पिछड़े

सरकार किसी भी जाति या समूह या समुदाय को इस रूप में बुलाने के लिए तैयार नहीं है

अपनी मीठी इच्छा और आनंद के अनुसार पीछे हटें और लाभ का विस्तार करें कि

उन प्रावधानों के तहत ऐसी जाति या समूह या समुदाय को अनुदान दिया जा सकता है।

इस संबंध में सरकार द्वारा अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग करने से

राजनीतिक पक्षपात के कारण वर्गों की न्यायसंगत आवश्यकताओं को अस्वीकार किया जाता है

जो वास्तव में पिछड़े हैं। किसी भी जाति को वर्गीकृत करने की सरकार की शक्ति

या पिछड़े के रूप में समूह या समुदाय का उपयोग इसके अनुसार किया जाना चाहिए

दिशानिर्देश जो संविधान से आसानी से एकत्र किए जा सकते हैं। यह अब है

स्वीकार किया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अभिव्यक्तियाँ अनुच्छेद 15 (4) में नागरिक और 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति'

संविधान के कुल मिलाकर 'नागरिकों के पिछड़े वर्गों' के बराबर हैं।

अनुच्छेद 16 (4)। [ 486 ए-डी]

इसके अलावा पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए मानदंड आधारित नहीं होना चाहिए

केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान और पिछड़ेपन पर

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के समान होना चाहिए जिससे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नुकसान उठाना पड़ा। यह दृश्य कॉम में है

संकल्प के खंड 6 में अंतर्निहित इरादे के साथ औपचारिकतादिसंबर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान के उद्देश्य और उद्देश्य

13 , 1946 जिसने संविधान सभा को एक संविधान समर्थक बनाने के लिए कहा

अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करना और

दबावग्रस्त और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुच्छेद 338 के प्रावधानों की भी कामना करते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 340। जब तक उपरोक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है

सरकार, सरकार के लिए किसी को भी बुलाना संभव हो जाएगा

राज्य पिछड़े के रूप में भले ही वास्तव में यह एक उन्नत जाति या हो सकता है समूह या समुदाय लेकिन किसी अन्य अग्रगामी समुदाय के ठीक नीचे।

[ 486 एच; 487 सी-डी] 373

के. सी. वी. कुमार 1. कर्नाटक

ऐसी उन्नत जातियों या समूहों का एक और महत्वपूर्ण कारण है

या समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और वह यह है कि यदि जातियों या समूहों और समुदायों, जो काफी उन्नत हैं और जातियों और समूहों और समुदायों, जो वास्तव में निचले स्तर पर पिछड़े हैं, को एक साथ पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से अधिक उन्नत वर्गों द्वारा खाया जाएगा और वास्तव में योग्य वर्ग व्यावहारिक रूप से बिना किसी लाभ के चले जाएंगे क्योंकि उनमें से अधिक उन्नत जातियों या समूह या समुदायों के बच्चों की अधिक संख्या में पिछड़े वर्गों के बच्चों की तुलना में अधिक अंक होंगे।

पिछड़ी जातियाँ या समूह या समुदाय। इसमें आरक्षण का पूरा उद्देश्य भी निराश हो जाएगा। [ 487 डी-एफ]

इसलिए जहां तक संभव हो पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करते समय,

राज्य सरकार को उपरोक्त सिद्धांत को एक मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखना होगा। उपरोक्त सिद्धांत को अपनाने से उन व्यक्तियों की संख्या में अनुचित रूप से कमी नहीं आएगी जो संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्तर भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उनके संबंध में किए गए कई उपचारात्मक उपायों के कारण बढ़ रहा है। साथ ही, यह वास्तव में पिछड़ी जातियों, समूहों और समुदायों को कई उन्नत समूहों के गला घोंटने से भी मुक्त करेगा, जिन्हें लगभग तीन दशकों से वास्तव में पिछड़े वर्गों के साथ आरक्षण का लाभ मिला है। यह समय है कि अधिक ध्यान दिया जाए

वे जातियाँ, समूह और समुदाय जो सबसे निचले स्तर पर रहे हैं, सभी नुकसान और अक्षमताओं से पीड़ित हैं (शायद अस्पृश्यता को छोड़कर)

जिसे कई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने अपनाया है। उजागर लेकिन समान या समान लाभों के बिना जो होने से प्रवाहित होते हैं

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल।

[ 487 एच; 488 ए-बी]

जानकी प्रसाद परिमू और अन्य। आदि, आदि। जम्मू और कश्मीर राज्य और

ओआरएस। [ 1973 ] 3 एस. सी. आर. 236 संदर्भित है।

8. चूँकि आर्थिक स्थिति भी एक प्रासंगिक मानदंड है, इसलिए यह होगा

निर्धारित करने में परीक्षणों में से एक के रूप में 'साधन परीक्षण' को शामिल करने के लिए उपयुक्त

पिछड़ेपन जैसा कि केरल सरकार ने किया था। ये दो परीक्षण

अर्थात् जाति या समूह या समुदाय की शर्तें अधिक या अधिक होनी चाहिए।

उन शर्तों के समान कम जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित

जनजातियाँ स्थित हैं और उस परिवार की आय जिसके लिए उम्मीदवार

संबंधित निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है जो उपयोगी मानदंड के रूप में काम करेगा

अनुच्छेद 15 (4) के तहत किए जाने वाले किसी भी आरक्षण के लाभार्थियों का निर्धारण करना। तथापि, अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजन के लिए यह भी दिखाया जाना चाहिए कि -

विचाराधीन पिछड़ा वर्ग सरकार की राय में पर्याप्त रूप से नहीं है

सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। [ 488 सी-ई]

9. 'विशेष समूह' के रूप में शैलीबद्ध वर्गीकरण जो इस पर आधारित है

व्यवसाय-सह-आय पर विचार और जिसे अनुमोदन प्राप्त हो गया है

चित्रलेखा के मामले में; एक और वैध और उपयोगी परीक्षण है जिसे अपनाया जा सकता है।

आरक्षण के उद्देश्य के लिए जिसका अधिक वैध रूप से कला से पता लगाया जा सकता है। 14

कला के लिए नहीं। 15 ( 4 ) और कला। 16 ( 4 ) .

[ 491 एच] [1985] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

10. में सभी सात विचारों के सावधानीपूर्वक विचार से

थॉमस के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित दृष्टिकोण

कि अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण इससे अधिक नहीं हो सकता है

50 प्रतिशत पीठ के बहुमत से अस्थिर हो गया है जिसने यह निर्णय लिया मामला। [ 491 बी]

11. यदि आरक्षण केवल उन पिछड़ी जातियों के पक्ष में किया जाता है या

खंड जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से तुलनीय हैं,

यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है (अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत सहित)।

जाति और अनुसूचित जनजाति और 15 प्रतिशत 'विशेष समूह' के लिए आरक्षित)

कर्नाटक राज्य में ऐसे पिछड़े वर्गों की कुल जनसंख्या का दृश्य। हवानूर आयोग ने एस. एस. एल. सी. में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ली है।

पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में वर्ष 1972 में परीक्षा।

राज्य की कुल जनसंख्या का प्रति हजार औसत पास

1972 में कर्नाटक की संख्या 1.69 थी। अनुसूचित जातियों के मामले में औसतयह संख्या 0.56 थी और अनुसूचित जनजातियों के मामले में 0.51 थी। भले ही हम सब कुछ ले लें

पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर। नतीजतन, आरक्षण की आवश्यकता है जो अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत कुल आरक्षण को 50 से आगे ले जाएगा।

सीटों/पदों की कुल संख्या का प्रतिशत अस्तित्व में नहीं रहेगा। वर्तमान में

विभिन्न जातियों के पिछड़ेपन के सवाल को फिर से निर्धारित करने के लिए आवश्यक,अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए जनजातियाँ और समुदाय

विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर एकत्र किए जाने वाले नवीनतम आंकड़ों का प्रकाश और

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा को संशोधित करें। 15 प्रतिशत का आरक्षण अब अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत बनाया गया है लेकिन जिसका पता लगाया जा सकता है

अनुच्छेद 14 और 16 (1) से लेकर व्यवसाय-सह-आय पर आधारित 'विशेष समूह' तककिसी भी स्थिति में सभी समुदायों और जातियों के सदस्यों द्वारा इसका लाभ उठाया जाए।

[ 491 सी-जी]

12. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अगर एक नए संकल्प पर

कुछ जातियों या समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर जाना पड़ता हैअनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के लिए तैयार, सरकार अभी भी आगे बढ़ा सकती है

जनसंख्या के कमजोर वर्गों के सुधार की नीति

संविधान। सभी जातियों और समुदायों में ऐसे गरीब लोग हैं जोपर्याप्त अवसर दिया जाता है और प्रशिक्षण सफलता का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है

उनके लिए छात्रवृत्ति का उदार अनुदान, मुफ्त छात्रावस्था, मुफ्त भोजन औररहने की सुविधा, मुफ्त वर्दी, मुफ्त मध्यान्ह भोजन आदि लोगों का जीवन बनाने के लिए।

गरीब छात्र सहज हैं। सरकार अतिरिक्त शिक्षण भी प्रदान कर सकती है। सुविधाएं, लेखन सामग्री और मुफ्त किताबें और पुस्तकालय की सुविधा। ये और अन्य

निचली कक्षाओं में कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जब तक कोई छात्र उपस्थित हो

योग्यता परीक्षा के लिए वह उच्च डिग्री प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है अपनी पढ़ाई में प्रवीणता। [ 491 एच; 492 ए-सी)

$

मौलिक न्यायनिर्णय: याचिका सं. लिखें। 1297-98 ,

1407 1979 का, 1980 का 4995-97 और 1981 का 402।

¤,सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चंद्रचूड़, सी. जे.)

375

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

;

एफ. एस. नरीमन, के. एन. भट, बी. वीरभद्रप्पा, एच. एस. रेणुका

प्रसाद, विजय कुमार वर्मा, नंजप्पा गणपति और पी. के. मनोहर

- डब्ल्यू. पी. सं. में याचिकाकर्ताओं के लिए। 1297-98 , 1979 से।

पेटी के लिए के. चेन्नाबसप्पा, एस. एस. जवाली और बी. आर. अग्रवाल

1979 के डब्ल्यू. पी. सं. 1407 में टियनर्स।

याचिकाकर्ताओं के लिए के. के. वेणुगोपाल और सी. एस. वैद्यनाथन

डब्ल्यू. पी. संख्या में। 4995-97 / 80 & 402 1981 से।

डब्ल्यू. पी. में उत्तरदाताओं के लिए आर. के. गर्ग और ए. वी. रंगम।

नं. 4995-97 / 80 और 1981 का 402।

हस्तक्षेपकर्ता अखिल के लिए पी. एच. पारेख और गौतम फिलिप

डब्ल्यू. पी. सं. में भारत अनुसुचित जाति। 1297-98 1979 से।

एल. जी. हेवनूर, के. एम. के. नायर और नारायण नेत्तर

हस्तक्षेप करने वाले राष्ट्रपति, कर्नाटक विधानमंडल, डब्ल्यू. पी. संख्या 1407 में

1979 .

हस्तक्षेप करने वाले द्रविड़ कड़गम के लिए के. राजेंद्र चौधरी

1981 के डब्ल्यू. पी. सं. 402 में।

हस्तक्षेपकर्ता अखिल भारतीय नायक संघ के लिए के. एम. के. नायर

1979 का डब्ल्यू. पी. सं. 1297-98 और 1407।

निम्नलिखित निर्णय दिए गए:

चंद्रचूड़, सी. जे. : मेरे विद्वान भाइयों ने आरक्षण की नीति पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो अफसोस की बात है कि आलंकारिक रूप से आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है। हमें वकील द्वारा इतना आमंत्रित नहीं किया गया था कि निर्णय देने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात व्यक्त करने के लिए।

आरक्षण के मुद्दे पर राय; जो कर्नाटक सरकार के साथ आयोग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकता है

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को बेहतर रोजगार और शैक्षिक अवसर प्रदान करने के प्रश्न की जांच करने के लिए। विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ के बिना अपने विचारों को व्यक्त करने में न्यायालय द्वारा कुछ असामान्य अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन, संस्थानों को सार्थक नवाचारों से लाभ होता है। तथ्य आयोग के समक्ष पेश किए जाएंगे और आयोग 376

आरक्षण के मामले में उपयुक्त परीक्षण विकसित करेंगे। मैं यह आशा व्यक्त करने से नहीं रोक सकता कि मेरे विद्वान भाइयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के निर्माण में जो गहरी सोच और ईमानदारी आई है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रस्तावित आयोग को अपनी महत्वपूर्ण राय को बारीकी से लागू करना चाहिए। मेरा केवल एक कंकाल प्रयास है। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने की संभावना बहुत कम है।

मैं अपनी राय निम्नलिखित प्रो के रूप में दूंगा।

पद:

1 . अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण जारी रहना चाहिए क्योंकि वर्तमान में, एक साधन परीक्षण के आवेदन के बिना, पंद्रह साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं है। संविधान के आने के पचास साल बाद और पंद्रह साल होंगे, जो कि उत्पीड़ित वर्गों के लिए सामाजिक उत्पीड़न, अलगाव और उत्पीड़न के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए काफी लंबा समय होगा।

अपमान।

2 . साधन परीक्षण, अर्थात, आर्थिक पिछड़ेपन की परीक्षा को उपरोक्त (1) में उल्लिखित अवधि के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि

अनिश्चित काल के लिए लाभ। जहाँ तक अन्य पिछड़े वर्गों की बात है, वे एकजुट हैं

3 .

इसलिए, रोजगार और शिक्षा में आरक्षण के उद्देश्य से उनकी पहचान करने के लिए दो परीक्षणों को संयुक्त रूप से लागू किया जाना चाहिए: एक, कि उन्हें अपने पिछड़ेपन के मामले में अनुसूचित जातियों और शेदु के नेतृत्व वाली जनजातियों के साथ तुलनीय होना चाहिए; और दो, कि उन्हें साधन परीक्षण को पूरा करना चाहिए जैसे कि राज्य सरकार के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है

प्रचलित आर्थिक स्थितियाँ।

4. रोजगार, शिक्षा और विधायी संस्थानों में आरक्षण की नीति की हर पांच साल में समीक्षा की जानी चाहिए। यह तुरंत एक विपरीत 377 का जोखिम उठाएगा।

के. सी. वी. कुमार, कर्नाटक (देसाई, जे.)

टच्युनिटी (i) स्टे के लिए, उत्पन्न होने वाली विकृतियों को ठीक करने के लिए आरक्षण नीति के विशेष पहलुओं और (ii)

पिछड़े और गैर-पिछड़े दोनों लोगों के लिए,

अभ्यास पर सार्वजनिक बहस में अपने विचार व्यक्त करें।

आरक्षण की राजनीति का प्रभाव।

देसत, जे। 'भारत ने गुणवत्ता को एक प्रमुख मूल्य के रूप में अपनाया

विस्तृत, अस्पष्ट और स्पष्ट रूप से कथित असमानता की पृष्ठभूमि बंधन '। ( 1) 'कला। 14 समानता की गारंटी लेकिन समाज में गहरी जड़ों वाली असमानता की जागरूकता कला में परिलक्षित होती है। 15 और 16. संविधान के काम करने के पंद्रह महीनों के बाद कला के विस्तार की आवश्यकता पड़ी। 15 ( 3 ) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक की शैक्षिक, आर्थिक या सामाजिक उन्नति के लिए राज्य द्वारा किए गए किसी भी विशेष प्रावधान को भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ( ) सेक. 2 इसके लिए उप-कला को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। ( 4 ) कला की। 15 साढ़े तीन दशकों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए निरंतर खोज जारी है

नागरिकों के वर्गों ने नीति निर्माताओं, नीति की व्याख्या करने वालों की अवहेलना की है जैसा कि कानूनों या कार्यकारी/प्रशासनिक आदेशों में परिलक्षित होता है और विपरीत दिशा में एक उछाल जोड़ा है, अर्थात्, जो लोग सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर की ओर/(प्रतिलोम) जाने का प्रयास करते हैं, उन्होंने आंदोलन को विपरीत गियर में डाल दिया है ताकि नीचे की ओर (अनुलोम) जा सकें।

शैक्षिक रूप से पिछड़े। रियायतों और लाभ की जागरूकता के रूप में उनके गैर-अवई के कारण परिणामी हताशा के साथ बढ़ता है

समाज के विभिन्न वर्गों के बीच क्षमता टकराव विकसित होता है।

संविधान ने एक समतावादी समाज का वादा किया। भोर होने पर

स्वतंत्रता भारतीय समाज एक विभाजित समाज था

विशिष्ट और विविध जीवन शैलियों वाले समूह। यह एक जाति थी

जर्जर स्तरीकृत पदानुक्रमित समाज। हालांकि यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है, जाति की अवधारणा ने एक सुसंगत परिभाषा का उल्लंघन किया है

न्यायविद या समाजशास्त्री।

संविधान के कार्यकरण के प्रारंभिक चरणों में, यह

असहमति या संवाद के बिना स्वीकार किया गया था जो जाति को प्रस्तुत करता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए कार्य मानदंड

कला के उद्देश्य के लिए नागरिकों का वर्ग। 15 ( 4 ) .

यह एक यथार्थवादी मूल्यांकन पर आधारित था कि एक के रूप में जाति

सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत सहस्राब्दियों से बना हुआ है।

( 1 ) मार्क गैलांटर-प्रतिस्पर्धा समानताएँ 1980।

( 2 ) संविधान का उद्देश्य और कारण विवरण (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951।

?



शास्त्रीय हिंदू सामाजिक कानूनी सिद्धांत की तुलना में व्यवहार में अव्यवस्थित और असममित रूप से इसे चित्रित किया गया है। ( 1) कला की भाषा। 15 ( 4 ) 'वर्ग' को संदर्भित करता है न कि जाति को। तरजीही उपचार जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है

ए.

जिस वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ दिखाया जाना था, उसे भेदभावपूर्ण माना जाना था, न कि उस जाति के सदस्यों के लिए जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग को जाति के लेबल की अनदेखी करते हुए हम कैसे परिभाषित करते हैं। जैसा कि हम एक साफ स्लेट पर नहीं लिख रहे हैं, आइए हम इस धोखाधड़ी को आकार और रूप देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप पर ध्यान दें।

बी.

नागरिकों के एक वर्ग का पालन जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पिछड़े ताकि पसंदीदा उपचार या प्रतिपूरक के योग्य हो

भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई।

एस. सी.

इस विषय पर निर्णयों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण भ्रम और अस्वस्थता की वर्तमान स्थिति को प्रकट करेगा। यह समीक्षा आवश्यक है क्योंकि एक गंभीर संदेह अब न्यायविदों, सामाजिक तर्कविदों और प्रशासकों को परेशान कर रहा है कि क्या जाति का आधार होना चाहिए।

पिछड़ेपन को पहचानना।

डी.

न्यायपालिका की ओर से इस सवाल पर कुछ दुविधा रही है कि क्या जाति को मान्यता देने का आधार होना चाहिए।

पिछड़ेपन। इसलिए, एक पक्षी की आंख-के निर्णयों का दृष्टिकोण

न्यायालय को पहले एक प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचाया जा सकता है कि -

क्या न्यायपालिका ने जाति को एक आधार के रूप में मान्यता दी है

ई.

पिछड़ेपन की मान्यता,

मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती चंपकम दोराईराजन और अन्र। , ( 1) इस न्यायालय ने धर्म और जाति के आधार पर स्थापित सांप्रदायिक जी. ओ. में वर्गीकरण को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह संविधान के खिलाफ है और नागरिक को गारंटी दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह निर्णय निर्देश पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता के दिन था।

एफ.

राज्य नीति के सिद्धांत। न्यायालय ने उस कला को अभिनिर्धारित किया। : 46 नहीं कर सकते

कला के प्रावधानों को ओवरराइड करें। 29 ( 2 ) क्योंकि निर्देश। सिद्धांत

जी.

राज्य की नीति के अनुरूप होना चाहिए और सहायक के रूप में चलना चाहिए

1

मौलिक अधिकारों का अध्याय।

एम. आर. बालजी और अन्य में। वी. मैसूर राज्य (3) में यह देखा गया कि

हालाँकि हिंदुओं के संबंध में जाति एक प्रासंगिक कारक हो सकती है -

एच.

( 1 ) सी. ओ. हटन-भारत में जाति: इसकी प्रकृति, कार्य और उत्पत्ति 1961।

( 2 ) [ 1951 ] एस. सी. आर 525

( 3 ) [ 1963 ] सप. 1 एस. सी. आर 439



समूहों के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने पर विचार करें या

कक्षाएँ

नागरिकों के लिए, इसे एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं बनाया जा सकता है।

सामाजिक

पिछड़ेपन अंतिम विश्लेषण में बहुत हद तक गरीबी का परिणाम है। नागरिकों के वर्ग जो निंदनीय हैं

गरीब अपने आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं। की समस्या

यह निर्धारित करना कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं, निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है।

जटिल, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों का वर्गीकरण

कला के तहत केवल उनकी जातियों के आधार की अनुमति नहीं है। 15 ( 4 ) . द. अदालत जाति को एकमात्र मानदंड मानने के खतरे का अनुमान लगा सकती है

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए। महत्वपूर्ण बात।

निर्णय का प्रभाव स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करने में निहित है। जब उसने कठोर लेकिन निर्विवाद सत्य का उच्चारण किया कि आर्थिक

पिछड़ेपन के लिए एक अधिक विश्वसनीय पैमाना प्रदान करेगा

सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना क्योंकि अधिक बार शैक्षिक

'जाति' और 'वर्ग' के बीच स्पष्ट अंतर दिखाया। प्रयास यह है किसामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का पता लगाने के लिए एक नया आधार खोजना

जाति के स्थान पर नेस इस निर्णय में परिलक्षित हुआ। इसमें दूरदर्शिता

हमारी राय में प्रदर्शित पक्ष प्रशंसनीय है।

टी. देवदेसन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. ( 1) याचिकाकर्ता

में आरक्षित सीटों के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम को चुनौती दी

केंद्रीय सचिवालय सेवा को कला का उल्लंघन करने वाला माना जाता है। 14 और 16

संविधान से। याचिका को स्वीकार करते हुए बहुमत ने कहा

कि सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की समस्या

पिछड़े वर्ग को कला का आदेश दिया गया। 16 ( 4 ) संविधान नहीं है

इसे ध्यान में रखे बिना एक सामान्य नियम तैयार करके पर्याप्त साल दर साल प्रतिबिंब। कौन सी सटीक विधि होनी चाहिए

इस उद्देश्य के लिए अपनाया गया निर्णय सरकार को लेना है। न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा विकसित की जाने वाली कोई भी विधि

के दावों के बीच एक उचित संतुलन बनाना चाहिए

अन्य कर्मचारियों के पिछड़ेपन और दावे, जैसा कि उल्लेख किया गया है

बालाजी का मामला।

आर. चित्रलेखा और अन्र में। वी. मैसूर राज्य और अन्य। ( 2 ) द.

बहुमत ने मैसूर सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को वैध ठहराया।

इंजीनियरिंग और चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में, और यह देखा गया कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

: परिस्थितियाँ और व्यवसाय खराब नहीं हैं और कला को आहत नहीं करते हैं। 15 ( 4 ) .

( 1 ) [ 1964 ] 4 एस. सी. आर 680

( 2 ) [ 1964 ] 6 एस सी आर 368.

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट (1985) एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

नागरिकों के एक समूह की जाति एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है

उनके सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाना और हालांकि यह एक प्रासंगिक मुद्दा है

एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए कारक, यह नहीं हो सकता है

उस ओर से एकमात्र या प्रमुख परीक्षण। यदि दी गई स्थिति में जाति है

कला के अर्थ के भीतर एक वर्ग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। 15 ( 4 ) यह

यदि यह अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करता है तो वर्गीकरण को दूषित नहीं करता है। अदालत नेअभिनिर्धारित किया कि संविधान के विभिन्न प्रावधान जो मान्यता देते हैं

इसका अर्थ उस नीति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए न कि देने के लिएसमाज के प्रगतिशील वर्गों को झूठे रंग के तहत महत्व

जिस जाति से वे संबंधित हैं। किसी भी परिस्थिति में ए

' जाति 'हालांकि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जाति हो सकती है

उसे एक विशेष वर्ग में रखने में एक प्रासंगिक कारक होना।

त्रिलोकी नाथ और अन्र में। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। ( 1)

राजपत्रित पदों में से 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रो द्वारा भरा जाएगा

प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों के पक्ष में था। अदालत नेअभिनिर्धारित किया कि राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा

खंड के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए निर्णायक। अदालत ने तदनुसार, आगे प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने के लिए निर्देश दिए

विषय बनने के लिए। पहले दिए गए निर्देश के अनुसार सामग्री एकत्र करने के बाद

मामला अदालत के समक्ष रखा गया था और निर्णय की सूचना दी गई थी

त्रिलोकी नाथ और अन्र में। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। ( 2 ) अदालत ने कहा कि 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का उपयोग 'पिछड़ी जाति' या 'पिछड़े समुदाय' के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है। किसी पूरी जाति या समुदाय के सदस्य, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर, किसी भी समय पिछड़े हो सकते हैं। और उस कारण से पिछड़े वर्ग के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वह है

इसलिए नहीं कि वे किसी जाति या समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि इसलिए कि

वे एक वर्ग बनाते हैं। अपने सामान्य अर्थ में, 'वर्ग' अभिव्यक्ति का अर्थ कुछ समानताओं या सामान्य लक्षणों के कारण एक साथ समूहीकृत लोगों का एक समरूप वर्ग हो सकता है, और जो कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे स्थिति, पद, व्यवसाय, किसी इलाके में निवास, नस्ल, धर्म और इसी तरह से सक्षम हैं, लेकिन कला के उद्देश्य से। 16 ( 4 ) यह निर्धारित करने में कि क्या कोई वर्ग एक वर्ग बनाता है, पूरी तरह से जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर एक परीक्षा को अपनाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह सीधे तौर पर होगा।

संविधान का उल्लंघन करता है। पिछड़ेपन को निर्धारित करने के आधार के रूप में जाति को एक कठोर झटका लगा।

( 1 ) [ 1967 ] 2 एस. सी. आर 265

( 2 ) [ 1969 ] 1 एस. सी. आर 103

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (देसल, जे.)

381

ए. पीरियाकरुप्पन आदि में वी. तमिलनाडु की स्थिति (1) यह न्यायालय

विशेष रूप से बालाजी के मामले में पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद और चित्रलेखा के मामले में कहा गया कि इस तथ्य को कहने का कोई लाभ नहीं है कि इस देश में कई जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना जीवन की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना है। यह पता लगाना मुश्किल है कि क्या अदालत ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति को एकमात्र आधार के रूप में स्वीकार किया है।

आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में। वी. यू. एस. वी. बलराम आदि (2) पिछड़े वर्गों की एक सूची जिसे प्रथम दृष्टया चुनौती दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जाति के आधार पर तैयार किया गया था। अदालत ने बारीकी से जांच करने पर पाया कि जाति चिह्न केवल आयोग द्वारा विस्तृत रूप से निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों या व्यवसायों के बाद समूह का एक विवरण है। इस धारणा पर भी कि सूची विशेष रूप से जाति पर आधारित है, आयोग के समक्ष सामग्री और अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा दिए गए कारणों से यह स्पष्ट था कि पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है और इसलिए, उप-जाति को पिछड़ों की सूची में शामिल किया गया है।

कक्षाओं को कला द्वारा समर्थित किया जाता है। 15 ( 4 ) . सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति मानदंड बनी रही। द असंप यह कहना कि किसी जाति के सभी सदस्य सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, पूरी तरह से निराधार है और सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक समर्थन का अभाव है।

जानकी प्रेस्ड परिमू एंड ओआरएस में। आदि। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। ( 5 ) यह देखा गया कि केवल गरीबी पिछड़ेपन की परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि इस देश में एक छोटी सी स्थिति को छोड़कर

आबादी का प्रतिशत, लोग आम तौर पर गरीब हैं-कुछ अधिक गरीब हैं, अन्य कम गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के कुछ क्षेत्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र उदासीन हैं, इस मानदंड को लागू करते हुए, पारंपरिक पेशे का पालन करने वाले पुरोहित वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं माना जाता था। जोत के आकार के आधार पर पिछड़े के रूप में नामित भूमि के किसानों को इस आधार पर अस्वीकार्य माना गया था कि केवल आर्थिक विचार को अन्य विचारों से ऊपर रखना, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए गलत है।

( 1 ) [ 1971 ] 2 एस. सी. आर 430 ( 2 ) [ 1972 ] 3 एस. सी. आर 247 ( 3 ) [ 1973 ] 3 एस. सी. आर 236



उत्तर प्रदेश राज्य में v. प्रदीप टंडन और अन्य। ( 1) आरक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में विचारों को इस आधार पर अस्थिर माना गया कि यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण का समर्थन करने के लिए वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती है।

केरल और अन्र राज्य में। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। ( 2 ) नियम 13एए की संवैधानिक वैधता दो की और छूट देती है।

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए वर्ष

आर में संदर्भित परीक्षणों को उत्तीर्ण करने से सेवा में जातियाँ। 13 या आर।

13ए, से पूछताछ की गई। उच्च न्यायालय ने इस नियम को रद्द कर दिया।

राज्य की अपील को अनुमति देते हुए, मैथ्यू, जे. ने अपने सहमति वाले फैसले में अभिनिर्धारित किया कि रोजगार के लिए अवसर की समानता प्रदान करने के लिए

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर ध्यान देना आवश्यक है।

न केवल निर्देशात्मक सिद्धांत कला में सन्निहित हैं। 46 बाध्यकारी

कानून निर्माताओं को जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, लेकिन उन्हें निर्णय लेते समय अदालत के दृष्टिकोण को समान रूप से सूचित और प्रकाशित करना चाहिए।

क्योंकि न्यायालय भी कला के अर्थ में राज्य है। 12 और अंतरालीय रूप से भी कानून बनाता है। समानता का अस्तित्व केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर ही नहीं बल्कि अक्षम संबंधों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। इसे प्राप्त करने के लिए असमान व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार की अनुमति है। इसे प्रतिपूरक भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई के रूप में वर्णित किया गया है। एक सहमत निर्णय में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कला की प्रतिभा का अवलोकन किया। 14 और 16 शाब्दिक समानता में नहीं बल्कि स्पष्ट असमानता के प्रगतिशील उन्मूलन में शामिल है। तीव्र रूप से भिन्न व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना सूक्ष्म अन्याय है। समान अवसर एक आशा है, खतरा नहीं।

कुमारी में के. एस. जयश्री और अन्र। वी. द स्टेस ऑफ केरल एंड अन्र। ( 3) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामाजिक और सामाजिक रूप से कौन हैं, यह निर्धारित करने की समस्या

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग निस्संदेह सरल नहीं हैं। इस सवाल पर कि क्या जाति अपने आप में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने का आधार हो सकती है, अदालत ने कहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का दावा करने वाले नागरिकों के समूह की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। व्यवसाय, निवास का स्थान भी यह निर्धारित करने में प्रासंगिक कारक हो सकते हैं कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं।

( 1 ) [ 1975 ] 2 एस. सी. आर. 761 (2) [1976] 1 एस. सी. आर. 906। ( 3 ) [ 1977 ] 1 एस सी आर 194.

» के, सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (देसाई, जे.)

: 383

1. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) के प्रतिनिधि

एसोसिएशन की ओर से इसके सहायक महासचिव द्वारा। वी. भारत संघ और अन्य। ( 1) इस न्यायालय ने विभिन्न स्तरों पर पदों के आरक्षण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में विभिन्न रियायतें देने को बरकरार रखा। कृष्ण अय्यर, जे. ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा को दिए गए अंतिम संबोधन का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष को देखते हुए राजनीतिक वर्चस्व अंत नहीं था, बल्कि एक सामाजिक प्रदर्शन था।

हठधर्मिता की स्थापना की जानी थी जिसके द्वारा इसका अर्थ एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित सामाजिक ताना-बाना था। कार्यात्मक रूप से अनुवादित, इसका अर्थ है 'सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन'।

यह संक्षिप्त समीक्षा स्पष्ट रूप से सी पर ध्यान केंद्रित करेगी।

और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के प्रश्न से निपटने में न्यायपालिका की ओर से अस्थिरता। न्यायपालिका ने अपनी आँखों पर अपनी पारंपरिक पट्टी रखी और इस तरह कथित वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया। न्यायिक हस्तक्षेप के एक बोधगम्य दर्शक ने देखा कि अदालतें एक सुविधाजनक बिंदु के रूप में अधिक सीमित साबित हुईं, तो मैंने शुरुआत में ही सरलता से मान लिया था। वे एक संतुलन चक्र प्रतिपूरक नीतियों के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करते हैं, लेकिन यह राजनीतिक प्रक्रिया है जो इन नीतियों के बड़े रूप को आकार देती है और उन्हें उनकी प्रेरक शक्ति देती है। आधिकारिक सिद्धांत-न्यायिक घोषणाएँ या प्रशासनिक नियम

दान-कार्रवाई में नीतियों के आकार और उनके द्वारा उत्पन्न परिणाम के लिए अपर्याप्त मार्गदर्शक साबित हुआ। ( 2) भारतीय सामाजिक परिदृश्य ने परेशान करने के अलावा स्तरीकृत समाज की तस्वीर को पदानुक्रमित रूप से खंडित रूप से प्रस्तुत किया। सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और उनके पक्ष में किसी भी तरजीही व्यवहार को कमोबेश न्यायिक अनुमोदन के साथ माना जाता है। लेकिन जब बात अधिमान्य व्यवहार या सकारात्मक कार्रवाई की आती है या जिसे सामाजिक रूप से प्रतिपूरक भेदभाव भी कहा जाता है

और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जाति ग्रस्त समाज ने अपना बदसूरत चेहरा उठाया। हजारों वर्षों से इसके अस्तित्व से, कमोबेश यह माना जाता था कि खनन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को रोकने के लिए जाति मानदंड होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह कहा जाता था, जाति को देखें, इसके पारंपरिक कार्यों को देखें, यह उच्च जातियों के संबंध में शुद्धता और प्रदूषण के मानक के आधार पर स्थिति में है, शुद्ध और इतना शुद्ध व्यवसाय नहीं है, एक बार जब इन प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया जाता है, तो वे लोग जो इससे संबंधित हैं।

( 1 ) . [ 1981 ] 2 एस. सी. आर 185 ( 2 ) मार्क गैलांटर-प्रतिस्पर्धी समानताएँ, 1980 पी। अठारवाँ।

एस.

आई.

आई.

1

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े का दर्जा दिया जाना चाहिए। यह

ए.

अति-सरलीकृत दृष्टिकोण ने प्रत्येक जाति में मौजूद एक बहुत ही यथार्थवादी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया कि ऐसी प्रत्येक जाति में जिसके सदस्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का दावा करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

खंडों को रखा। लेकिन यह इंतजार कर सकता है। हम वर्तमान में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को वरीयता देने के कार्यपालिका के प्रयास के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया से चिंतित हैं। अदालत में जो मुकदमा आया वह अक्सर उन लोगों द्वारा किया जाता था जो योग्यता पर भरोसा करते थे और शिकायत करते थे कि योग्यता को समानता के मृग की वेदी पर सूली पर चढ़ाया जाता है। पसंदीदा उपचार के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम संक्षेप में इस प्रकार है -

बी.

इसके अंतर्गत:

सी.

" संक्षेप में, हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्षतिपूर्ति भेदभाव नीति पर मुकदमेबाजी का सकल प्रभाव

इसे कम करना और सीमित करना रहा है। जिन लोगों ने अदालत में प्रतिपूरक भेदभाव योजनाओं पर हमला किया है, उन्होंने सफलता का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड संकलित किया है, जबकि प्रतिपूरक भेदभाव बढ़ाने की मांग करने वाले कम सफल रहे हैं। ( 1),

डी.

विवाद अब नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की ओर स्थानांतरित हो गया है। अभिव्यक्ति 'पीछे'

ई.

वार्ड वर्ग 'परिभाषित नहीं है। अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के अभाव में अदालतों को अधिक या नुकसान होता है, जो जाति लेबल पर आधारित नहीं हैं, इस दृष्टिकोण से घूमते हैं कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होने के लिए, समूह का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान संकेत होना चाहिए। संकीर्ण प्रश्न जिसकी जाँच की जा रही है

एफ.

यहाँ यह है कि क्या सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए जाति का लेबल पर्याप्त होना चाहिए? इस जटिल समस्या से निपटने के लिए कई आयोगों ने प्रयास किए हैं। हालाँकि, कर्नाटक के मंडल आयोग और गुजरात के बख्शी आयोग दोनों ने अंततः सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए पहचान मानदंड के रूप में जाति को शामिल किया है, हालांकि वर्तमान में इसे इंगित किया जाएगा।

जी.

कि मंडल आयोग को गंभीर आपत्तियाँ थीं: जाति मानदंड के बारे में। इनमें से अधिकांश आयोगों और सरकारी आदेशों ने अपनी सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव करने के लिए सांप्रदायिक इकाइयों का इस्तेमाल किया। गुजरात के राणे आयोग ने सामाजिक निर्धारण के आधार के रूप में जाति को खारिज करते हुए एक अलग रास्ता तैयार किया है।

एच.

और शैक्षिक पिछड़ेपन। सवाल जो हमें पूछना चाहिए और

( 1 ) मार्क गैलेंटर, प्रतिस्पर्धी समानताएँ, पी। 511 .



जवाब है: क्या जाति सामाजिक निर्धारण का आधार होनी चाहिए

और शैक्षिक पिछड़ेपन। दूसरे शब्दों में, किस कसौटी पर,

जिन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माना जाना है क्या पहचान की जानी चाहिए? प्रश्न को सरल बनाने के लिए: सदस्यता लेनी चाहिए

जाति नागरिकों के एक वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से दर्शाती है।

पीछे की ओर? यदि 'जाति' को सामाजिक निर्धारण के लिए मानदंड के रूप में अपनाया जाता है

और शैक्षिक पिछड़ेपन क्या यह एक वैध परीक्षा प्रदान करता है या यह होगा

कला का उल्लंघन करते हैं। 15 ( 1 ) जो किसी के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। नागरिक

पर। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर

उन्हें।

1

पी.

$ . :

फिर जाति क्या है? हालाँकि जाति पर चर्चा की गई है

विद्वानों और न्यायविदों, अभिव्यक्ति की कोई सटीक परिभाषा नहीं है

उभरा। जाति समाज का एक क्षैतिज विभाजन है।

किसी जिले या किसी क्षेत्र या पूरे राज्य में और कभी-कभी

इसके बाहर। ( 1) होमो पदानुक्रम के केंद्रीय होने की उम्मीद है और

जाति/प्रणाली के मूल तत्व से इसे अलग करते हुए

अन्य सामाजिक प्रणालियाँ। शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा

जाति व्यवस्था का अपमान करता है। लुई डुमोंट का कहना है कि

शुद्ध और अशुद्ध का विरोध पदानुक्रम का आधार है, जो

अशुद्ध की तुलना में शुद्ध की श्रेष्ठता है, जो अलगाव का आधार है

क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध को अलग रखा जाना चाहिए और इसके नीचे

श्रम का विभाजन क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध व्यवसायों को पसंद करना चाहिए

बुद्धिमान, अलग रहें। ( 2)। इसकी चार प्रमुख विशेषताएँ हैं - जाति व्यवस्था जो बनी रही: एकर होमो पदानुक्रम चरित्र: ( 1 )

- पदानुक्रम (2) समानता ( 3 ) विवाह पर प्रतिबंध; और (4)

वंशानुगत व्यवसाय। ( 3 ) अधिकांश जाति। अंतर्विवाही समूह हैं।

दो समूहों के बीच अंतर-विवाह की अनुमति नहीं है। लेकिन 'प्रतिलोम'

विवाह पूरी तरह से अज्ञात नहीं हैं। इसी तरह आगे बढ़ने के साथ

शहरीकरण के कारण, विभिन्न जातियों के सदस्य धीरे-धीरे हार मान रहे हैं,

पारंपरिक व्यवसाय और शुद्ध और अशुद्ध व्यवसाय किए जा रहे हैं।

श्रम की गरिमा की धारणा विकसित करके तिरस्कार किया। जिस तरह सेस्वतंत्रता के फल असमान रूप से विभिन्न वर्गों के बीच वितरित किए गए थे

समाज के विचार, हर जाति में एक तिगुना अस्तित्व में आया सदस्यों के बीच आर्थिक पुनरुत्थान के आधार पर विभाजन

जाति। जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं, उन्होंने लाभ उठाया है।

एक उच्च वर्ग की स्थिति (वर्ग चेतना) और एक कदम पर

नीचे मध्यम वर्ग है और तीसरा गरीब वर्ग से संबंधित है

. :

( 1 ) . आई. पी. देसाईः क्या 'जाति' को पिछड़ेपन को पहचानने का आधार होना चाहिए?

.वाय.

[ 1985 ) .

: ........

( 2 ) लुईस डुमोंट-होम हाइराचिकस (1970)। ( 3 ) समकालीन भारत में जातिः जी. शाह [1985]।



जाति से। इससे यह एहसास हुआ कि जाति संस्कृति आर्थिक हित में मदद नहीं करती है। वास्तव में एक ही जाति के उच्च वर्ग पर वास्तव में उसी जाति के निचले वर्ग का शोषण करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए, यह उचित तर्क दिया जाता है कि जाति व्यवस्था का आधार, अर्थात् शुद्धता और प्रदूषण धीरे-धीरे एक ही जाति के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति से विस्थापित हो रहा है। यह लगभग सभी हाथों से माना जाता है कि जाति संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरोत्तर क्षरण का सामना कर रही है। नया संगठन, तथाकथित जाति संगठन, पारंपरिक संरचना और जाति परिषदों से काफी अलग है। जाति के सदस्यों के बीच आर्थिक भेदभाव तेज हो गया है, लेकिन इतना तेज नहीं है कि जाति की भावनाओं और संबंधों को दफन कर दिया जाए।

यदि जाति संरचना में परिवर्तन जैसा कि यहाँ इंगित किया गया है

वास्तव में स्वीकार किया जाता है, क्या जाति के लेबल को अभी भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ए में

प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री आई. पी. देसाई (अफसोस, वे नहीं रहे) के हालिया शोध पत्र में यह तर्क दिया गया है कि जाति की नहीं बल्कि वर्ग या सामाजिक समूह की जांच उनकी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने की दृष्टि से की जानी चाहिए। ग्रामीण समाज में जाति अक्सर उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आर्थिक शक्ति में प्रतिबिंबित नहीं होती है। सामाजिक पदानुक्रम और आर्थिक स्थिति एक अविवादित पारस्परिकता प्रदर्शित करते हैं। जाति जितनी निचली होगी, उसके सदस्य उतने ही गरीब होंगे। जाति के सदस्य जितने गरीब होंगे, जाति उतनी ही नीची होगी। जाति और आर्थिक स्थिति, एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए जैसे वे करते हैं, सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के ड्यूस एक्स मशीना हैं।

ग्रामीण समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग द्वारा संचालित। सामाजिक स्थिति और आर्थिक शक्ति भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था में इस तरह बुनी और एकीकृत की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कह सकता है कि यदि गरीबी इसका कारण है, तो जाति सामाजिक पिछड़ेपन का प्राथमिक सूचकांक है, ताकि सामाजिक पिछड़ेपन को अक्सर किसी व्यक्ति की जाति के संदर्भ में आसानी से पहचाना जा सके। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय समाज में जाति की मूल शक्ति और सर्वव्यापीता है, हालाँकि, हम इसे दूर करना चाहते हैं। दुख की बात है कि हमारे देश में जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसने धर्म की बाधाओं को भी पार कर लिया है। जाति व्यवस्था ने अन्य धार्मिक और असंतुष्ट हिंदू संप्रदायों में प्रवेश कर लिया है, जिनके लिए जाति की प्रथा अभिशाप होनी चाहिए और आज हम जुर्माना लगाते हैं कि अन्य धार्मिक आस्थाओं के पालन करने वाले और हिंदू भावनाओं के पालन करने वाले कभी-कभी उतने ही कठोर होते हैं

जाति व्यवस्था के अनुयायी

रूढ़िवादी हिंदू। हम.

ईसाई हरिजनों, ईसाई के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (देसल, जे.) को ढूंढें।

387

मदरस, ईसाई रेड्डी, ईसाई कम्मा, मुजबी सिख आदि। आंध्र प्रदेश में एक समुदाय है जिसे पिंजार या ड्यूड कुलास (उत्तर में 'रुई पिंजने वाला' के रूप में जाना जाता है) के नाम से जाना जाता है: ( पेशेवर कपास-पीटने वाले) जो वास्तव में मुसलमान हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक हिंदू जाति के रूप में व्यवहार किया जाता है। कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं।

आर्थिक पदानुक्रम में साझा स्थिति, जाति वर्गीकरण,

व्यवसाय, निवास, उपभोग की शैली, साक्षरता का स्तर और ऐसे कई अन्य कारक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर जाते प्रतीत होते हैं। कुछ स्थितियों में और वास्तव में अक्सर, सामाजिक अन्वेषक

आसानी से एक पूरे जाति समूह को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचानने में सक्षम हो सकते हैं; वह कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे पहाड़ी, जीवन का एक नया पट्टा छोड़ दें। वास्तव में एक ऐसी जाति से संबंधित होने के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पागल भीड़ है जिसे इसके नामकरण से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाएगा।

इसे स्पष्ट करने के लिए: गुजरात में बख्शी आयोग ने जितने लोगों को मान्यता दी

82 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियाँ। जिस पर

अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, गुजरात सरकार को उन जातियों के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ जिन्होंने कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया था

बख्शी आयोग को उनके साथ सामाजिक व्यवहार करने के लिए और

शैक्षिक रूप से पिछड़े। इस घटना को मंडल ने देखा था।

आयोग ने जब यह टिप्पणी की: जबकि आयोग ने कोशिश की हैओ. बी. सी. एस. की राज्यवार सूचियों को यथासंभव व्यापक बनाना,

यह काफी संभावना है कि वापस सूचीबद्ध जातियों के कई पर्यायवाची

वार्ड को छोड़ दिया गया है। कुछ जातियों को कई लोगों द्वारा जाना जाता है -

समानार्थी शब्द जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और उनके समुदाय में भिन्न होता है

पूर्ण कवरेज लगभग असंभव है। मंडल आयोग ने पाया कि यह सिफारिश करके कि यदि किसी विशेष जाति के साथ व्यवहार किया गया है

पिछड़े के रूप में इसके सभी पर्यायवाची शब्द चाहे राज्य में उल्लिखित हों

सूचियाँ हों या न हों, उन्हें भी पिछड़े माना जाना चाहिए। ( 1) गुजरात सरकार

एक दूसरा आयोग नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया जिसे राणे के नाम से जाना जाता था आयोग। राणे आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि वहाँ

सामाजिक रूप से माने जाने के लिए एक संगठित प्रयास था और

शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियाँ। राणे आयोग ने याद किया कि

बालाजी के मामले में टिप्पणियाँ कि 'सामाजिक पिछड़ेपन पर है

बहुत हद तक गरीबी के परिणाम का अंतिम विश्लेषण। द.

आयोग ने देखा कि कुछ जातियाँ सिर्फ होने के लिए

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले लोगों का पतन हुआ है

( 1 ) मंडल आयोग की रिपोर्ट खंड, च। बारहवाँ पी। 55 , 388



स्वयं को इस हद तक कि, उन्हें अपनी जातियों के साथ पिछड़ेपन के संकेत देने वाले अन्य कारकों को विभिन्न प्रकार के दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराने और उन्हें जोड़ने में कोई संकोच नहीं था। आयोग ने कहा कि इस अस्वस्थता को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए आयोग ने जाति के संदर्भ के बिना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने के लिए एक विधि तैयार की, जो उस जाति के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद है जिससे वे संबंधित हैं। आयोग एक निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचा कि कुछ जातियों और समुदायों या लोगों के वर्ग में, उनमें से केवल निम्न आय वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। हम यहाँ एन. एम. थॉमस के मामले में एक संक्षिप्त अवलोकन को याद कर सकते हैं जो नीचे दिया गया है:

" समाजशास्त्रीय सावधानी का एक शब्द। के प्रकाश में

अनुभव, यहाँ और कहीं और, 'आरक्षण' का खतरा, मुझे लगता है, तीन गुना है। इसके लाभ, बड़े पैमाने पर, 'बैक वार्ड' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार सप्ताह के बीच सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखते हैं और भाग्यशाली परतों को पीछे छोड़ देते हैं।

पूरे केक का सेवन करें। दूसरा, यह दावा लोकतंत्र में बड़े और मुखर समूहों द्वारा अतिरंजित तरीके से किया जाता है समय के उतार-चढ़ाव और बेहतर शिक्षा के उपायों और रोजगार के अधिक अवसरों से आंशिक रूप से हल्का हुआ, लेकिन औपचारिक रूप से ऊपरी कोष्ठक के रूप में वर्गीकृत अपने निकट-बराबर से अधिक अंक प्राप्त करने के साधन के रूप में 'कमजोर वर्ग' के लेबल को कमजोर करना चाहते हैं।

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के आधार के रूप में जाति को अस्वीकार करने के कुछ अन्य पहलुओं पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है। यदि पसंदीदा व्यवहार के लिए राज्य संरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति को एकमात्र प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है, तो खतरा बहुत बड़ा है कि केवल यह दृष्टिकोण ही जाति व्यवस्था को वैध और स्थायी बना देगा। यह हमारे घोषित धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ ठीक नहीं है जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यह धारणा कि किसी जाति के सभी सदस्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान रूप से पिछड़े हैं, उचित नहीं है। इस तरह का दृष्टिकोण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने की एक जटिल समस्या का अति सरलीकरण प्रदान करता है। के अध्यक्ष

1953 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बेहतर होता कि हम के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (ईसाई, जे.) के अलावा अन्य सिद्धांतों पर पिछड़ेपन के मानदंड निर्धारित कर पाते।

389

जाति '। ( 1) अंत में यह बिना असहमति के माना जाता है कि जाति आधारित है।

समान जाति के आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग ने आरक्षण को हड़प लिया है। उदाहरण के लिए, यह बताया जा सकता है कि कुछ साल पहले, मुझे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति के लिए एक याचिका मिली थी जिसमें

2-1 / 2 " पंजाब में सिखों के बीच अनुसूचित जातियों के सदस्यों के उच्च वर्ग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में माझाबी सिखों के पक्ष में प्रवेश के लिए चुनौती दी थी, जिससे यह साबित होता है कि कमजोर व्यक्ति वास्तव में कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। इसके अलावा, मंडल आयोग की सहायता करने वाले समाजशास्त्रियों की अनुसंधान योजना योजना के निष्कर्षों में कहा गया है: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के मानदंडों के खनन को रोकते हुए,

सामाजिक पिछड़ेपन को महत्वपूर्ण तत्व माना जाना चाहिए और शैक्षिक पिछड़ेपन को जुड़ा हुआ तत्व माना जाना चाहिए।

अनिवार्य रूप से पूर्व से व्युत्पन्न। ' ( 1) अंततः टीम

निष्कर्ष निकाला कि 'सामाजिक पिछड़ेपन का अर्थ निर्धारित स्थिति और

प्राप्त स्थिति के लिए शैक्षिक चेतावनी, और यह माना जाता है

महत्वपूर्ण तत्व और शैक्षिक पीठ के रूप में सामाजिक पिछड़ेपनवार्डनेस जुड़ा हुआ है, हालांकि व्युत्पन्न तत्व नहीं है। यह प्रयास

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों की पहचान करना है।

जाति, जैसा कि हिंदू समाज में समझा जाता है, अज्ञात है

मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि जाति मानदंड नहीं होगा। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने के लिए एक विश्वसनीय पैमाना प्रस्तुत करें

उपरोक्त समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े समूह

पिछड़ेपन होगा।

इसलिए, मानदंड की समीक्षा करने का समय आ गया है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना

जाति लेबल। एकमात्र मानदंड जिसे यथार्थवादी रूप से तैयार किया जा सकता है वह है आर्थिक पिछड़ेपन का एक। इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है।

पिछड़ेपन को भार तारा होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? दीर्घकालिक गरीबी भारतीय समाज का अभिशाप है। बाजार आर्थिक और धन कताई संस्कृति ने अपने सदस्यों के प्रति समाज के सामान्य व्यवहार को बदल दिया है। उच्च जाति का दर्जा या सम्मान, पारंपरिक, स्वैच्छिक या ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिक होता है, जो कि अत्यधिक पश्चिमीकृत शहरी समाज की बात है।

( 1 ) पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट खंड। आई. च. XIV। ( 2 ) भाग 3 परिशिष्ट XIII, पी।



बैंक संतुलन, संपत्ति धारण और धन की शक्ति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को कम करती है और इसकी गारंटी देती है।

शीर्ष स्तर पर पहुँचने का अवसर। धन कैसे अर्जित किया जाता है, इसका महत्व कम हो गया है। महात्मा गांधी के साथ साधनों की शुद्धता गायब हो गई और हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं जहां लक्षय साधनों का निर्धारण करते हैं। चाहे कोई इसे पसंद करे या न करे, यह वर्तमान परेशान करने वाली स्थिति है। अपने समक्ष साक्षय के आधार पर और प्रासंगिक परीक्षणों और मानदंडों को लागू करने के बाद आयोग को निम्नानुसार देखा गया:

" हमने प्रासंगिक परीक्षणों को लागू करने और अभिलेख पर साक्षय के आधार पर पाया है कि कुछ जातियाँ/समुदाय या लोगों के वर्ग हैं जो पिछड़े हैं, लेकिन उनमें से केवल निम्न आय वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपरोक्त पहलू के संबंध में कोई अस्पष्टता न रहे, हम यह जोड़ सकते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियाँ मानती हैं ।उन वर्गों के संबंध में भी अच्छा है जो पहचाने जाते हैं

बिना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े

किसी भी जाति का संदर्भ "। ( 1)

किसी न किसी रूप में आरक्षण दशकों से रहा है। यदि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले विभिन्न जातियों के परिवारों के संदर्भ में एक सर्वेक्षण किया जाता है, तो

पसंदीदा उपचार के लाभ, यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आरक्षण के लाभ शीर्ष मलाईदार द्वारा छीन लिए जाते हैं

पिछड़ी जातियों की परत। इससे किसी भी कीमत पर बचना चाहिए।

यदि गरीबी को सामाजिक और सामाजिक निर्धारण का मानदंड बनाना है।

शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हमें समाजशास्त्रियों द्वारा व्यक्त किए गए भय से निपटना चाहिए। समाजशास्त्री के शब्दों में इन पहलुओं को दोहराना बेहतर है:

" अब, यदि सरकार जाति से वर्ग में आरक्षण के मानदंड को बदलती है, तो निचली जातियों के उच्च वर्ग के व्यक्ति जो आरक्षण के बावजूद उच्च जातियों के उच्च वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सफेदपोश नौकरियों से बाहर रखा जाएगा। और निचली जातियों के निम्न वर्ग के लोग उच्च जातियों के अपने समकक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। यह

( 1 ) राणे आयोग की रिपोर्ट अध्याय बारहवीं अनुच्छेद 12.1।



उस अंतर को पाटेंगे जो अन्यथा के बीच चौड़ा हो रहा है

उच्च जातियों के अमीर और गरीब और यह होगा उनकी जाति पहचान को मजबूत करें। यह छोटे को मिटा देगा

गरीबों की कीमत पर उच्च जातियों का गरीब वर्ग

निचली जातियों के वर्ग, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। में।

समय के साथ उच्च जाति भी उच्च जाति बन जाएगी।

वर्ग। इस तरह की प्रक्रिया विकास में बाधा डालेगी

धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ "। ( 1)

इस भय मनोविकृति का एक प्रख्यात शिक्षाविद द्वारा प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर गरीबों को परिचालन रूप से परिभाषित, वर्गीकृत और उप-वर्गीकृत किया जा सकता है और आरक्षण लाभों को तदनुसार स्तरीकृत किया जा सकता है, तो क्या परिदृश्य अभी भी उपयोगी होगा? मुझे नहीं लगता। उन्होंने माना कि यह बिंदु गरीब वर्ग की धारणाओं को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता के प्रति सभी को सचेत करने के संदर्भ में मूल्यवान है। उन्होंने माना कि राज्य अपनी सभी

सीमाओं और संसाधनों के साथ सामाजिक परिवर्तन को निर्देशित करने और योजना बनाने के लिए है। ( गैर-क्रांतिकारी) विकल्प 'जाति' को मजबूत करने या मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के बीच है।

मूल्य '। ( 3)

मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि प्रतिपूरक के लिए आर्थिक मानदंड

भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई को स्वीकार किया जाता है, यह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के मूल कारण पर हमला करेगा, और साथ ही जाति संरचना के विनाश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगा जो बदले में राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आगे बढ़ाएगा। यह दृष्टिकोण दोहरे संवैधानिक लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है: एक, भारतीय समाज के जातिगत स्तरीकरण को कायम रखने के लिए हड़ताल करना ताकि प्रगतिशील कदम को रोका जा सके और एक जातिविहीन समाज की स्थापना की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जा सके।

और दो, समाज के वंचित वर्गों को अपनी स्थिति बढ़ाने और जीवन की मुख्यधारा का हिस्सा बनने का अवसर देकर गरीबी को उत्तरोत्तर समाप्त करना, जिसका अर्थ है -

गरीबी।

मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह दृष्टिकोण काम नहीं करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में आरक्षण के साथ। हजारों वर्षों का भेदभाव और शोषण नहीं हो सकता।

एक पीढ़ी में मिटा दिया। लेकिन यहां भी आर्थिक मानदंड लागू करने के लिए उन लोगों के लिए पसंदीदा उपचार से इनकार करना उचित है जो

( 1 ) जी. शाह आईपीडब्ल्यू 17 जनवरी, 1983। ( 2 ) उपेंद्र बख्शी, उप-कुलाधिपति, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, 'जाति,

वर्ग और आरक्षण: घनश्याम शाह को एक प्रत्युत्तर।



जो पहले ही इससे लाभान्वित हो चुके हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर चुके हैं।

ए.

और अंत में आरक्षण की एक समय अवधि होनी चाहिए अन्यथा रियायतें।

निहित स्वार्थ बन जाते हैं। यह एक सूची में एक निर्णय नहीं हैविरोधी प्रणाली। जब तर्क समाप्त हुए, तो एक बयान था

बनाया कि कर्नाटक राज्य सरकार एक नियुक्त करेगी

संवैधानिक रूप से मजबूत और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित करने के लिए आयोग

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए स्वीकार्य मानदंड

"

बी.

नागरिकों के ऐसे वर्ग जिनके लाभ के लिए राज्य कार्रवाई करेगा।

कुछ हद तक, उस दिशा की ओर इशारा कर सकता है जिसमें प्रस्तावितआयोग को आगे बढ़ना चाहिए।

चिनापा रेड्डी, जे. तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है जब से हम

सी.

स्वयं से "न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक" का वादा किया और

" स्थिति और अवसर की समानता "। फिर भी, आज भी, हम पाते हैं

जातियों, समुदायों, वर्गों या किसी भी नाम से आप

उनका वर्णन कर सकते हैं, स्थिति के लिए जॉकी कर सकते हैं, एक दूसरे को कोहनी देने की कोशिश कर सकते हैं बाहर, और, एक दूसरे के साथ देखने के लिए नामित और पहचाने जाने के लिए

डी.

' सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, 'प्राथमिक' के लिए गुणवत्ता

उन्नति और प्रावधान के लिए विशेष प्रावधान का अपमानआरक्षण के लिए जो कला के तहत किया जा सकता है। 15 ( 4 ) & 16 ( 4 ) में से

संविधान। आरक्षण प्रणाली का विरोधाभास यह है कि

लोगों में आत्म-अपमान की भावना पैदा की है। अब

दुनिया में कहीं और जातियाँ, वर्ग या समुदाय कतार में खड़े होते हैं

पीछे की मूर्ति प्राप्त करने के लिए। दुनिया में कहीं और नहीं

क्या पिछड़ेपन का दावा करने और 'हम हैं' का दावा करने के लिए प्रतिस्पर्धा है

आप से अधिक पिछड़े '। यह एक दुखी और परेशान करने वाली स्थिति है।

यह, लेकिन यह एक कठोर वास्तविकता है। जो भी चमक कोई डालना चाहे

इन अपीलों और रिट में प्रतिद्वंद्वी दावों से यह स्पष्ट है

एफ.

याचिका है कि यहाँ असली मुकाबला दो के कुछ सदस्यों के बीच है कर्नाटक के प्रमुख (जनसंख्या-वार) जाति-समुदाय-वर्ग,

लिंगायत और वोक्कालिगा, प्रत्येक का दावा है कि दूसरा एक नहीं है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और प्रत्येक को शामिल करने के लिए उत्सुक

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल। को।

उन्हें, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे का सदस्य करार दिया जाए

जी.

वार्ड क्लास पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक पासपोर्ट है और

कभी वे बाहर रहते हैं और कभी वे उनमें से कुछ की शुरुआत करते हैंप्रतियोगिता या आरक्षण द्वारा वैध प्रवेश का हकदार। कॉम.

पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए अतीत में मिशन नियुक्त किए गए हैं

एच.

वर्ग, सरकारों ने आयोगों की रिपोर्टों पर विचार किया है,

और अदालतों ने सरकारों के फैसलों की जांच की है; मामलों में

अदालत में भी पहुंचे, तब और अब बार-बार।

एक बार फिर हमें बताया जाता है कि के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

कि कर्नाटक राज्य एक और आयोग नियुक्त करने के लिए तैयार है और उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या आप कृपया कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करेंगे?

हमारा देश महान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का देश है

सिटी। हम अक्सर देश की सांस्कृतिक विविधता पर बहुत गर्व करते हैं। जहाँ सांस्कृतिक विविधता भारत की भव्यता को बढ़ाती है, वहीं अन्य हमारे दुख और शर्म को बढ़ाती हैं। सामाजिक और आर्थिक मतभेद वास्तव में निराशाजनक रूप से विशाल हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जिन्हें 'लोगों के कमजोर वर्गों' के रूप में वर्णित किया गया है, को समाज बनाने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें सहायता की आवश्यकता है; उन्हें सुविधा की आवश्यकता है; उन्हें प्रक्षेपण की आवश्यकता है; उन्हें प्रणोदन की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकताएँ उनकी माँगें हैं। मांगें अधिकार के मामले हैं न कि परोपकार के। वे समानता की माँग करते हैं, दान की नहीं। द्रोणाचार्य और एकलव्य के दिन समाप्त हो गए हैं। वे अपना संवैधानिक दावा करते हैं

स्थिति और अवसर और आर्थिक समानता का अधिकार सामाजिक न्याय। कई पुलों का निर्माण करना पड़ता है ताकि वे

रूबिकॉन को पार करें। के तहत व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार

राज्य को ऐसे दो पुल माना जाता है। इसलिए विशेष प्रो उन्नति के लिए और कला के तहत आरक्षण के लिए दृष्टिकोण। 15 ( 4 ) और

16 ( 4 ) संविधान से।

इससे पहले कि हम कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित आयोग के लाभ के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रयास करें

बेहतर होगा कि हम खुद को और प्रस्तावित आयोग को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के सवाल के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण के नुकसान के खिलाफ चेतावनी दें, जो आम तौर पर बेहतर, अभिजात्य वर्ग और इसलिए अस्पष्ट रहा है। जो बुराई की गई थी उसे पूर्ववत करने का कर्तव्य

ऐसा माना जाता है कि पीढ़ियों के माध्यम से एक उदारता और दूरदर्शिता जो राष्ट्रों के बीच दुर्लभ है। इसलिए एक श्रेष्ठ और पैट्रो नाइसिंग रवैया अपनाया जाता है। परिणाम यह है कि मानव और संवैधानिक अधिकार के मामले के रूप में समानता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के दावे को भुला दिया गया है और उनके अधिकार 'प्रोफेरेन टियल सिद्धांत' या 'सुरक्षात्मक या क्षतिपूर्ति भेदभाव' के रूप में वर्णित किए गए हैं, जो अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। जब तक हम इन श्रेष्ठ, संरक्षक और पैतृक दृष्टिकोण से छुटकारा नहीं पाते हैं, जिसे फ्रांसीसी ले मेन्टेलाइट पदानुक्रम कहते हैं, तब तक वास्तव में इसकी सराहना करना मुश्किल है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के दावे में शामिल समस्याएं उनके मानवता से संबंधित होने और एक देश [1985] एस. यू. पी. पी. एल. से उत्पन्न होने वाले लाभों के वैध हिस्से के लिए।

एस सी आर।

394

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसका संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और सभी के लिए स्थिति और अवसर की समानता का उपदेश देता है।

श्रेष्ठ, अभिजात्य दृष्टिकोण के परिणामों में से एक यह है कि

आरक्षण के सवाल को हमेशा योग्यता के सिद्धांत और क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के बीच संघर्ष के रूप में देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक संघर्ष उन लोगों के वर्ग के बीच है, जो कभी गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के रेगिस्तान में नहीं रहे हैं या जो पहले ही गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के रेगिस्तान से बाहर निकल चुके हैं। विषाक्त जीवन और जो अभी भी रेगिस्तान में हैं और मरूद्यान तक पहुंचना चाहते हैं। बगीचे में पर्याप्त फल नहीं हैं और इसलिए जो लोग अंदर हैं, वे बाहर के लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। हमारे देश के अल्पपोषित, निर्धनता से पीड़ित, मुश्किल से पढ़े-लिखे और कमजोर लोगों के विशाल बहुमत के लिए तथाकथित मेरिटेरियन सिद्धांत के विनाशकारी संकेतों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। और, क्या?

क्या यह योग्यता है? ऐसी प्रणाली में कोई योग्यता नहीं है जो इस तरह के परिणाम लाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की संतान नहीं है जिसका पालन-पोषण किसी राज्य में किया गया है।

गरीबी, निरक्षरता और संस्कृति-विरोधी वातावरण, जिसे परंपरा और समाज द्वारा नीचा देखा जाता है, जिसके पास घर पर पढ़ने के लिए किताबें और पत्रिकाएं नहीं हैं, सुनने के लिए रेडियो नहीं है, देखने के लिए टीवी नहीं है, उसके घर के काम में मदद करने वाला कोई नहीं है, जो निकटतम स्थानीय बोर्ड स्कूल और कॉलेज जाता है, जिसके माता-पिता अनपढ़ हैं या इतने अज्ञानी और अनजान हैं कि वह किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर उनकी सलाह लेने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है, एक बच्चा जिसे दुनिया में क्या हो रहा है, यह जानने के लिए निकटतम सार्वजनिक पठन कक्ष में अखबार पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ता है, क्या इस बच्चे को योग्यता नहीं मिली है अगर वह अपने सभी नुकसानों के साथ 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सक्षम है। निश्चित रूप से, एक बच्चा जो इतनी सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम रहा है, उससे जीवन में आगे बढ़ने के साथ बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा सकती है। यदि वसंत फूल वह नहीं हो सकता है, तो शरद फूल वह हो सकता है। उसे एक कथित

योग्यता के सिद्धांत पर सीमा पर क्यों रोका जाना चाहिए? दक्षता की आवश्यकताओं को हमेशा न्यूनतम मानकों के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। उच्च वर्गों के मामले में अतीत में मध्यस्थता हमेशा विजयी रही है। लेकिन तथाकथित योग्यता के सिद्धांत को औसत दर्जे के खिलाफ क्यों रखा जाना चाहिए?

जब हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं

कक्षाएँ?



जब भी विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की जुबान पर दक्षता बहुत अधिक होती है

आरक्षण का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि यदि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो दक्षता प्रभावित होगी; ऐसा लगता है कि यदि 'कैरी फॉरवर्ड' नियम अपनाया जाता है तो दक्षता प्रभावित होगी; ऐसा लगता है कि यदि आरक्षण का नियम पदोन्नति के पदों तक बढ़ाया जाता है तो दक्षता प्रभावित होगी। 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के खिलाफ या पदोन्नति के पदों तक विस्तार के विरोध से और कैरी फॉरवर्ड नियम के खिलाफ, कोई भी सोच सकता है कि सिविल सेवा एक स्वर्गीय स्वर्ग है जिसमें केवल प्रधान स्वर्गदूत, अभिजात वर्ग के चुने हुए, सबसे अच्छे लोग ही प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें सीढ़ी के ऊपर जाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि

अन्यथा है। सच्चाई यह है कि सिविल सेवा कोई स्वर्ग नहीं है और

चयनित वर्गों से संबंधित उच्च स्तर आवश्यक रूप से दक्षता के मॉडल नहीं हैं। अंतर्निहित धारणा है कि जो संबंधित हैं

उच्च जातियों और वर्गों के लिए, जिन्हें गैर-आरक्षित वर्ग में नियुक्त किया जाता है

पद अपनी अनुमानित योग्यता के कारण 'स्वाभाविक रूप से' बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

जो आरक्षित पदों पर नियुक्त किए गए हैं और

दक्षता की स्पष्ट धारा घुसपैठ से प्रदूषित हो जाएगी

पवित्र परिसरों में बाद वाला एक दुष्चक्रपूर्ण धारणा है, जो विशिष्ट है

अभिजात वर्ग का बेहतर दृष्टिकोण। न तो सांख्यिकीय है

इन धारणाओं का समर्थन करने के लिए न तो आधार और न ही विशेषज्ञ साक्षय यदि पुनरुत्थान 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो दक्षता अनिवार्य रूप से खराब हो जाएगी।

यदि आरक्षण को आगे बढ़ाया जाता है या यदि आरक्षण को आगे बढ़ाया जाता है

प्रचार करते हैं। तर्क उन्नत हैं और राय हैं

पूरी तरह से एक तदर्थ अनुमानित आधार पर व्यक्त किया गया। उम्र लंबी है। अवमानना जिसके साथ 'श्रेष्ठ' या 'अग्रगामी' जातियों ने व्यवहार किया है

'निम्न' या 'पिछड़े' कास्ट अब बदल रहे हैं और क्रिस्टलिस हैं

स्वयं को एक अनुचित पूर्वाग्रह में डालना, सचेत और अवचेतन, हमेशा

चूंकि 'निम्न' जातियों और वर्गों ने अपने वैध होने का दावा करना शुरू कर दिया था

केक का हिस्सा, जिसका स्वाभाविक रूप से अर्थ है, 'श्रेष्ठ' जातियों के लिए

इसे थोड़ा सा छोड़ दें। हालांकि वास्तविक व्यवहार में उनके आभासी

अभिजात वर्ग के व्यवसायों और पदों पर एकाधिकार शायद ही खतरे में है,

फिर भी अगड़ी जातियों को डर है कि वे पलायन कर रहे हैं सरकारी सेवा के उच्च पदों में इस एकाधिकार को खोना और

पेशा। 'श्रेष्ठ' जातियों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है

खड़े हों और अपने पूर्वाग्रह से ऊपर उठें और यह उनके लिए इतना मुश्किल है

कटु पूर्वाग्रह और विरोध को दूर करने के लिए निम्न जातियों और वर्गों

जिसका वे हर स्तर पर सामना करने के लिए मजबूर हैं। हमेशा एक दक्षता शब्द को सुनता है जैसे कि यह पवित्र और गर्भगृह है

कड़ी सुरक्षा की जानी चाहिए। ' दक्षता 'एक मंत्र नहीं है जो है

शिष्य के कान में गुरु द्वारा फुसफुसाया गया। केवल सुरक्षा एक परीक्षा में उच्च अंक आवश्यक रूप से अच्छे 396 को चिह्नित नहीं कर सकते हैं

प्रशासक। एक कुशल प्रशासक, जो इसे लेता है, वह होना चाहिए

जिनके पास अन्य गुणों के साथ समझने की क्षमता है

सहानुभूति और, इसलिए, एक बड़ी समस्या की समस्याओं से बहादुरी से निपटने के लिए

आबादी का एक हिस्सा जो लोगों के कमजोर वर्गों का गठन करता है।

और, उन्हीं वर्गों से संबंधित लोगों से बेहतर कौन है? क्यों?

खुद से मत पूछिए कि 35 साल बाद, स्वतंत्रता की स्थिति क्यों अनुसूचित जाति आदि में बहुत सुधार नहीं हुआ है? क्या यह कानूनी नहीं है?

यह पूछने के लिए कि क्या चीजें अलग हो सकती हैं, साथी का सवाल था

इन वर्गों से बड़ी संख्या में जिला प्रशासकों और राज्य और केंद्रीय नौकरशाहों को शामिल किया गया था। अदालतें नहीं हैं।

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं

जवाब और समाधान खोजने के लिए सरकार के ईमानदार प्रयासों के साथ। हमारा यह कहना नहीं है कि सिविल सेवा में दक्षता अनावश्यक है या यह एक मिथक है। हमारा बस इतना कहने का मतलब है कि किसी को इसके बारे में भद्दी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ पदों के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ की नियुक्ति की जा सकती है और अध्ययन के कुछ पाठ्यक्रमों के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ को ही प्रवेश दिया जा सकता है यदि ऐसा है, तो नियमों में ऐसे पदों पर नियुक्ति और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकता है। नियम कोई उपयुक्त विधि प्रदान नहीं कर सकते हैं

चयन करें। ऐसा हो सकता है कि कुछ पदों के लिए बहुत उच्च स्तर के कौशल या दक्षता की आवश्यकता होती है और अध्ययन के कुछ पाठ्यक्रमों के लिए उच्च स्तर के उद्योग और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा है, तो नियम उच्च निर्धारित कर सकते हैं

न्यूनतम योग्यता मानक और चयन की एक उपयुक्त विधि। विभिन्न न्यूनतम मानक और विभिन्न विधियाँचयन विभिन्न पदों के लिए और पदों की आवश्यकताओं और अध्ययन के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी यह सुझाव नहीं देगा कि एक कार्डियक या न्यूरो सर्जन के लिए आवश्यक दक्षता की डिग्री समान है

एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक दक्षता की डिग्री। इसी तरह कोई सुझाव नहीं देगा कि एक शोध डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार से अपेक्षित उद्योग और बुद्धिमत्ता की डिग्री एक साधारण कला डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार के समान होनी चाहिए। इसलिए, हमारा यह कहना नहीं है कि दक्षता में पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए। यह सब हम

कहने का मतलब यह है कि इसे छलावरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

ताकि उच्च वर्ग पिछड़े वर्गों का लाभ उठा सकें

सेवाओं, विशेष रूप से उच्च पदों और पेशेवर संस्थानों का नाम लेना और उन पर एकाधिकार करना। हमें डर है कि इससे पहले कि हम समस्या के मूल में पहुँचें, हमें अपने दिमाग को कई जालों से मुक्त करना होगा।

समानता की खोज आत्म-मायावी है, हमें अपने भ्रम खोने चाहिए,

लेकिन हमारा विश्वास नहीं। खोज को आगे बढ़ाना मनुष्य की गरिमा है।

समानता के लिए। इस मोड़ पर आर. एच. टॉनी को उनके उत्कृष्ट कार्य समानता में उद्धृत करना फायदेमंद होगा जहाँ वे कहते हैं।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

397

" सच्चाई यह है कि यह पुरुषों के लिए बेतुका और अपमानजनक है।

एक-दूसरे के प्रति अपनी बौद्धिक और नैतिक श्रेष्ठता का अधिक से अधिक उपयोग करना और फिर भी धन और शक्ति लाने वाली कलाओं में अपनी श्रेष्ठता का अधिक उपयोग करना, क्योंकि किसी भी सार्वभौमिक योजना में उनके स्थान के आधार पर, वे असीम रूप से महान या असीम रूप से छोटे हैं। समानता जो इन सभी

विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि क्षमता या प्राप्ति की समानता वांछनीय नहीं है, बल्कि परिस्थितियों और संस्थानों और जीवन के तरीके की समानता वांछनीय है। वे जिस समानता की निंदा करते हैं, वह व्यक्तिगत उपहारों की असमानता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक वातावरण की असमानता है.. उनके विचार, संक्षेप में, यह है कि, क्योंकि पुरुष पुरुष हैं, सामाजिक संस्थान-संपत्ति के अधिकार, उद्योग का संगठन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रणाली-की योजना बनाई जानी चाहिए, जहां तक संभव हो, उन वर्ग मतभेदों पर जोर देने और मजबूत करने के लिए, जो विभाजित करते हैं, न कि आम मानवता को।

जो उन्हें एकजुट करते हैं।

99

लेकिन योग्यता और क्षतिपूर्ति के बीच विवाद 398

टोरी सिद्धांतों को हमारे सामने के मुद्दों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। समानता के मौलिक अधिकारों का एक बोधगम्य परिणाम

हमारे संविधान के तहत सभी नागरिकों को कानून, कानूनों की समान सुरक्षा, अवसर की समानता आदि की गारंटी, लोगों के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश और सेवाओं में प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार है। स्थिति की वास्तविकताओं की सराहना करते हुए, और कम से कम किसी भी गलतफहमी के कारण, संविधान ने कला में लोगों के कमजोर वर्गों के इस अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख करने का विशेष ध्यान रखा है। 15 ( 4 ) और संविधान की धारा 16 (4)। कला की दृष्टि से। 15 ( 4 ) और 16 (4), मेरिटेरियन और कॉम के बीच तथाकथित विवाद

दंडात्मक सिद्धांतों का कोई बड़ा महत्व नहीं है, हालांकि, निश्चित रूप से, हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि दक्षता का त्याग किया जाना चाहिए। वास्तव में सवाल यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग कौन हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों और प्रतिनिधियों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान और आरक्षण के हकदार हैं।

सेवाओं में प्रेषण। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सवाल है, उनकी पहचान का सवाल खड़ा हैभाग XVI के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा हल किया गया

संविधान से। समस्या केवल पहचान के संबंध में है

अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का गठन। द.

वास्तव में सवाल यह है कि इन पिछड़े वर्गों की पहचान कैसे की जाए

उन्हें कला के द्वार से प्रवेश करने के लिए। 15 ( 4 ) और 16 (4)। और, आगे का सवाल, स्वाभाविक रूप से, आरक्षण की सीमाओं के बारे में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

हमें डर है कि अदालतें सबसे सक्षम नहीं हैं।

पिछड़े वर्ग की पहचान करना या व्यापक और बहुत सामान्य तरीके को छोड़कर उनकी पहचान के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं; हमारे पास सामाजिक पिछड़ेपन को मापने के लिए कोई कानूनी बैरोमीटर नहीं है। हम वास्तव में लोगों से, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों से, स्तर दर स्तर श्रेणीकरण और

अवक्रमण। और, भारत इतना विशाल देश है कि परिस्थितियाँ राज्य से राज्य, क्षेत्र से क्षेत्र, जिले से जिले और एक जातीय धार्मिक, भाषाई या जाति समूह से दूसरे में भिन्न होती हैं। एक परीक्षण

पिछड़े वर्गों की पहचान करें जो आवेदन करने पर उपयुक्त लग सकते हैं लोगों के एक समूह के लिए यह पूरी तरह से अनुचित और अनुचित हो सकता है।

यदि लोगों के किसी अन्य समूह पर लागू किया जाता है। कोई सार्वभौमिक परीक्षण नहीं हो सकता; कोई विशेष परीक्षण नहीं हो सकता; कोई निर्णायक परीक्षण नहीं हो सकता। वास्तव में, किसी भी कठोर परीक्षण को लागू करना व्यर्थ हो सकता है। स्थिति की व्यापकता और समग्रता को देखना पड़ सकता है।

जब हम अमीर वर्गों, गरीब वर्गों, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, शासक वर्ग, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वर्गों आदि की बात करते हैं तो हम आम तौर पर समझते हैं कि हमारा क्या मतलब है। कला में 'वर्ग' शब्द का उपयोग किस अर्थ में किया जाता है। 15 ( 4 ) और कला में। 16 ( 4 ) संविधान का? 'सामाजिक' और 'शैक्षिक रूप से पिछड़े' अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?

कक्षाएँ? पिछड़ेपन में क्या शामिल है? 'पिछड़ेपन', 'पिछड़े वर्गों' और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों 'का क्या अर्थ है, इस बारे में स्पष्ट स्थिति रखने के लिए हमें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि सामाजिक असमानता क्या है। मैक्स वेबर हमें सामाजिक असमानता की एक त्रि-आयामी तस्वीर देते हैं। वेबर के अनुसार, तीन आयाम वर्ग, स्थिति और शक्ति हैं। एक व्यक्ति की वर्ग-स्थिति, वेबर के अर्थ में, वह है जो वह दूसरों के साथ साझा करता है, इसी तरह रखा गया है।

उत्पादन, वितरण और विनिमय की प्रक्रिया में, एक परिभाषा

वर्ग की स्थिति जो मार्क्सवादी अवधारणा के बहुत करीब है। वर्ग की असमानता मुख्य रूप से आय की असमानता पर और कुछ हद तक ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए समान अवसर पर निर्भर करती है। इस परिभाषा के अनुसार, एक व्यक्ति का वर्ग, आर्थिक पदानुक्रम में उसकी साझा स्थिति है। स्थिति, वेबर के तीन आयामों में से दूसरा आम तौर पर खपत की शैली द्वारा निर्धारित किया जाता है, हालांकि आवश्यक रूप से आय के स्रोत या राशि से नहीं। एक गरीब अभिजात वर्ग की कभी-कभी नए अमीरों द्वारा तलाश की जाती है। एक डेस्क कर्मचारी खुद को एक शारीरिक कार्यकर्ता से बेहतर मानता है। एक डॉक्टर या वकील जैसे पेशेवर को जीवन के कई अन्य क्षेत्रों से संबंधित लोगों की तुलना में बेहतर दर्जा माना जाता है।

स्थिति के. सी. वी. कुमार वी. कन्नटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) को प्रतीत होती है।

· 399

आर. एच. टॉनी 'आय और सामाजिक स्थिति की थकाऊ अश्लीलता' के रूप में वर्णित पोशाक, भाषण, व्यवसाय, आदि सहित सामाजिक विशेषताओं और शैली पर निर्भर करता है। इसी तरह, वर्ग और स्थिति शक्ति के साथ समकालीन नहीं हैं, हालांकि शक्ति और वर्ग को अक्सर निकटता से जोड़ा जा सकता है। शक्ति में भागीदारी है निर्णय लेने की प्रक्रिया लेकिन जो लोग सत्ता का उपयोग करते हैं, उन्हें न तो सबसे अच्छा वेतन दिया जाता है और न ही सबसे सम्मानित। लेकिन, अब यह सबसे सतही पर्यवेक्षक के

लिए भी स्पष्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग अनगिनत अनदेखे तरीकों से उन लोगों द्वारा किया जाता है जो आर्थिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा बेरोकटोक हेरफेर किया जाता है। इसलिए, हम देखते हैं कि वेबर द्वारा प्रस्तावित तीन आयामों में से प्रत्येक आर्थिक स्थिति के साथ घनिष्ठ और अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हालाँकि, हम 'पिछड़ेपन' के सवाल को देखते हैं, चाहे वर्ग, स्थिति या शक्ति के दृष्टिकोण से, हम आर्थिक कारक को इन सब के सबसे नीचे पाते हैं और हम गरीबी पाते हैं,

अपराधी-कारण और प्रमुख विशेषता। गरीबी, आर्थिक माइक कारक सभी पिछड़ेपन को ब्रांड करता है जैसे कि सीधी मुद्रा होमोसेपियन्स को ब्रांड करती है और मंगल ग्रह से देखने वाले की नजर में उसे अन्य सभी जानवरों से अलग करती है। लेकिन, क्या उसका नस्लीय स्टॉक है

कॉकेशियन, मंगोलॉइड, नेग्रॉइड आदि की आगे की जांच करनी होगी। इसलिए भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आगे के सवाल की और अधिक जांच की आवश्यकता है। भारत में, यह मामला सर्वव्यापी जाति व्यवस्था, श्रेणीकरण और अवमूल्यन की एक अनूठी और विनाशकारी प्रणाली, जिसने पूरे भारतीय और आंशिक रूप से हिंदू समाज को क्षैतिज रूप से ऐसी अलग-अलग परतों में विभाजित कर दिया है, जो गतिशीलता के विनाशकारी हैं, एक ऐसी प्रणाली जिसने प्रवेश किया है और भ्रष्ट किया है, के कारण और अधिक जटिल और दयनीय रूप से अत्याचारित हो गया है।

प्रत्येक भारतीय नागरिक का मन और आत्मा। यह एक कुख्यात तथ्य है

कि ग्रामीण समाज की एक ऊपरी परत है जिसमें वरिष्ठ शामिल हैं

जातियाँ, आम तौर पर पुजारी, जमींदार और व्यापारी जातियाँ,

एक निचला स्तर है जिसमें भारतीय ग्रामीण की 'बाहरी जातियाँ' शामिल हैं।

समाज, अर्थात् अनुसूचित जातियाँ, और, उच्चतम के बीच में

और सबसे कम, जनसंख्या के बड़े वर्ग हैं जो क्योंकिजिस जाति से वे ग्रामीण क्षेत्र में संबंध रखते हैं, उसके कानून श्रेणीकरण का

पिछड़ेपन, सामाजिक और शैक्षिक, पिछड़ेपन जो रोकता है उन्हें ऊपरी के साथ पकड़ने के लिए समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने से

क्रस्ट।

जाति व्यवस्था, वर्ग या सरसरी, के बारे में कोई भी दृष्टिकोण तुरंत होगा।

आर्थिक शक्ति के साथ जाति व्यवस्था के दृढ़ संबंधों को प्रकट करें।

भूमि और शिक्षा, 400 में आर्थिक शक्ति के दो प्राथमिक स्रोत

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यम जातियों द्वारा व्यावसायिक कौशल का अभ्यास किया जाता था और अब तक प्रचलित आर्थिक प्रणाली में वे प्रणाली में रैंक कर सकते थे। केवल भूमि और विद्वान कुलीन वर्ग का गठन करने वाली जातियों के बाद। पदानुक्रम में सबसे कम जहां उन्हें सौंपा गया था

प्रतिस्थापन के बिना, कहें कि अगर गरीबी कारण है, तो जाति सामाजिक पिछड़ेपन का प्राथमिक सूचकांक है, ताकि सामाजिक पिछड़ेपन को अक्सर कम किया जा सके। किसी व्यक्ति की जाति के संदर्भ में आसानी से पहचाने जाने योग्य। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय समाज में जाति की मूल शक्ति और सर्वव्यापीता है, हालाँकि, हम इसे दूर करना चाहते हैं। दुख की बात है कि हमारे देश में जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह धर्म की बाधाओं को भी पार कर चुकी है। जाति व्यवस्था ने अन्य धार्मिक और असंतुष्ट हिंदू संप्रदायों में प्रवेश किया है, जिनके लिए जाति की प्रथा अभिशाप होनी चाहिए और आज हम पाते हैं कि अन्य धार्मिक आस्थाओं के अनुयायी और हिंदू असंतुष्ट कभी-कभी रूढ़िवादी हिंदुओं की तरह जाति प्रणाली के कठोर अनुयायी होते हैं। हम ईसाई हरिजन, ईसाई मदर, ईसाई रेड्डी, ईसाई कम्मा, मुजबी सिख आदि पाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक समुदाय है जिसे पिंजार या डुडेकुलस के नाम से जाना जाता है (जिसे उत्तर में 'रुई पिंजने वाला' के रूप में जाना जाता है): पेशेवर कपास-पीटने वाले) जो वास्तव में मुसलमान हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक हिंदू के रूप में माने जाते हैं। जाति के कई अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं।

आर्थिक पदानुक्रम में साझा स्थिति, जाति वर्गीकरण,

व्यवसाय, निवास, उपभोग की शैली, साक्षरता का स्तर और ऐसे कई अन्य कारक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की ओर जाते प्रतीत होते हैं। कुछ स्थितियों में और अक्सर मृत अवस्था में, सामाजिक अन्वेषक आसानी से एक पूरे जाति समूह को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचानने में सक्षम हो सकते हैं; वह कुछ क्षेत्रों, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तानी या वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में आसानी से पहचान सकते हैं; वह कुछ 'निम्न' क्षेत्रों का अनुसरण करने वालों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में स्वतंत्र रूप से समझ सकते हैं: वह बिना किसी कठिनाई के, बहुत गरीब और बेसहारा लोगों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) के रूप में अलग कर सकता है।

पिछड़े वर्ग। सामाजिक अन्वेषक यह सब क्षेत्र द्वारा करने में सक्षम हो सकता है-अनुसंधान, अध्ययन, अवलोकन, संग्रह और व्याख्या।

डेटा का, सामान्य का अनुप्रयोग हालांकि कठोर मानक नहीं। हम अपने निर्णय में बाद में प्रश्न के इन पहलुओं का उल्लेख करेंगे।

इन प्रारंभिक, सामान्य टिप्पणियों के साथ, अब हम उल्लेख कर सकते हैं

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के लिए। संविधान का भाग XVI "कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों" से संबंधित है। जिन वर्गों के बारे में संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान करना उचित समझा, वे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो-इंडियन समुदाय और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

अनुच्छेद 330 और 332 योजना के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

जनता के सदन और राज्य की विधानसभाओं में जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शासित किया। अनुच्छेद 331 और 333 में लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 में प्रावधान है कि आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व 30 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। लोक सभा या राज्य की विधानसभाओं में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण या विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है।

अनुच्छेद 335 एक संवैधानिक दायित्व को लागू करता है

संघ या राज्यों के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ विचार करना। अनुच्छेद 336 और 337 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुछ सेवाओं में और उस समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य (राज्यपाल के परामर्श के बाद) या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जो संविधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना को किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाना है, लेकिन केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में इसी तरह के प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को एक आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार देता है।

सामाजिक और शैक्षिक 402 की स्थितियों की जांच करने के लिए सायन

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एससी. आर.

भारत के क्षेत्र के भीतर पिछड़े वर्गों और उन कठिनाइयों के बारे में जिनके तहत वे काम करते हैं और उन कदमों के बारे में सिफारिशें करना जो संघ द्वारा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए उठाए जाने चाहिए और अनुदान के बारे में जो चाहिए

उस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य द्वारा किया जाए। आयोग की रिपोर्ट जो तथ्यों को निर्धारित करने और बनाने के लिए हैसिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता होती है, साथ ही उस पर की गई कार्रवाई के बारे में एक ज्ञापन भी दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 338 एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का आदेश देता है

राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति जिनका कर्तव्य अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना है

और संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को और राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने वाले अंतरालों पर उन सुरक्षा उपायों के काम करने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी है। अनुच्छेद 338 (3) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है। 338 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संदर्भों का अर्थ ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भों को शामिल करने के रूप में किया जाएगा जो राष्ट्रपति अनुच्छेद के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने पर कर सकते हैं। 340 ( 1 ) . एंग्लो-इंडियन समुदाय को भी निर्दिष्ट करें।

इस प्रकार, जबकि सीटों के आरक्षण के लिए एक विशेष प्रावधान है

लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए और लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए, लोकसभा में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण या आरक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

राज्यों के लोग या विधानसभाएँ। फिर से, जबकि कला के तहत। 335 , संघ और राज्यों के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार करने का एक संवैधानिक दायित्व है और कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए एक सीमित अवधि के लिए एक विशेष प्रावधान है। सामाजिक और सामाजिक रूप से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। लेकिन कला के तहत एक प्रावधान है। 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए संविधान

कक्षाएं और ऐसी स्थितियों में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए, के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

403

संविधान का अनुच्छेद 14, सकारात्मक भाषा में कहा गया है,

प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, अनुच्छेद 15 (1) राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। इसी तरह अनुच्छेद 22 (2) केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार करने या राज्य के धन से सहायता प्राप्त करने पर रोक लगाता है। जबकि कला। 15 ( 3 )

कहते हैं कि कला में कुछ भी नहीं है। 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से रोकेगा। 15 ( 4 ) "इस अनुच्छेद में या कला के खंड (2) में कुछ भी नहीं है। 29 नागरिकों के किसी भी सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य को उन्नति करने और विशेष प्रावधान करने से रोकेगा। कला. 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। कला. 16 ( 1 ) यह उपबंध करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता होगी। 16 ( 2 )

केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। कला. 16 ( 4 ) राज्य कहते हैं, "इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा

नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान, जो राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है। हम मुख्य रूप से इस मामले में क्वेस्टन के साथ चिंतित हैं कि कौन हैं

कला. 15 ( 4 ) और नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि नहीं कला में उल्लिखित राज्य के तहत सेवाओं में भेजा गया। 16 ( 4 ) .

हम इसे आर्ट के दौरान देखते हैं। 15 ( 4 ) किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान पर विचार करता है। नागरिकों का या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुच्छेद। 16 ( 4 ) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के प्रावधान की बात करता है, जो

राज्य के अधीन सेवाओं में राज्य की राय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है "-अब, यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि नागरिकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनसे उन्नति के लिए विशेष प्रावधान पर अनुच्छेद द्वारा विचार किया गया है। 15 ( 4 ) नागरिकों के पिछले वार्ड वर्गों से अलग और अलग हैं जो पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं

राज्य के अधीन सेवाएँ जिनके लिए पदों का आरक्षण और नियुक्ति कला द्वारा विचारों पर विचार किया जाता है। 16 ( 4 ) . नागरिकों के पिछड़े वर्गों का उल्लेख कला में किया गया है। 16 ( 4 ) , संक्षिप्त विवरण के बावजूद, वही सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एसयूपीएल हैं।

एस सी आर।

404'नागरिकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' के रूप में, कला में पूरी तरह से वर्णित है। 15 ( 4 ) : त्रिलोकीनाथ टिकू बनाम। जम्मू और काशीमीर राज्य और अन्य मामले। हालाँकि, कला के उद्देश्यों के लिए। 16 ( 4 ) यह और भी आवश्यक है कि पिछड़े वर्ग में पर्याप्त नहीं होना चाहिए

सेवाएँ। फिर से, और स्पष्ट रूप से, 'अग्रिम के लिए विशेष प्रावधान' एक व्यापक व्याख्या है और इसमें कई और चीजें शामिल हो सकती हैं।

संबंध, छात्रवृत्ति, मुफ्त परिवहन, रियायती या मुफ्त आवास, अन्य वर्गों के मामले में आवश्यकताओं से छूट आदि। हम, अभी के लिए, कॉलेजों में सीटों के आरक्षण के अलावा, प्रगति के तरीके से चिंतित नहीं हैं। हम कला के तहत इसका पालन करते हैं। 16 ( 4 ) , उन पिछड़े वर्गों को लाभान्वित करने के लिए आरक्षण दिया जाना है, जो सरकार की राय में हैं

सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं। आरक्षण का उद्देश्य, सबसे पहले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल करना होना चाहिए। इसका पालन करना चाहिए कि आरक्षण की सीमा पुनः आरक्षण की अपर्याप्तता से मेल खाती होनी चाहिए।

प्रस्तुति। ऐसा कोई कारण नहीं है कि संविधान द्वारा प्रस्तुत इस दिशानिर्देश को भी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नहीं अपनाया जाना चाहिए:

कला. 15 ( 4 ) भी। उदाहरण के लिए, पेशेवर कॉलेजों में सीटों के आरक्षण की सीमा को विभिन्न व्यवसायों में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संदर्भ में आसानी से निर्धारित किया जा सकता है।

इसी तरह, अन्य कॉलेजों में आरक्षण की सीमा स्नातकों आदि की संख्या में अपर्याप्तता के संदर्भ में मन को विचलित कर सकती है। स्वाभाविक रूप से, यदि खोए हुए आधार को प्राप्त करना है, तो आरक्षण की सीमा प्रतिशत से थोड़ी अधिक भी हो सकती है।

पिछड़े वर्गों की जनसंख्या।

चूँकि ये प्रश्न पूरी तरह से समाकलन नहीं हैं, इसलिए यह होगा

इस न्यायालय के पहले के कुछ विचारों को संदर्भित करने के लिए उपयोगी है

इस सवाल पर।

थॉमस (1) के दृश्य पर आने तक, बालाजी (1) को कई लोगों द्वारा आरक्षण पर महान कृति माना जाता था। बालाजी भी एक मामला था।

कारंतका से। एक गजेन के फैसले का पहला वाक्य

जे. द्रगडकर, यह उस निराशाजनक कार्य का रहस्योद्घाटन है जो कर्नाटक की सरकार पिछले कई वर्षों से कर रही है। पहला वाक्य कहता है: " 1958 से, मैसूर राज्य रहा है

( 1 ) [ 1976 ] 1 एससीआर 906। ( 2 ) [ 1963 ] एसएनपीपीएल।



मैसूर राज्य में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कला के तहत एक विशेष प्रावधान करने का प्रयास करना। 15 ( 4 ) संविधान और हर बार जब उस ओर से कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसकी वैधता को रिट कार्यवाही द्वारा चुनौती दी गई है। उस ओर से पारित चार पिछले आदेशों को अनुच्छेद के तहत राज्य के खिलाफ की गई रिट कार्यवाही द्वारा चुनौती दी गई थी। 226 " . बालाजी कला के तहत किए गए आरक्षण की वैधता के सवाल से चिंतित थे। 15 ( 4 ) मैसूर और कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में संविधान

विश्वविद्यालय। 28 प्रतिशत सीटें तथाकथित पिछड़े वर्गों के लिए, 20 प्रतिशत अधिक पिछड़े वर्गों के लिए, 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं, जिससे कुल 58 प्रतिशत सीटें केवल आरक्षित श्रेणी के लिए और 32 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध थीं, जिन्हें निर्णय में "योग्यता पूल" के रूप में वर्णित किया गया था। आरक्षण आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नागन गौड़ा समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था। अदालत ने पाया कि समिति ने इन सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना और वर्गीकरण करने की समस्या का इस आधार पर समाधान किया कि सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय काफी हद तक उस जाति पर निर्भर करते हैं जिससे वे संबंधित हैं, हालांकि इसने माना कि आर्थिक स्थिति एक योगदान कारक हो सकती है। अदालत के अनुसार, समिति ने वस्तुतः 'वर्गों' की तुलना जातियों से की। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान

इस सवाल के साथ कि क्या नागरिकों का कोई वर्ग सामाजिक थापिछड़े हों या न हों, जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है

उक्त नागरिक लेकिन जाति का महत्व कम नहीं होना चाहिए

टेड। यह देखा गया कि जाति को एकमात्र नहीं बनाया जा सकता है या

नागरिकों के वर्ग। यह ध्यान दिया गया कि सामाजिक पिछड़ेपन में थाबहुत हद तक गरीबी के परिणाम का अंतिम विश्लेषण। यह था।

यह भी देखा कि नागरिकों का व्यवसाय भी योगदान कर सकता है

नागरिकों के वर्गों को सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाना। नागम गौड़ा के रूप में

समिति ने जाति परीक्षण को प्रमुख परीक्षण के रूप में अपनाया था, यदि नहीं

एकमात्र परीक्षण, अन्य कारकों की परवाह किए बिना जो एक थे

संदिग्ध रूप से प्रासंगिक, अदालत ने वर्गीकरण के बारे में विचार व्यक्त किया

सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की समिति द्वारा बनाई गई

अमान्य है। गुजरते हुए, एक स्थान पर, यह टिप्पणी की गई कि पिछड़े

नागरिकों के वर्ग जिनके लिए विशेष प्रावधान अधिकृत किया गया थाबनाया गया, कला द्वारा इलाज किया गया। 15 ( 4 ) स्वयं, शेदु के समान होने के रूप में

जातियों और जनजातियों का नेतृत्व किया। यह देखा गया कि पिछड़े वर्ग

अनुसूचित की तुलना में अपने पिछड़ेपन के मामलों में थे

जातियाँ और जनजातियाँ। इन टिप्पणियों और जुक्सा [1985] एस. यू. पी. पी. एल. के आधार पर।

एस सी आर।

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिव्यक्तियों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

कला में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। 15 और कला। 338 ,

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह सुझाव दिया था किसामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग वे थे जिनकी स्थिति और

जाति और अनुसूचित जनजाति। हम नहीं सोचते कि ये अवलोकनराज्य किसी भी प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए थे कि सामाजिक रूप से

पिछड़े वर्ग लोगों के वे वर्ग थे, जिनकी परिस्थितियाँ

जनजातियाँ। हम ऐसा पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि आवेदन करना अनुचित है। संविधान की व्याख्या करने के लिए वैधानिक व्याख्याओं के सामान्य नियम

राष्ट्रीय उपकरण जो सुई जेनेरी हैं और जो महत्व और परिणाम की स्थितियों से संबंधित हैं। यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है

मार्शलियन जागरूकता कि हम एक संविधान की व्याख्या कर रहे हैं; हम

यह भी याद रखना चाहिए कि हम बीसवीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुए संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की, जो संवैधानिक उपकरणों, घटनाओं और अन्य क्रांतियों से प्रभावित है।

जहाँ, एक बेहतर दुनिया की तलाश में, और सभी के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के विचार की ओर बढ़े। इस तरह के संविधान को एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उसके सभी नागरिकों को उसके द्वारा वादा किए गए न्याय का पूरा पैमाना मिल सके। संविधान के व्याख्याताओं को केवल शब्दों और व्यवस्था के बारे में कम सोचना चाहिए।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और संविधान के अन्य प्रावधानों में हमारे मार्गदर्शन के लिए संविधान के दर्शन और प्रचलित 'भावना और भावना' की तुलना में शब्दों का इतना विस्तार से खुलासा किया गया है। अब, भारत में ग्रामीण परिदृश्य से परिचित कोई भी व्यक्ति तुरंत इस स्थिति को पहचान लेगा कि अनुसूचित जातियां एक विशेष रूप से अपमानित स्थिति में हैं और उनके साथ जाति के व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि बहिष्कृत लोगों के रूप में व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि अन्य स्वीकार्य रूप से पिछड़े वर्ग भी उनसे दूर रहते हैं और उन्हें हीन प्राणी मानते हैं। यह उनके विशेष अपमान के कारण था कि संविधान को ही उनके लिए विशेष प्रावधान करने के लिए आगे आना पड़ा। अनुसूचित जातियों के अस्तित्व की स्थितियों के निकटता की कसौटी को लागू करके अन्य वर्गों के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने का प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह का परीक्षण व्यावहारिक रूप से सामाजिक और सामाजिक रूप से आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर देगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इस तरह की परीक्षा मौजूदा उच्च वर्गों के प्रभुत्व को कायम रखेगी। इस तरह की परीक्षा उच्च वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच के अधिकांश वर्गों को पिछड़े वर्गों की श्रेणी से बाहर ले जाएगी और उन्हें स्थायी रूप से नुकसान में डाल देगी। निकाय के केवल 'प्रबुद्ध' वर्ग ही सभी 'खुले' पदों और सीटों और आरक्षित पदों और 407 पर कब्जा करेंगे।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों और उन लोगों को मिलेंगी जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बहुत करीब हैं। 'प्रबुद्ध' वर्गों के पीछे और निकट अनुसूचित जातियों और जनजातियों से आगे रहने वालों का बड़ा हिस्सा ऊँचा और सूखा छोड़ दिया जाएगा, जिसमें कभी भी खुद को थोपने का मौका नहीं होगा।

इससे पहले हमने उल्लेख किया था कि न्यायालय द्वारा गरीबी को सामाजिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण माना जाता था। पृष्ठ 460 पर कहा गया था, "सामाजिक पिछड़ेपन का अंतिम विश्लेषण गरीबी का परिणाम है, बहुत बड़े पैमाने पर। नागरिकों के वर्ग जो दयनीय रूप से गरीब हैं, वे अपने आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं। उन्हें समाज में कोई दर्जा नहीं मिलता है और इसलिए, उन्हें पीछे की सीट लेने के लिए संतुष्ट होना पड़ता है। यह सच है कि गरीबी के परिणामस्वरूप होने वाले सामाजिक पिछड़ेपन की जाति के विचारों से वृद्धि होने की संभावना है, जिससे गरीब नागरिक संबंधित हो सकते हैं, लेकिन यह केवल नागरिकों के पिछड़ेपन को निर्धारित करने में जाति और गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। हम केवल यह जोड़ते हैं कि दोनों के बीच एक प्रबल पारस्परिकता है।

भारतीय परिदृश्य पर गरीबी और जाति। फिर से, वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई कुछ योजनाओं का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा, "हालांकि, हम देख सकते हैं कि यदि कोई राज्य इस तरह के उपाय को अपनाता है, तो वह राज्य में पिछड़े वर्गों को राहत दे सकता है और उनकी प्रगति में सहायता कर सकता है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन अंततः और मुख्य रूप से गरीबी के कारण है।" सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बुराई के वास्तविक स्रोत के रूप में गरीबी और पिछड़ेपन को निर्धारित करने में एक प्रासंगिक कारक के रूप में जाति को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने व्यवसाय और निवास को दो अन्य महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारकों के रूप में भी देखा और अंत में एक गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा गया था,

" नागरिकों के व्यवसाय भी नागरिकों के वर्गों को सामाजिक रूप से पिछड़े बनाने में योगदान दे सकते हैं। वहाँ हैं।

कुछ व्यवसाय जिन्हें पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हीन माना जाता है और इन व्यवसायों का पालन करने वाले नागरिकों के वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े होने के योग्य हैं। निवास का स्थान भी व्यक्तियों के समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने में एक छोटी भूमिका नहीं निभाता है। एक मायने में, सामाजिक पिछड़ेपन की समस्या ग्रामीण भारत का दोष है और इस संबंध में, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े स्थान पर रहने वाले नागरिकों के वर्ग कला के दायरे में आते हैं। 15 ( 4 ) . खनन रोकने की समस्या जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, निस्संदेह बहुत जटिल है। इस समस्या और [1985] एस. यू. पी. पी. एल. को हल करने में समाजशास्त्रीय, सामाजिक और आर्थिक भावनाओं का उपहास किया जाता है।

एस सी आर।

408

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उचित मानदंड तैयार करना स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए विस्तृत जांच और आंकड़ों के संग्रह और उक्त आंकड़ों की तर्कसंगत और वैज्ञानिक रूप से जांच करने की आवश्यकता होगी।

रास्ता "।

इसके बाद बालाजी अदालत ने शैक्षिक पिछड़ेपन के सवाल पर विचार करना शुरू किया। नागन गौड़ा समिति ने उस समुदाय के एक हजार नागरिकों के संबंध में राज्य के सभी उच्च विद्यालयों की पिछली तीन उच्च विद्यालय कक्षाओं में छात्र जनसंख्या के औसत के आधार पर इस प्रश्न से निपटा था। समिति का विचार था कि जिन जातियों का औसत राज्य के औसत से कम है, उन्हें पिछड़ा समुदाय माना जाना चाहिए और जिनका औसत राज्य के औसत के 50 प्रतिशत से कम है, उन्हें अधिक पिछड़ा माना जाना चाहिए। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पिछली तीन उच्च विद्यालय कक्षाओं की परीक्षा को अपनाना थोड़ा अधिक हो सकता है। लेकिन भले ही इसे उच्च नहीं माना जाता था, लेकिन राज्य के औसत से कुछ ही नीचे के समुदायों के साथ पिछड़े के रूप में व्यवहार करना सही नहीं था। इस सवाल पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। जहां राज्य का औसत अपने आप में बहुत कम है, वहां ऐसे लोगों के वर्गों को बाहर रखने का कोई कारण नहीं है, जिनका औसत राज्य के औसत से थोड़ा ऊपर या बहुत करीब या उससे थोड़ा नीचे था।

पिछड़े वर्गों की सूची से। राज्य के औसत या राज्य के औसत परीक्षण के 50 प्रतिशत को अपनाने से काफी मनमाने परिणाम मिल सकते हैं और यह निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं हो सकता है जिसमें अदालत को अपने विचार थोपने का प्रयास करना चाहिए।

वास्तव में निरीक्षण करते हुए: " यदि परीक्षा को राज्य की छात्र आबादी के औसत के संदर्भ में लागू किया जाना है, तो वैध दृष्टिकोण यह होगा कि नागरिकों के वर्ग, जिनका औसत राज्य के औसत से काफी या काफी कम है, उन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जा सकता है ", अदालत ने यह भी कहा, 'इस बिंदु पर फिर से हम कोई कठोर और तेज नियम निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं; यह राज्य पर है कि वह मामले पर विचार करे और उस तरीके से निर्णय ले जो कला की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। 15 ( 4 ) ” . बालाजी में यह भी देखा गया था कि पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण आदेश द्वारा उप-वर्गीकरण किया गया था।

वार्ड वर्ग कला के तहत उचित नहीं प्रतीत होते थे। 15 ( 4 ) क्योंकि यह राज्य में सबसे उन्नत वर्गों की तुलना में कम उन्नत नागरिकों के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए तैयार किया गया एक उपाय प्रतीत होता है, और यह कला का दायरा नहीं था। 15 ( 4 ) . उप-वर्गीकरण का परिणाम यह हुआ कि लगभग 90 प्रतिशत के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) 409

राज्य की आबादी को पिछड़े माना जाता था। इस तरह के पाठ्यक्रम के औचित्य पर प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि सिद्धांत रूप में वर्गीकरण क्यों नहीं किया जा सकता है ।पिछड़े वर्गों और अधिक पिछड़े वर्गों में, यदि दोनों वर्ग केवल थोड़े पीछे नहीं हैं, बल्कि सबसे बहुत पीछे हैं

उन्नत कक्षाएँ। वास्तव में अधिक पिछड़े वर्गों की मदद के लिए इस तरह का वर्गीकरण आवश्यक होगा; अन्यथा पिछड़े वर्गों के जो अधिक पिछड़े वर्ग की तुलना में थोड़े अधिक उन्नत हो सकते हैं, वे सभी सीटों के साथ चले जा सकते हैं, जैसे कि यदि आरक्षण अधिक पिछड़े वर्गों तक ही सीमित था और थोड़ा अधिक उन्नत पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, तो सबसे उन्नत वर्ग सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध सभी सीटों के साथ चले जाएंगे और पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ेंगे। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि उप-वर्गीकरण की अनुमति हो सकती है यदि ऐसे लोगों के वर्ग हैं जो निश्चित रूप से उन्नत वर्गों से बहुत पीछे हैं। लेकिन बहुत पिछड़े वर्गों से आगे।

औसत को अपनाने के बारे में भी यही बात कही जा सकती है

सापेक्ष पिछड़ेपन का आकलन करने के आधार के रूप में उस समुदाय के एक हजार नागरिकों के संबंध में राज्य के सभी उच्च विद्यालयों की अंतिम तीन उच्च विद्यालय कक्षाओं में छात्रों की संख्या। बालाजी ने सोचा कि यह थोड़ा अधिक था लेकिन निश्चित रूप से अन्य विचार संभव हैं। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रसार को देखते हुए, कोई भी सोच सकता है कि आधार को और ऊपर उठाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पिछड़े वर्गों के अधिक से अधिक लड़के साक्षर हो सकते हैं। लेकिन यह लंबा है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े होने से बचने का रास्ता। जैसे-जैसे कोई वर्ग दर वर्ग ऊपर जाता है, यह एक कुख्यात तथ्य है कि पिछड़े वर्ग के लड़कों में आगे के लड़के की तुलना में अधिक 'ड्रॉप-आउट' होते हैं।

कक्षाएँ। शैक्षिक बैक वार्डनेस का आकलन करने के लिए कम आधार को अपनाना पूरी तरह से गलत तस्वीर दे सकता है। आखिरकार, अगर कोई पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश का सवाल उठा रहा है या

पदों पर नियुक्ति, आधार संभवतः उस समुदाय के छात्रों की औसत संख्या होनी चाहिए जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है, और शायद उस समुदाय के व्यक्तियों की औसत संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में स्नातक किया है, क्योंकि स्नातक आमतौर पर अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम योग्यता है, आरक्षण की सीमा पद के वर्ग के संदर्भ में भी भिन्न हो सकती है। यह एक मुद्दा है

विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन।

बालाजी अदालत ने तब इस सवाल पर विचार किया कि किस हद तक

विशेष प्रावधान जो राज्य कला के तहत करने के लिए सक्षम होगा। 15 ( 4 ) . यहाँ न्यायालय तथाकथित योग्यता सिद्धांत लाया और सोचा कि बड़ा आरक्षण अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा।

दक्षता। हम शायद यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने क्या कहा था: इसलिए प्रमुख आरक्षण विरोधी अपने अभियानों के लिए राष्ट्रीयकरण खोजने के लिए हाथ से। एक पसंदीदा है कन्ज्योर करना।

नकली संयोजन की छवि ऊपर; एक तरफ खुली सूची में उम्मीदवारों द्वारा दिखाई गई 'योग्यता' है, दूसरी तरफ 'अक्षमता' है, जिसका प्रतिनिधित्व बी आरक्षित सूची में है इसलिए-इसलिए तर्क

40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक मनमाना होगा और संविधान हमें मनमाना होने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि बालाजी मामले में, अदालत ने सोचा कि आम तौर पर और व्यापक रूप से एक विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए, और 50 प्रतिशत से कितना कम प्रत्येक मामले में प्रासंगिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, अदालत ने स्वीकार किया। इस मामले मेंएक बार फिर, हम निश्चित रूप से यह कहने के लिए अनिच्छुक हैं कि एक उचित समर्थक दृष्टि क्या होगी। अदालत अंततः इतना ही कहेगी कि उनके समक्ष मामले की परिस्थितियों में, 68 प्रतिशत का आरक्षण कला के साथ असंगत था। 15 ( 4 ) संविधान से। हम बालाजी को आरक्षण की बाहरी सीमा के रूप में मनमाने ढंग से 50 प्रतिशत निर्धारित करने के रूप में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। बालाजी द्वारा जो सटीक निर्णय लिया गया था, उसका सारांश स्वयं न्यायालय ने एस. सी. आर. के पृष्ठ 471 में दिया है।

निम्नलिखित शब्द:

( 1 ) रूथ ग्लास: भारत के दलित लोगों को विभाजित और अपमानित किया, (मासिक समीक्षा जुलाई-अगस्त) 1982।



" हम पहले ही देख चुके हैं कि वर्तमान में आक्षेपित आदेश

इस मामले में पिछड़े वर्गों को केवल जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसकी हमारी राय में, कला द्वारा अनुमति नहीं है। 15 ( 4 ) : और हमारे पास

यह भी माना गया कि विवादित आदेश द्वारा दिया गया 68 प्रतिशत का आरक्षण स्पष्ट रूप से कला द्वारा अधिकृत विशेष प्रावधान की अवधारणा के साथ असंगत है। 15 ( 4 ) . इसलिए, यह इस प्रकार है कि आक्षेपित

आदेश अनुच्छेद द्वारा राज्य को प्रदत्त संवैधानिक शक्ति के साथ धोखाधड़ी है। 15 ( 4 ) " .

जो हम पहले कह चुके हैं, उसे हमें यहाँ दोहराना चाहिए कि

कोई वैज्ञानिक सांख्यिकीय डेटा या विशेषज्ञ प्रशासकों का सबूत नहीं जो इस राय का समर्थन करने के लिए समस्या का कोई अध्ययन किया है कि

50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दक्षता को प्रभावित कर सकता है। यह एक

अंगूठे का नियम और अंगूठे के नियम न्यायाधीशों को निर्धारित करने के लिए नहीं हैं

जटिल सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना।

कभी-कभी, यह तिरछा सुझाव दिया जाता है कि अत्यधिक आरक्षण

केवल वोट डालने के उपकरण के रूप में शामिल किया गया। शायद ऐसा है, शायद नहीं।

कोई केवल यह कह सकता है कि 'बुराई से अच्छा आता है' और जल्दी से सुधार होता है।

उत्पीड़ित वर्गों की स्थिति, राष्ट्र के लिए उतनी ही बेहतर होगी।

हमारी टिप्पणियों का उद्देश्य वास्तविक होने का द्वार दिखाना नहीं है।

दक्षता। दक्षता एक मार्गदर्शक कारक होना चाहिए लेकिन धूम्रपान नहीं।

क्रीम। न्यायालय वैध रूप से केवल इतना ही कह सकता है कि आरक्षण हो सकता है

अति न करें। हो सकता है कि यह इतना अधिक न हो कि दमनकारी हो;

हो सकता है कि यह इतना अधिक न हो कि अनुचित होने की आवश्यक धारणा की ओर ले जाए

बाकी सभी का बहिष्कार।

आर. चिरालेखा बनाम। मैसूर राज्य, (1) उच्चतम न्यायालय

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

आर्थिक स्थिति और अधिभोग के आधार पर बनाया गया, बिना

जाति का संदर्भ। सरकारी आदेश के अनुसार, एक परिवार

जिनकी आय रु। 1200 प्रति वर्ष या उससे कम और व्यक्ति या

कृषि के व्यवसायों के बाद के वर्ग छोटे व्यवसाय, अंतर्विरोधी सेवाएँ, शिल्प या शारीरिक श्रम से जुड़े अन्य व्यवसाय, थे

सामान्य रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। सरकार ने

निम्नलिखित व्यवसायों को सामाजिक पिछड़ेपन में योगदान के रूप में सूचीबद्ध किया गया

नेस; (1) वास्तविक कृषक; (2) कारीगर; (3) निम्न सेवाएँ (अर्थात। वर्ग IV सरकारी सेवाओं में और संबंधित वर्ग या सेवा में

आकस्मिक श्रम सहित निजी रोजगार और (4) कोई अन्य

शारीरिक श्रम से युक्त व्यवसाय। इस मानदंड को अपनाया गया था

सरकार एक अस्थायी उपाय के रूप में आगे विस्तृत रूप से लंबित है

अध्ययन करते हैं। आदेश को एक मानदंड के रूप में नहीं लिया गया था

किसी आवेदक की जाति का पिछड़ेपन। बालाजी पर पूरा भरोसा करते हुए,

( 1 ) [ 1964 ] 6 एस सी आर 368.



मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई योजना सबसे अपूर्ण थी क्योंकि उनकी राय में व्यवसाय और गरीबी परीक्षणों के अलावा, अध्ययन को वर्गीकरण करने में जाति परीक्षण के साथ-साथ "निवास" परीक्षण को भी अपनाना चाहिए था। इसने यह भी कहा कि बालाजी मामले में निर्णय में कहा गया है कि जाति का आधार निस्संदेह एक प्रासंगिक था, न कि पिछड़े हिंदुओं के वर्गों के खनन को रोकने में एक महत्वपूर्ण आधार था, लेकिन इसे एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। जे. सुब्बा राव ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए बताया कि कैसे मैसूर उच्च न्यायालय ने बालाजी को गलत समझा और कहा:

" जबकि इस न्यायालय ने कहा कि जाति केवल एक प्रासंगिक बात है

परिस्थिति और यह कि यह प्रमुख परीक्षण नहीं हो सकता है

नागरिकों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाना, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारण में एक महत्वपूर्ण आधार है

पिछड़े हिंदुओं का वर्ग और सरकार

जाति को एक परीक्षा के रूप में अपनाया जाना चाहिए था। के रूप में

संबंधित प्राधिकारी के मन में कुछ भ्रम के लिएजिसे निर्धारित करने का कर्तव्य सौंपा जा सकता है

सिटी के वर्गों के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए नियम

कला के अर्थ के भीतर ज़ेंस। 15 ( 4 ) संविधान का,

हम यह स्पष्ट करने के लिए जल्दी करेंगे कि जाति केवल एक है

एक वर्ग और इस न्यायालय के फैसले में कुछ भी नहीं हैजो संबंधित प्राधिकारी को निर्णय लेने से रोकता है

नागरिकों के एक समूह के सामाजिक पिछड़ेपन को शामिल करना यदि यह कर सकता है

जाति के संदर्भ के बिना ऐसा करें। जबकि इस न्यायालय नेपिछड़ेपन का पता लगाने से जाति को बाहर नहीं किया गया

नागरिकों का एक वर्ग, इसने इसे मजबूरों में से एक नहीं बनाया है

के निर्धारण के लिए एक आधार प्रदान करने वाली परिस्थितियाँ

एक वर्ग का पिछड़ेपन। इसे अलग तरह से रखने के लिए, एयू

संबंधित थोरिट जाति को ध्यान में रख सकता है व्यक्तियों के एक समूह के पिछड़ेपन का पता लगाना; लेकिन,

यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका आदेश उस कारण से खराब नहीं होगा,

यदि यह किसी व्यक्ति के समूह के पिछड़ेपन का पता लगा सकता हैअन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर।

बाद में उन्होंने आगे व्याख्या की:

" यह व्याख्या इरादे को पूरा करेगी

उपरोक्त अनुच्छेद में व्यक्त संविधान। यह. बढ़ावा देने के बजाय वास्तव में पिछड़े वर्गों की मदद करता है

व्यक्तियों या समूहों के हित जो, हालांकि वे के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) हैं।

अधिकांश लोग एक विशेष जाति से संबंधित हैं, जहाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग वास्तव में एक वर्ग से संबंधित हैं। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत है। सचित्र करने के लिए

दर, राज्य में एक जाति लें जो संख्यात्मक रूप से

उसमें सबसे बड़ा। ऐसा हो सकता है कि उस जाति के अधिकांश लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे हैं। वार्ड, एक प्रभावी अल्पसंख्यक सामाजिक और शैक्षिक हो सकता है

किसी अन्य छोटी उप-जाति की तुलना में अधिक उन्नत जाति के लिए, जिनकी कुल संख्या उक्त जाति की तुलना में बहुत कम है। अल्पसंख्यक। यदि हम "वर्ग" अभिव्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं

" अन्यथा, संविधान का उद्देश्य निराश हो जाएगा और जो लोग किसी भी विज्ञापन सहायता के लायक नहीं हैं, वे इसे उन लोगों के बहिष्कार के लिए प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में योग्य हैं।

यह विसंगति तब पैदा नहीं होगी जब जाति की बराबरी नहीं की जाएगी।

वर्ग के साथ, जाति को केवल एक विचार के रूप में लिया जाता है

यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का है

क्लास हो या न हो। दूसरी ओर, यदि पूरी उप-जाति, बड़े पैमाने पर, पिछड़ी हुई है, तो उचित प्रक्रिया का पालन करके इसे अनुसूचित जातियों में शामिल किया जा सकता है।

संविधान द्वारा निर्धारित "।

कठिनाई को धीरे-धीरे पहचानना-सी द्वारा किसी भी प्रयास को निर्धारित करना

लचीले मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने बताया:

' हम कोई भी कठोर नियम निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं।

सरकार का पालन करने के लिए। की स्थापना

एक वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए मानदंड एक जटिल समस्या है जो कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में और यहां तक कि एक राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भिन्न हो सकती है। लेकिन हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में

" "वर्ग" को "जाति" के बराबर माना जा सकता है, हालांकि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की जाति पर विचार किया जा सकता है।

उसे एक पार्टी कुलर वर्ग में रखने में अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि यदि किसी स्थिति में कला के अर्थ के भीतर किसी वर्ग का निर्धारण करने में जाति को बाहर रखा जाता है। 15 ( 4 ) संविधान के अनुसार, यह वर्गीकरण को दूषित नहीं करता है यदि यह अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करता है।

राजेंद्रन बनाम। मद्रास राज्य (1) रामास्वामी, जे. ने एस की देखभाल की

( 1 ) [ 1968 ] 1 एससीआर 721।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस.

........यदि विचाराधीन आरक्षण आधारित था

केवल जाति पर और विचाराधीन जाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में नहीं रखते हुए, यह

यह कला का उल्लंघन होगा। 15 ( 1 ) . लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है तो ऐसी जाति के पक्ष में इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है कि वह कला के अर्थ में नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। 15 ( 4 ) ...... यह सच है कि वर्तमान मामलों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची जाति द्वारा निर्दिष्ट की गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जाति ही एकमात्र विचार था और इन जातियों से संबंधित व्यक्ति भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों का वर्ग नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में v. पी. सागर, (1) शाह, जे. ने कहा

" जिस संदर्भ में यह अभिव्यक्ति होती है

चाहे कोई विशेष वर्ग एक वर्ग बनाता हो, जाति को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी वर्ग के निर्धारण में केवल जाति या समुदाय पर आधारित परीक्षा को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समाज के कमजोर वर्गों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण अपनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि योग्य और योग्य उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा में प्रवेश से बाहर न रखा जाए

संस्थाएं। पिछड़ेपन का निर्धारण करने का मानदंड केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित नहीं होना चाहिए और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का होना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन के समान होना चाहिए।

पीड़ा होती है। "

( 1 ) [ 1998 ] 3 एससीआर 595।



तिरलोकी नाथ बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य, (1) न्यायालय ने फैसला सुनाया

यह कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के पुनर्निर्धारण का प्रावधान करना राज्य के लिए खुला था, लेकिन वह समुदाय या स्थान या निवास के आधार पर पदों या नियुक्तियों की संख्या का वितरण नहीं कर सकता था। जम्मू और कश्मीर सरकार के एक आदेश में कश्मीर (पूरे राज्य) के मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत, जम्मू हिंदुओं के लिए 40 प्रतिशत और कश्मीरी हिंदुओं के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित किया गया था। यह इंगित किया गया था कि अभिव्यक्ति

" पिछड़े वर्ग का उपयोग पिछड़ी जाति या पिछड़े समुदाय के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता था, लेकिन यह देखा गया कि "एक पूरी जाति या समुदाय के सदस्य एक निश्चित समय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हो सकते हैं और इस कारण से उन्हें पिछड़े वर्ग के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि

वे एक जाति या समुदाय के सदस्य हैं, लेकिन क्योंकि वे गठन करते हैं

एक वर्ग "। अदालत ने आगे कहा:

" अपने सामान्य अर्थ में अभिव्यक्ति "वर्ग"

इसका अर्थ है लोगों का एक सजातीय वर्ग

कुछ समानताओं या सामान्य लक्षणों के कारण, और जिन्हें कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है जैसे कि

स्थिति, पद, व्यवसाय, एक इलाके में निवास, जाति के रूप में,

धर्म और इसी तरह। लेकिन कला के उद्देश्य के लिए। 16 ( 4 )

यह निर्धारित करने में कि क्या एक खंड एक वर्ग, एक परीक्षण बनाता है केवल जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर

प्रतिशत, जन्म या निवास स्थान को अपनाया नहीं जा सकता है,

क्योंकि यह सीधे संविधान का उल्लंघन करेगा "।

ए. पीरियाकाट्टुप्पन बनाम। तमिलनाडु राज्य, (1) न्यायालय

परेशान:

" एक जाति को हमेशा एक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है।

इस तथ्य को कहने में कोई लाभ नहीं है कि संख्याएँ हैं इस देश में असभ्य जातियाँ जो सामाजिक और शैक्षिक हैं

तर्कसंगत रूप से पीछे। उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना है

जीवन के तथ्यों को नजरअंदाज करें।

आंध्र प्रदेश राज्य में v. बलराम (3) का आदेश

आंध्र प्रदेश सरकार सामाजिक और

( 1 ) [ 1969 ] 1 एस. सी. आर 103( 2 ) [ 1971 ] 1 एस. सी. सी. 38

( 3 ) ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 1375.



में प्रवेश के उद्देश्य से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

राज्य के मेडिकल कॉलेजों को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सरकारी आदेश पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसने यह निर्धारित करने के लिए जाति को मुख्य आधार के रूप में अपनाया था कि कौन पिछड़े वर्ग थे और यह बालाजी में न्यायालय के फैसले के विपरीत था। उच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि आयोग ने 10वीं या 11वीं कक्षा में किसी विशेष वर्ग या समुदाय की प्रति हजार छात्र आबादी के औसत को अपनाने में गलत कदम उठाया था।

शिक्षा का निर्धारण करने के उद्देश्य से राज्य के औसत का संदर्भ

कारणात्मक पिछड़ेपन। फिर भी पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कुछ समूहों की साक्षरता का प्रतिशत राज्य के औसत से काफी अधिक था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि आयोग ने इस सिद्धांत की अनदेखी की थी कि सूची में वर्गीकृत व्यक्तियों की सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की तुलना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समान या समान होनी चाहिए। आयोग ने समूहों को अधिक पिछड़े और कम पिछड़े वर्ग में विभाजित करके एक और गलती की थी। इस न्यायालय के समक्ष यह

आग्रह किया गया था कि जिन सिद्धांतों को बालाजी में निर्धारित किया गया था, चित्रलेखा और सागर वह कला। 15 ( 4 ) इसे कला के लिए एक प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना था। 15 ( 1 ) और 29 (2) और यह कि पिछड़ेपन के मामले में पिछड़े वर्गों की तुलना अनुसूचित जातियों से की जानी चाहिए और

अनुसूचित जनजातियाँ गलत थीं और उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने पाया कि उनके लिए मामले के इस पहलू पर विचार करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उनके समक्ष विशेष मामले में, वे तथ्यात्मक रूप से संतुष्ट थे कि पिछड़े के रूप में गिने जाने वाले वर्ग वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। हालांकि अदालत ने ध्यान रखा

कहने के लिए:

" यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं

निर्णय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करते हैं

नेस को सभी मामलों में बिल्कुल समान होना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति "।

इस तर्क को कि पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, निम्नलिखित अवलोकन के साथ पूरा किया गया:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जानते हैं कि इस खंड के तहत किया गया कोई भी प्रावधान अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं के भीतर होना चाहिए और केवल जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह की जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो सकती है।

यदि के. सी. वी. एकत्र करने के बाद कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

417

आवश्यक आँकड़े, यह पाया जाता है कि पूरी जाति

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, हमारी राय में,

ऐसे व्यक्तियों का आरक्षण बढ़ाना होगा।

इस तथ्य के बावजूद कि कुछ व्यक्तियों में

वह समूह सामाजिक और शैक्षिक दोनों रूप से ऊपर हो सकता है

सामान्य औसत। इस तथ्य को कहने का कोई लाभ नहीं है कि

देश में कई जातियाँ हैं, जो हैं

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और इसलिए राज्य द्वारा उपयुक्त प्रावधान करना होगा

उनके हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 15 (4) में प्रभार।

एक पूरी जाति या समुदाय के सदस्य कर सकते हैं

मूल्यों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पैमाने पर

दिया गया समय पीछे हो सकता है और उस कारण से हो सकता है

पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वे

समुदाय की एक जाति के सदस्य हैं लेकिन क्योंकि वे

एक वर्ग बनाएँ। इसलिए, यह स्पष्ट है कि हो सकता है

एक पूरी जाति या एक समुदाय के सामाजिक होने के उदाहरण

और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के लिए माना जाता है

कला के तहत संरक्षण दिया गया। 15 ( 4 ) ......निष्कर्ष निकालने के लिए, हालांकि प्रथम दृष्टया पिछड़े लोगों की सूची

जिन वर्गों पर हमारे सामने हमला हो रहा है, उन्हें माना जा सकता है

जाति के आधार पर होगा लाल, एक करीबी जांच होगी

विशेष व्यवसायों या व्यवसायों का पालन करते हुए,आयोग द्वारा विस्तृत रूप से संदर्भित "।

इसके बाद न्यायालय ने कहा कि उनके सामने सवाल यह था कि क्या पिछड़े वर्ग आयोग के पास पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की गणना के लिए प्रासंगिक डेटा और सामग्री है, यह एक वास्तविक सवाल था न कि क्या आयोग वैज्ञानिक रूप से सटीक था। न्यायालय ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आयोग के निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक सामग्री है और कहाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां शैक्षिक औसत राज्य के औसत से थोड़ा अधिक है, लेकिन यह स्थिति अपने आप में पूरी सूची को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, वहाँ भी यह देखा जाता है कि जब पूरा वर्ग जिसमें वह विशेष समूह होता है

सम्मिलित, औसत 418 से कम माना जाता है

राज्य के औसत से अधिक। यह मानते हुए भी कि कुछ श्रेणियां हैं जो साक्षरता में राज्य के औसत से थोड़ी अधिक हैं, यह राज्य के लिए ध्यान देने और व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों की स्थिति की समीक्षा करने का विषय है और

उचित निर्णय लें। "

पिछले तीन उच्च न्यायालय स्कूल कक्षाओं में औसत छात्र आबादी की परीक्षा के संबंध में बालाजी में टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए यह था

उन्होंने कहा:

" उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा की गई इन टिप्पणियों को, हमारी राय में, द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है

उच्च न्यायालय ने मामले को बंद कर दिया। यह इस आधार पर आगे बढ़ा है कि यह स्पष्ट है कि कक्षा के शैक्षिक औसत की गणना पिछली तीन उच्च विद्यालय कक्षाओं में छात्र आबादी के आधार पर नहीं की जानी चाहिए और केवल वे वर्ग जिनका औसत राज्य के औसत से कम है, उन्हें ही शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में माना जा सकता है। इस न्यायालय ने केवल उन व्यापक सिद्धांतों का संकेत दिया है जिन्हें निम्नलिखित प्रावधान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कला. 15 ( 4 ) . ”

जानकी प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य ने आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के बीच की कड़ी को देखा और कहा:

" भारत में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन आगे आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है और बालाजी के मामले में यह देखा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन अंततः और मुख्य रूप से होता है।

गरीबी के कारण "।

यह कहने के बाद न्यायालय गरीबी को इस आधार पर विशेष परीक्षा के रूप में निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं था कि भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से ग्रस्त था और यदि गरीबी को आरक्षण के लिए एकमात्र परीक्षा बनाया जाता है, तो एक संसाधनहीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहा गया था,

" लेकिन अगर गरीबी एकमात्र परीक्षा है, तो भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जाता है और यदि आरक्षण केवल आर्थिक के. सी. वी. कुमार बनाम कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) के आधार पर किया जाता है

कोड्साइडरेशन, एक अस्थिर स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि

उन क्षेत्रों में भी जिन्हें सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है और

शैक्षिक रूप से उन्नत, वहाँ के बड़े पॉकेट हैं गरीबी। इस देश में एक छोटे से प्रतिशत को छोड़कर

आबादी, लोग आम तौर पर गरीब हैं-कुछ हैं

अधिक गरीब, अन्य कम गरीब। इसलिए जब एक सामाजिक

अन्वेषक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने का प्रयास करता है

पिछड़े वर्ग वह इसे विश्वास के साथ कर सकते हैं कि वे हैं

गरीब होना तय है। हालांकि दो वार्ड, 'सामाजिक रूप से' और' शैक्षिक रूप से 'के उद्देश्य के लिए संचयी रूप से उपयोग किया जाता है

पिछड़े वर्ग का वर्णन करते हुए, कोई यह पा सकता है कि यदि एक वर्ग

समग्र रूप से शैक्षिक रूप से उन्नत है, यह आम तौर पर भी है

के सुधारात्मक प्रभाव के कारण सामाजिक रूप से उन्नत

उस वर्ग में शिक्षा। शब्द "उन्नत" और

" पिछड़े केवल सापेक्ष शब्द हैं-कई हैं

और "पिछड़े", और कठिन कार्य यह है कि कौन सा वर्ग कर सकता हैइनमें से कई परतों को सामाजिक रूप से मान्यता दी जाए

और शैक्षिक रूप से पिछड़े "।

जम्मू और कश्मीर राज्य ने छह वर्गों की घोषणा की थी

नागरिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। वे थे (1) ऐसे व्यक्ति जिनकी पारंपरिक स्थिति बासठ पुरुषों में से एक थी; (2) 23 सामाजिक जातियों के व्यक्ति; (3) छोटे किसान; (4) कम वेतन पाने वाले पेंशनभोगी; (5) संघर्ष विराम रेखा से सटे क्षेत्रों के निवासी; (6) "खराब इलाकों" से संबंधित व्यक्ति। अदालत ने पाया कि बत्तीस सूचीबद्ध व्यवसायों में से कुछ पारंपरिक व्यवसाय नहीं थे और उस सूची की समीक्षा की आवश्यकता थी। अदालत ने भी

यह पाया गया कि 23 में से 19 जातियों की पहचान समिति द्वारा सामाजिक अक्षमताओं और शैक्षिक रूप से पीड़ित के रूप में की गई थी और

आर्थिक रूप से पिछड़े। शेष चार जातियों के मामले में, यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि वे पिछड़े वर्ग थे। छोटे किसानों की तीसरी श्रेणी का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि वे इसे 'समान व्यवसाय वाले लोगों का एक सजातीय सामाजिक वर्ग और कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पहचाने जाने योग्य' नहीं कहा जा सकता था।

उनके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता था कि वे खेती करते थे या जीते थे।

जमीन पर। इसी तरह चौथी श्रेणी के संबंध में, यह देखा गया

कि वे भी लोगों के एक समान वर्ग से संबंधित नहीं हैं,

उनके बीच एक ही बात समान थी कि वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। पाँचवीं और छठी श्रेणी के संबंध में अदालत ने कहा कि संचार की कमी, पहुंच की कमी, 420 की कमी है।



भौतिक संसाधनों, आदिम जीवन स्थितियों और इस तरह के राशन ने उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े।

उत्तर प्रदेश राज्य में v. प्रदीप टंडन, (1) न्यायालय

गरीबी को एक प्रासंगिक कारक के रूप में मान्यता दी, लेकिन यह देखा गया कि यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े गरीब वर्गों की खोज का निर्धारक कारक नहीं था। फिर भी उत्तर प्रदेश में पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को आर्थिक आधार पर बनाए रखा गया। कहा गया था,

" उत्तर प्रदेश में पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्र हैं -

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उदाहरणउन कारणों से नागरिकों के लिए। पिछड़ेपन का आंकलन किया जाता है

आर्थिक आधार पर कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना माप है

मानव संख्या के रखरखाव के लिए सक्षम संभावनाएँ, जीवन और अचल संपत्ति के मानक। एक आर्थिक से

दृष्टिकोण से नागरिकों के वर्ग पिछड़े हैं जबवे संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं करते हैं। जब बड़ा होता है।

आबादी जिनकी संपत्ति छोटी और अपात्र हैसामाजिक पिछड़ेपन का तत्व देखा जाता है। कब प्रभावी होता है

इसकी अनुपस्थिति में क्षेत्रीय विशेषज्ञता संभव नहीं है।

संचारण के साधनों और तकनीकी प्रक्रियाओं में

पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों के लोग सामाजिक रूप से

दूर-दराज के इलाकों में लोग सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दीवारें उठाते हैं लोगों की भावना "।

" शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाया जाता है

उन कारकों का संदर्भ। जहाँ लोगों के पास पारंपरिक हैसामाजिक और पर्यावरण के कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता

मानसिक स्थितियाँ या व्यावसायिक बाधाएँ, यह एक

शैक्षिक पिछड़ेपन का चित्रण। पहाड़ी और

उत्तराखंड क्षेत्र दुर्गम हैं। की कमी है

शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक सहायता। लोग अंदर

शिक्षा की कमी के कारण नागरिकों के पिछड़े वर्ग सुविधाएँ उन्हें स्थिर रखती हैं और उनके पास न तो है

अर्थ और मूल्य और न ही शिक्षा के लिए जागरूक ",

( 1 ) [ 1975 ] 1S.C.R.5761।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) 421

अदालत ने ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया

इस आधार पर कि ग्रामीण आबादी जो राज्य की आबादी का 80 प्रतिशत है, एक सजातीय वर्ग नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे।

न्यायालय ने परिभाषित करने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए

के. एस. जयश्री बनाम केरल राज्य, (1) जिस पर सवाल उठाया गया था वह एक सरकारी आदेश था जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि केवल वे नागरिक जोऐसे परिवार के सदस्य जिनकी कुल आय रु. 500 करोड़ से कम थी। 6,000 प्रति वर्ष और जो सरकारी आदेश के अनुलग्नकों में उल्लिखित जाति और समुदाय से संबंधित था

कला के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का गठन करना। 15 ( 4 ) . न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा और कहा:

" नागरिकों के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में नागरिकों के समूह की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। हालाँकि जाति को एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं बनाया जा सकता है। अंतिम विश्लेषण में सामाजिक पिछड़ेपन काफी हद तक गरीबी का परिणाम है। गरीबी के परिणामस्वरूप होने वाली सामाजिक अभद्रता उनकी जाति के विचार से बढ़ने की संभावना है। यह नागरिकों के पिछड़ेपन को निर्धारित करने में जाति और गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। गरीबी अपने आप में नहीं है

सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारक कारक। गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन के संदर्भ में प्रासंगिक है। आयोग ने पाया कि निम्न आय वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। आरक्षण का आधार आय नहीं है, बल्कि प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर निर्धारित सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन है। यदि पिछड़े वर्गों का कोई वर्गीकरण

( 1 ) [ 1976 ] 3 एस. सी. सी 730



तार्किक।गरीबी के परिणामस्वरूप सामाजिक पिछड़ेपन की संभावना है

जाति संबंधी विचारों से बड़ा किया जाए। व्यवसाय, स्थान निवास के निर्धारण में प्रासंगिक कारक भी हो सकते हैं।

जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं।

सामाजिक और आर्थिक विचार चलन में आए।

समस्या को हल करने और उचित मानदंड विकसित करने मेंयह निर्धारित करना कि कौन से वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पीछे की ओर।

यह निर्धारित करने की समस्या कि सामाजिक रूप से कौन हैं और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग सरल नहीं हैं।

समाजशास्त्रीय और आर्थिक विचार लागू होते हैं।इसके निर्धारण के लिए उचित मानदंड तैयार करने में। यह है।

राज्य का कार्य। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है -

यह तय करें कि आवेदन किए गए परीक्षण वैध हैं या नहीं।

यदि वर्गीकरण पूरी तरह से नागरिक की जाति पर आधारित है, तो यह तर्कसंगत नहीं हो सकता है। सामाजिक पिछड़ेपन बहुत हद तक गरीबी का परिणाम है। पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति और गरीबी दोनों प्रासंगिक हैं। लेकिन

न केवल जाति होगी और न ही गरीबी।परीक्षण निर्धारित करना

इसलिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

अनुच्छेद 15 (4) में नागरिकों की जाति के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है। आर. चित्रलेखा बनाम। मैसूर राज्य [1964] 6 एससीआर 368: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1823 इस न्यायालय ने कहा कि आर्थिक स्थितियों के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण और

व्यवसाय अनुच्छेद 15 (4) का उल्लंघन नहीं करते हैं।"

केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1) एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसका निर्णय सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाता है जिसमें रे, सीजे शामिल होते हैं। , खन्ना, मैथ्यू, बेग। कृष्णा अय्यर, गुप्ता और मुर्तजा फजल अली, जे. जे.) . सवाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को एक सीमित अवधि के लिए दी गई छूट के बारे में था।

( 1 ) [ 1976 ] 1 एससीआर 906।



लोअर डिवीजन क्लर्क के पद से अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ विभागीय परीक्षा। छूट प्रदान करने वाले नियम पर इस आधार पर हमला किया गया कि यह

कला का उल्लंघन था। 16 ( 1 ) . हमले के समर्थन में तर्कों में से एक यह था कि नियम के लागू होने का परिणाम होगा

पदोन्नति। रे, सीजे द्वारा इस नियम को बरकरार रखा गया था। , मैथ्यू, बेग, कृष्णा अय्यर और मुर्तजा फजल अली, जेजे। और खन्ना द्वारा मारा गया औरगुप्ता, जे जे। रे, सीजे। यह देखा गया कि अवसर की समानता ने "प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर पदोन्नति सहित इसकी समाप्ति तक सेवा के सभी चरणों" को अपने दायरे में ले लिया। अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उस नियम द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा जो प्रशासन की दक्षता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद गैर-प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित करेगा। कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े समुदाय को वरीयता देने वाला नियम कला का उल्लंघन नहीं करेगा।

14 , 16 ( 1 ) और 16 (2)। अनुच्छेद 16 (4) ने केवल इसमें किसी भी संदेह को दूर कर दिया।

जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विस्तारित अवधि की अनुमति देने के लिए पदोन्नति के लिए विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो साल का समय उचित था।

और उद्देश्य के लिए तर्कसंगत संबंध रखने वाला उचित वर्गीकरण

संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना

सार्वजनिक पद पर नियुक्ति या नियुक्ति। सभी वैध तरीके

सेवा में अवसर की समानता के लिए प्रयास करने के लिए उपलब्ध थे

कला. 16 ( 1 ) . अनुच्छेद 16 (4) ने इसे प्राप्त करने के तरीकों में से एक को अधिनियमित किया

कला में सन्निहित समानता। 16 ( 1 ) . इस तर्क से निपटना कि

नियम परिणामी वरीयता की अनुमेय सीमाओं को पार कर गया

अनुसूचित जातियों को दिखाया गया। रे, सीजे। देखा गया:

" उच्च न्यायालय ने अपने इस निष्कर्ष को आधार बनाने में गलती की कि महाभियोग नियम और आदेशों के लागू होने का परिणाम अत्यधिक और अत्यधिक है, अर्थात् 51 पदों में से 34 पद शेड्यूल के नेतृत्व वाली जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दिए गए थे। समग्र रूप से सेवा में की गई पदोन्नति कुल पदों की संख्या का लगभग 50 प्रतिशत नहीं है। अनुसूचित जातियाँ और राज्य की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। राज्य की राजपत्रित सेवा में उनकी हिस्सेदारी 8,700 में से 2 प्रतिशत 184 बताई जाती है। गैर-राजपत्रित नियुक्तियों में उनकी हिस्सेदारी केवल 7 प्रतिशत है, जो 1,62,784 में से 11,437 है। इसलिए यह सही है कि नियम 13एए और आदेश 424 को लागू करने के लिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

न केवल कला के तहत निर्देशन। 335 , लेकिन निर्देश भी

कला के तहत सिद्धांत। 46. "

रे, सी. जे. में एक और महत्वपूर्ण कथन। फैसला यह है कि

ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा, "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

जाति के सामान्य अर्थ के भीतर एक जाति नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया

भैयालाल वी. हरिकिशन सिंह को यह माना गया था कि एक जांच

इस सवाल में अनुमति नहीं थी कि क्या कोई विशेष जाति थी

अनुसूचित जाति या कला के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए नहीं। 341 .

मैथ्यू, जे. जो सीजे रे के निष्कर्षों से सहमत थे। ,

देखा कि किसी प्रकार की आनुपातिक समानता का सहारा लिया गया था

न्याय प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रों में आवश्यक है। अवसर की समानता केवल कानूनी समानता का मामला नहीं था, यह न केवल अक्षमता की अनुपस्थिति पर बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करता था। असमानताओं को समाप्त करने और प्रावधान करने के लिए सरकार का एक सकारात्मक कर्तव्य है

मानवाधिकारों और दावों के प्रयोग के लिए अवसर। उन्मूलन के लिए सरकार की सकारात्मक जिम्मेदारी है

असमानताएँ, सामाजिक, आर्थिक या अन्यथा। अदालत के लिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह राज्य से समान्तर समानता के मानक को अपनाने की अपेक्षा करे जो नागरिकों के एक वर्ग की अलग-अलग शर्तों और परिस्थितियों को ध्यान में रखता हो जब भी वे शर्तें और

परिस्थितियाँ बुनियादी अधिकारों और दावों के आनंद के लिए उनकी समान पहुंच के रास्ते में खड़ी थीं। कला. 16 ( 4 ) यह कला का अपवाद नहीं था। 16 ( 1 ) . यह अवसर की समानता को किस हद तक ले जाया जा सकता है, यह बताने का एक जोरदार तरीका था। , यहाँ तक कि आरक्षण करने तक भी। राज्य को ऐसा कोई भी उपाय अपनाने का अधिकार था जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक दंडात्मक उपाय के रूप में उचित ठहराए, बशर्ते कि यह उपाय प्रशासन की दक्षता के लिए आवश्यक न्यूनतम बुनियादी योग्यता के अधिग्रहण के साथ न हो। बेग, जे. रे, सीजे के निष्कर्षों से स्पष्ट रूप से सहमत हैं। , मैथ्यू, कृष्णा अय्यर और एस. एम. फजल अली, जे. जे. , उन्होंने कहा कि कला का संरक्षण। 16 सेवा की अवधि के दौरान जारी रखा। उन्होंने देव साना और बालाजी को इस आधार पर अलग किया

कि यदि सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समग्र स्थिति और तस्वीर को ध्यान में रखा जाए, तो कर्मचारियों का तथाकथित पसंदीदा वर्ग पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम होगा।

हालांकि, जे. बेग ने सोचा कि कला। 16 ( 4 ) के लिए डिज़ाइन किया गया था

कला के परस्पर विरोधी आकर्षणों का मिलान करें।

16 ( 1 ) गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हुए के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.)

425

न्याय की, ऐसी परिस्थितियों में समानता के रूप में कल्पना की गई जिसके तहत कैंडी तिथियां वास्तव में सरकारी सेवा और कला के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। 46 और 335 को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कर्तव्यों को शामिल करना

आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का हित ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय के चंगुल से मुक्त किया जा सके। जे. बेग के अनुसार कला के क्षेत्र में अतिक्रमण। 16 ( 1 ) केवल उस हद तक अनुमति दी जा सकती थी जब तक वे कला द्वारा वारंट किए गए थे। 16 ( 4 ) और कला में सामाजिक न्याय और समानता की व्यापक अवधारणा को पढ़ना। 16 ( 1 ) यह प्रावधान को ही बाधित कर सकता है और कला बना सकता है। 16 ( 4 ) ओटियोस। हमें तुरंत पीछे हटना होगा। कला में समानता की अवधारणा को संकुचित करने का कोई कारण नहीं है। 16 ( 1 ) और इसमें सामाजिक न्याय और समानता की व्यापक अवधारणाओं को पढ़ने से इनकार करते हैं। वास्तव में, यह आवश्यक है

कला पढ़ने के लिए। 16 ( 1 ) ताकि कला के साथ किसी भी संघर्ष में न आए। 46 और 335। एक संवैधानिक दस्तावेज को इसके प्रावधानों को संश्लेषित करने और वैमनस्य से बचने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। यह कहना कि समानता का अर्थ यह भी है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है, केवल यह कहना है कि जो स्वयं-स्पष्ट और सामान्य स्थान है। कला. 14 इसका तात्पर्य है और हम यह नहीं समझते कि यह कला में क्यों निहित नहीं है। 16 ( 1 ) भी। सच है, पहली नज़र में, कला। 16 ( 4 ) ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के लिए प्रावधान करने की शक्ति को बचाया जा सकता है

नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण, लेकिन दूसरी नज़र से पता चलता है कि यह वास्तव में एक पूर्व-विद्यमान शक्ति को मान्यता देता है और मान्यता को एक जोरदार तरीके से व्यक्त करता है ताकि उस शक्ति पर कोई संदेह जाति न हो। इस तरह की

विधायिकाओं और संविधान बनाने वाले निकायों के लिए उपकरण अज्ञात नहीं है। कला. 16 ( 4 ) व्याख्या के नियम की प्रकृति में अधिक है

कला के निर्माण का मार्गदर्शन करें। 16 ( 1 ) . व्याख्या की संभावना

अनुच्छेद 16 (1) ताकि संकीर्ण समानता को बढ़ावा दिया जा सके

कला द्वारा अधिक समानता को बाहर रखा गया है। 16 ( 4 ) .

कृष्ण आयस, जे. ने नियम 13एए की वैधता को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि कला। 16 ( 4 ) इसे एक बचत वर्ग के रूप में नहीं बल्कि कला में जोड़े गए एक खंड के रूप में देखा जाना था। 16 संदेह की संभावना से परे मामलों को स्पष्ट करने के लिए ड्राफ्ट्समैन की अत्यधिक चिंता के कारण।

वह इस कला पर जोर दे रहे थे। 16 नियुक्तियों और प्रस्तावों पर भी लागू किया गया। उन्होंने जे. फजल अली के साथ अपनी सहमति व्यक्त की कि कुछ पहले के फैसलों द्वारा निर्धारित एक वर्ष में 50 प्रतिशत की अंकगणितीय सीमा को बहुत अधिक नहीं दबाया जा सकता है और एक विभाग में समग्र प्रतिनिधित्व किसी विशेष वर्ष में भर्ती पर नहीं, बल्कि एक संवर्ग की कुल संख्या पर निर्भर करता है। उन्होंने जे के कला निर्माण, फजल अली के साथ भी सहमति व्यक्त की। 16 ( 4 ) और 'कैरी फॉरवर्ड' नियम के बारे में उनका दृष्टिकोण। लेकिन हमें यह इंगित करना चाहिए कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भी कुछ टिप्पणियां कीं जो संकेत देती हैं कि वे भी अभिजात वर्ग 426 में गिर गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

प्रश्न को 'सुरक्षात्मक भेदभाव' के रूप में देखने का जाल। जिस प्रश्न पर उन्होंने खुद को संबोधित किया वह था 'क्या नियम (13एए) हरिजनों के लिए सुरक्षात्मक विवाद के रूप में मान्य है'। यह देख रहे हैं इस सवाल के संदर्भ में, उन्होंने आरक्षण की बुराइयों के बारे में कथित सावधानी के कुछ शब्द बोलने शुरू किए। उन्होंने कहा,

समाजशास्त्रीय सावधानी का एक शब्द। के प्रकाश में

अनुभव से मुझे लगता है कि यहाँ और कहीं और 'आरक्षण' का खतरा तीन गुना है। इसके लाभ, मोटे तौर पर, पीठ की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं।वार्ड 'जाति या वर्ग, इस प्रकार कमजोरों में से सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखता है और भाग्यशाली परतों को छोड़ देता है

पूरा केक खाओ। दूसरा, यह दावा लोकतंत्र में बड़े और मुखर समूहों द्वारा असाधारण रूप से किया जाता है, जिनके पिछड़ेपन का बोझ कम हो गया है।

समय की प्रगति और बेहतर शिक्षा के उपायों और रोजगार के अधिक अवसरों से स्थिर रूप से हल्का हुआ

लेकिन औपचारिक रूप से ऊपरी कोष्ठक के रूप में वर्गीकृत अपने निकट-बराबर पर स्कोर करने के साधन के रूप में 'कमजोर खंड' लेबल पहनना चाहते हैं। अंत में, इस समस्या का एक स्थायी समाधान केवल

सामाजिक वातावरण में सुधार, अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं और अंतर-जाति और अंतर-वर्ग विवाहों द्वारा जातियों के अंतर-निषेचन से आता है, जिसे एक बड़े राज्य कार्यक्रम के रूप में प्रायोजित किया जाता है, और इस समाधान को पिछड़ेपन में निहित स्वार्थ वाले उच्च 'पिछड़े' समूहों द्वारा नज़र से छिपा दिया जाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, न्यायिक प्रभाववाद नहीं, केवल पूरी सच्चाई बताएगा और 'अंडर डॉग' श्रेणियों द्वारा दर्ज की गई प्रगति के वस्तुनिष्ठ पुनर्मूल्यांकन की एक निरंतर प्रक्रिया आवश्यक है ताकि एक बार योग्य 'रिसेर वेशन' को 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' में नीचा किया जा सके।

इस कथन से कोई विवाद नहीं कर सकता कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संवेदनशील प्रश्न की अदालतों द्वारा जाँच का आधार न्यायिक प्रभाववाद नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान होना चाहिए। इससे पहले हमने उल्लेख किया था कि कैसे यह धारणा कि यदि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, यदि आरक्षण को पदोन्नति के पदों तक बढ़ाया जाता है या यदि कैरी फॉरवर्ड नियम अपनाया जाता है, तो दक्षता प्रभावित होगी, किसी भी वैज्ञानिक डेटा पर आधारित नहीं है। हालाँकि, इस आलोचना के लिए एक चेतावनी दर्ज करनी चाहिए कि आरक्षण के लाभ अक्सर पिछड़े वर्ग या जाति की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीने जाते हैं। कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कुछ सीटें और पद के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) हैं।

427

उनमें से अधिक भाग्यशाली लोगों द्वारा छीने जाने का मतलब यह नहीं है कि आरक्षण आवश्यक नहीं है। हमारे जैसे प्रतिस्पर्धी समाज में ऐसा होना तय है। क्या अनारक्षित सीटें और पद नहीं हैं?

उसी तरह समाज पर शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिया गया? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उनमें से शीर्ष स्तरों द्वारा योग्यता के उसी सिद्धांत पर छीन लिया जाता है जिस पर समाज के शीर्ष स्तरों द्वारा अनारक्षित सीटों को छीन लिया जाता है। यह कैसे बुरा हो सकता है अगर आरक्षित सीटों और पदों को पिछड़े वर्गों की मलाईदार परत द्वारा छीन लिया जाता है, अगर समाज की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा गैर-बेद पदों को छीनना अपने आप में बुरा नहीं है? यह उस आर्थिक और सामाजिक प्रणाली का एक आवश्यक सहवर्ती है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। पूरे में विशेषाधिकार प्राप्त

समाज अनारक्षित पुरस्कारों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को छीन लेता है पिछड़े वर्ग आरक्षित पुरस्कार छीन लेते हैं, यह करता है

आरक्षण को खराब न करें। लेकिन यह इस बात पर जोर देता है कि केवल

महाविद्यालयों में सीटों के प्रतिशत का आरक्षण और

सेवाओं में पद पिछड़े वर्ग की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

नेस। विकासात्मक सुविधा और अवसर सृजित किए जाने चाहिए

वास्तव में पिछड़े लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएँ। यह.

यह इंगित करता है कि अंतिम समाधान दृढ़ता से लक्षित उपायों में निहित है

सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक विकास। बेशक, वहाँ है

खतरा है कि यह आत्म-अपमान और पिछड़ेपन को जन्म दे सकता है

एक निहित स्वार्थ बन जाता है। आगे वास्तविक खतरा आरक्षण नहीं है।

लेकिन सामान्य के बिना आरक्षण सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक

विकास। इस तरह के आरक्षण का परिणाम यह है कि सभी युवा

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के योग्य पुरुष सिविल सेवाओं द्वारा कक्षाओं को सचमुच 'गड़बड़' कर दिया जाता है और बहुत कम छोड़ दिया जाता है

उन वर्गों के शिक्षित युवाओं को अपना कारण बनाने के लिए

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर। कार्यालय की बहुत सी बाधाएँ

सिविल सेवक बन चुके लोगों को विजेता बनने से रोकें

उनके भाइयों का कारण। ऐतिहासिक सच्चाई भी है

कि उत्पीड़ित व्यक्ति जो भूलने के प्रयास में अपनी स्थिति में सुधार करते हैं

आदतें और विचार। इस प्रक्रिया में वे अपना कम भूल जाते हैं।भाग्यशाली भाई।

फज़ल अली, जे. ने संतोष व्यक्त किया कि वर्गीकरण

सरकार द्वारा नियम 13 (ए. ए.) द्वारा बनाया गया अनुच्छेद द्वारा पूरी तरह से उचित था। 16 संविधान से। उन्होंने उस कला को धारण किया। 16 ( 4 ) इसे अलग से या कला के अपवाद के रूप में नहीं पढ़ा जाना था। 16 ( 1 ) , लेकिन पढ़ा जाना था

कला का अंश और अंश। 16 ( 1 ) और (2)। अत्यधिक आरक्षण के तथाकथित प्रश्न से निपटते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा:

" इसका मतलब है कि आरक्षण इसके भीतर होना चाहिए।

अनुमेय सीमाएँ और सभी के लिए एक लबादा नहीं होना चाहिए

नागरिकों के एक विशेष वर्ग से संबंधित पद और

इस प्रकार कला का उल्लंघन होता है। 16 ( 1 ) अप्रत्यक्ष रूप से संविधान। में।

उसी समय कला का खंड (4)। 16 कोई सीमा तय नहीं करता है

आरक्षण देने की सरकार की शक्ति पर।

चूँकि खंड (4) कला का एक भाग है। 16 संविधान के अनुसारयह स्पष्ट है कि राज्य को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

अत्यधिक आरक्षण ताकि नीति को विफल किया जा सके

कला में। 16 ( 1 ) . उपयुक्त आरक्षण क्या होगा?

अनुमेय सीमाओं के भीतर तथ्यों पर निर्भर करेगा और

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ और कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है

निर्धारित किया जा सकता है, और न ही इस मामले को एक गणित तक कम किया जा सकता है

भौतिक सूत्र ताकि सभी मामलों में इसका पालन किया जा सके।

इस न्यायालय के निर्धारित मामलों में कोई संदेह नहीं है

कि आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रतिशत। जैसा कि मैंने अधिकारियों को पढ़ा, यह, हालांकि, एक है

सावधानी का नियम और सभी श्रेणियों को समाप्त नहीं करता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य के पास बड़ी संख्या में धन है।

नागरिकों के वार्ड वर्ग जो 80 प्रतिशत हैं

उनके लिए नौकरियां, क्या यह कहा जा सकता है कि रेसर का प्रतिशत

वैशन खराब है और खंड की अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन करता है।

( 4 ) कला की। 16 ? इसका जवाब अनिवार्य रूप से होना चाहिए

नकारात्मक। इस प्रावधान का प्रमुख उद्देश्य है -

पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कदम उठाएँ।

फजल अली, जे. मेक्स्ट ने 'कैरी फॉरवर्ड' नियम की वैधता पर विचार किया और उस नियम को भी बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में कैरी फॉरवर्ड नियम को अपनाने की अनुमति नहीं दी गई, तो इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए समानता हो सकती है।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि बहुमत का गठन करने वाले सभी पाँच न्यायाधीश स्पष्ट थे कि अनुच्छेद। 16 नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक, पदोन्नति सहित, सिविल सेवक की सेवा के सभी चरणों में लागू किया जाता है। सात में से चार न्यायाधीश रे सी. जे., बेग, कृष्णा अय्यर और फजल अली जे. जे. हैं।, उनका यह भी स्पष्ट विचार था कि तथाकथित पचास प्रतिशत नियम सेवा में पदों की कुल संख्या पर लागू होगा, न कि

अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग समय पर भरे गए पदों की संख्या। किसी भी एक अवसर पर की गई नियुक्तियों में आरक्षण हो सकता है 50 प्रतिशत से अधिक। सात में से चार न्यायाधीश, रे, सीजे।, मैथ्यू, कृष्णा अय्यर और फजल अली, जे. जे. , आगे यह विचार व्यक्त किया कि कला।



16 ( 4 ) यह कला का अपवाद नहीं था। 16 ( 1 ) और यह केवल यह कहने का एक तरीका था कि आरक्षण एक तरीका था

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए समानता प्राप्त करना।

अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम। संघ का

भारत और अन्य. (1) न्यायालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के तहत पदों के आरक्षण और 'कैरी फॉरवर्ड रूल' के सवाल पर विचार करना था। आरक्षण और नियम

अदालत द्वारा बरकरार रखा गया। जोर-शोर से दिए गए तर्कों में से एक सामान्य दलील थी कि दक्षता प्रभावित होगी। कृष्ण अय्यर, जे. ने तर्क का सामना करते हुए कहा:

" आरक्षण के खिलाफ तर्क का दंश है

कि यह चुनाव द्वारा प्रशासन में अक्षमता को बढ़ावा देता है

जिनके साथ वरीयता में उप-मानक उम्मीदवार

बेहतर धैर्य। प्रतिस्पर्धी कौशल उच्च स्तर पर अधिक प्रासंगिक है।

पद, विशेष रूप से वे जहाँ चयन कॉम द्वारा किया जाता है

पदोन्नति को वरिष्ठता के आधार पर यांत्रिक रूप से सुरक्षित किया जाता हैसिवाय वहाँ जहाँ उम्मीदवार अयोग्य हो। उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं है

चयन पदों के मामले में कौशल की डिग्री। ( देखें [1968]

1 एस. सी. आर पी. 721 734)। यह स्पष्ट है कि चयन के बीच

राष्ट्र और गैर-चयन पदों में योग्यता की भूमिका होती है

पहले वाले की तुलना में पहले वाले में यह अधिक प्रासंगिक है।

और अगर रंगाचारी आरक्षण में वैध माना गया है

चयन पदों के मामले में, गैर-चयन में ऐसा आरक्षण

पद का पद एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। यदि, शीर्ष अधिकारियों के चयन में

आप कम योग्यता वाले एससी/एसटी के लिए पद आरक्षित कर सकते हैं, कैसे

क्या आप तर्कसंगत रूप से तर्क दे सकते हैं कि चपरासियों के पदों के लिए या

लोअर डिवीजन क्लर्क आरक्षण आपदा का कारण बनेगा? द.

वह भाग जो दक्षता खेलती है, उच्च के मामले में कहीं अधिक है निचले पदों की नियुक्ति की तुलना में पद। उस पर

यह दृष्टिकोण अनुलग्नक के निंदा से परे है।

" दक्षता और अक्षमता के बारे में तुच्छ तर्क

एक तुच्छ नकली हैं क्योंकि, आखिरकार, उच्च स्तर परहरिजनों के गिरिजान नियुक्त व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी होते हैं।

और यहां तक कि कक्षा III और II के पदों के मामले में भी वे

नगण्य हैं। प्रमुख बहुमत से आ रहा हैअनारक्षित समुदाय संभवतः कुशल हैं और

न्यूनतम प्रेरण के कारण दक्षता में कमी

( 1 ) [ 1981 ] 1 एस. सी. आर 185

महत्वपूर्ण रूप से सभी प्रशासनिक दक्षता। वास्तव में,के पतन की कल्पना करना घोर अतिशयोक्ति होगी

प्रशासन क्योंकि कुल का 5 से 10 प्रतिशत

विभिन्न वर्गों में अधिकारियों की संख्या होती है

एसडीबी-मानक। इसके अलावा, देने के लिए ध्यान रखा गया है

कमी को ठीक करने के लिए सेवा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण "।जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि प्रतिस्पर्धी कौशल उच्च पदों में प्रासंगिक है,

हमें नहीं लगता कि पदों में आरक्षण के बारे में माफी मांगना आवश्यक है, जब तक कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। दूसरी ओर, हमें माफी मांगनी होगी कि अभी भी आरक्षण की आवश्यकता है। इससे पहले हमने टॉनी की समानता से एक अंश निकाला जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया कि मानवता के लिए एक-दूसरे के प्रति अपनी बौद्धिक और नैतिक श्रेष्ठता को कितना अपमानजनक बनाना था। कृष्ण अय्यर, जे. ने एक बार फिर उस कला पर जोर दिया। 16 ( 4 ) यह समानता की केंद्रीय अवधारणा के बहुआयामी चरित्र का एक पहलू था। हममें से एक (जे. चिन्नाप्पा रेड्डी) ने इसी मामले में बताया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को दी गई संवैधानिक गारंटी को वास्तविकता में बदलना कितना आवश्यक था ताकि उन वर्गों के नागरिकों की रक्षा और पोषण के लिए आवश्यक राज्य कार्रवाई की जा सके ताकि वे अपने कंधों से एक हजार साल के अभाव के भारी बोझ को दूर कर सकें और भागीदारी के उचित अनुपात का दावा कर सकें।

प्रशासन में। यह बताया गया था कि कला। 16 ( 4 ) वास्तव में कला से निकला। 16 ( 1 ) . कहा गया था,

" कला. 16 ( 4 ) एक अपवाद की प्रकृति में नहीं है

कला. 16 ( 1 ) . यह कला का एक पहलू है। 16 ( 1 ) जो बढ़ावा देता है और

विशेष के साथ अवसर की समानता के विचार को आगे बढ़ाता है

एक कम विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्ग का संदर्भ

नागरिकों को जब समान डी ड्रोइट (औपचारिक या कानूनी समानता)

समानता (व्यावहारिक या तथ्यात्मक समानता) नहीं है।

यह इस बात का उदाहरण है कि राज्य को इसका सफाया करने के लिए क्या करना चाहिए।इगालाइट डू ड्रोइट और इगालाइट डी फैट के बीच अंतर,

यह मान्यता देता है कि अवसर की समानता का अधिकार

शर्तों के लिए कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का अधिकार शामिल है

उन लोगों के तुलनीय या प्रतिपूरक जो आनंद लेते हैं

विशेषाधिकार प्राप्त। अवसर की समानता ऐसी होनी चाहिए कि -'परिणामों की समानता' प्राप्त करें न कि वह जो केवल

कम भाग्यशाली के खिलाफ जीतने के लिए, तब भी जब प्रतिस्पर्धा अन्यथा यह अपने आप में न्यायसंगत है।

ए. के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) में जॉन रॉल्स

431

न्याय का सिद्धांत 'वितरणात्मक अर्थों में समानता की प्राथमिकता और सामाजिक प्रणाली की स्थापना की मांग करता है "ताकि कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक संपत्तियों के वितरण में अपने मनमाने स्थान या समाज में अपनी प्रारंभिक स्थिति से बिना मुआवजे के लाभ दिए या प्राप्त किए बिना लाभ या हानि न प्राप्त करे। सामाजिक न्याय का उनका मूल सिद्धांत है: " सभी सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं-स्वतंत्रता और अवसर, आय और धन, और आत्म-सम्मान के आधार को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि एक असमान वितरण न हो।

इन वस्तुओं में से किसी भी या सभी का उपयोग कम से कम पसंदीदा के लाभ के लिए है, "सामाजिक न्याय की उनकी अवधारणा के आवश्यक तत्वों में से एक है जिसे वे निवारण का सिद्धांत कहते हैं:" यह वह सिद्धांत है जिसके लिए अनुचित असमानताओं के निवारण की आवश्यकता होती है, और चूंकि जन्म और प्राकृतिक संपन्नता की असमानताओं को कम किया जाता है, इसलिए इन असमानताओं की भरपाई किसी न किसी तरह की जानी चाहिए। इसलिए समाज को उन लोगों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करना चाहिए जिनके पास कम मूल संपत्ति है और जो कम अनुकूल सामाजिक वातावरण में पैदा हुए हैं।

पद "।

यह कथन कि अवसर की समानता से परिणामों की समानता मिलनी चाहिए, कला की पूर्ति की दार्शनिक नींव थी। 16 ( 1 ) कला में। 16 ( 4 ) .

इसलिए अब हमने ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय पर ध्यान दिया है।

वर्ग और जाति की पृष्ठभूमि, दर्शन, आरक्षण और आरक्षण विरोधी तर्क और बयानबाजी, संवैधानिक प्रावधान और अलग-अलग न्यायिक रुख। संसदीय, कार्यपालिका, न्यायिक, राजनीतिक और व्यावहारिक ज्ञान के इन तीन दशकों से क्या निकलता है? स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जो एक तरफ अग्रगामी वर्ग-जमींदार, विद्वान, पुजारी और व्यापारी वर्ग और दूसरी तरफ बाहरी जाति और दलित वर्ग, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच खड़े हैं। गरीबी, जाति, व्यवसाय और निवास प्रमुख कारक हैं जो एक वर्ग को सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में चिह्नित करने में योगदान करते हैं। जिन रीति-रिवाजों का वे सम्मान करते हैं और पालन करते हैं, जिन अनुष्ठानों से वे डरते हैं और उन आदतों का पालन करते हैं जिन्हें वे अनुकूलित और अनुरूप करते हैं, जिन उत्सवों का वे आनंद लेते हैं और मनाते हैं और यहां तक कि जिन देवताओं का वे सम्मान और पूजा करते हैं, वे उनके सामाजिक स्तर और पिछड़ेपन को पहचानने में ज्ञानवर्धक तत्व हैं। उदाहरण के लिए, यह संभव हो सकता है 432

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

यह प्रदर्शित करने के लिए कि सामाजिक रूप से हीन माने जाने वाले कई वर्गों, जातियों या सामुदायिक संबंधों में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम और हिंदू विवाह के बावजूद बाल विवाह आज भी कायम है।

एक्ट करें। कानूनी पंडितों और हिंदू कानूनों पर विद्वान पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के बावजूद यह घोषणा करते हुए कि सप्तपदी एक वैदिक हिंदू विवाह के लिए आवश्यक है, अधिकांश सामाजिक रूप से निम्न वर्ग शायद ही कभी नियम का पालन करते हैं; उनके अपने रीति-रिवाज और अनुष्ठान हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने से बहुत पहले, हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा तलाक की अनुमति देने से बहुत पहले, कई तथाकथित सामाजिक रूप से निम्न वर्गों या समुदायों की प्रथा की अनुमति थी।

विधवाओं का पुनर्विवाह और तलाक। तलाक अदालत के आदेश से नहीं था, बल्कि एक जाति पंचायत द्वारा दिया गया था। जाति-पंचायत तलाक अस्वीकार्य था और सामाजिक रूप से उच्च वर्गों के बीच विधवाओं का पुनर्विवाह भी अस्वीकार्य था जो इन रीति-रिवाजों को आदिम मानते थे। द.

तथाकथित निम्न वर्गों के पास विवाह करने के लिए पुरोहितों या उन्हें भंग करने के लिए अदालतों का सहारा नहीं था और न ही उनके पास था।

कपड़ों की आदतें भी प्रकाश डालती हैं, जबकि यह कल्पना करना मुश्किल है कि उच्च जाति या व्यावसायिक समूहों से संबंधित व्यक्ति अपने दैनिक काम के बारे में नंगे-खुले जाते हैं, निम्न जाति या व्यावसायिक समूहों से संबंधित व्यक्तियों को देखना कोई असामान्य अधिकार नहीं है, इसलिए काम की आदतों को भी एक संकेत दिया गया है। उच्च सामाजिक समूहों से संबंधित महिलाएं आम तौर पर अन्य सामाजिक समूहों में सेवा करने की परवाह नहीं करतीं।

निम्न जातियाँ। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में हर गाँव में तथाकथित हीन जातियाँ देवी सुनकलम्मा की पूजा करती हैं।गंगम्मा, पोलीमेरम्मा (गाँव की सीमा की रखवाली करने वाली देवी), येलम्मा (गाँव की सीमा की रखवाली करने वाली एक और देवी)। वे हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, दीपावली आदि मनाते हैं, लेकिन अन्य त्योहार भी जिनमें उच्च वर्ग भाग नहीं लेते हैं।

कई अन्य रीति-रिवाज, अनुष्ठान या महत्वपूर्ण आदतें हैं।

अगर कोई केवल उनका अध्ययन करने की परवाह करता है तो सामाजिक रूप से पिछड़े वार्ड वर्गों को चिह्नित करें।

इन कारकों से जुड़ा वजन के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (चिन्नाप्पा रेड्डी, जे.) 433 पर निर्भर करता है।

मामले की परिस्थितियों पर जो केवल विचारशील, मर्मस्पर्शी जांच और विश्लेषण से ही सामने आ सकती हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता।

गणितीय सूत्रों के माध्यम से लेकिन केवल में देखकर

चारों ओर घूमना या पूरी स्थिति पर एक नज़र डालना। कभी-कभी कुछ जातियों या सामाजिक समूहों को सामाजिक रूप से आगे या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में आसानी से पहचानना संभव हो सकता है। गरीबी, ज़ाहिर है,

बुनियादी है, मूल कारण होने के साथ-साथ सामाजिक समस्या का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भी है

और शैक्षिक पिछड़ेपन। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल गरीबी नहीं है।

संवैधानिक ब्रांडिंग को आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि विशाल

हमारे देश के अधिकांश लोग गरीबी से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ

उनमें से सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे हैं और अन्यपीछे की ओर। भारत जैसे देश में जहां 80 प्रतिशत लोग रहते हैं

रोटी-रेखा के नीचे, यहाँ तक कि तथाकथित सामाजिक रूप से अधिकांश

अग्रगामी वर्ग गरीब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई नहीं सोचेगा

देश में कहीं भी ब्राह्मणों को सामाजिक और शैक्षिक के रूप में वर्णित करना

हालाँकि, वे गरीब हो सकते हैं। यह विचार कि खराब

ब्राह्मण भी अनुच्छेद 15 (4) के लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं और 16 (4) इतना विचित्र है कि इस पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी संभवतः यह दावा नहीं कर सकता कि गुजरात के पटेल, बंगाल के कायस्थ,

आंध्र प्रदेश के रेड्डी और कम्मा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

वर्ग, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से अधिकांश गरीब हो सकते हैं

किसान और खेतिहर मजदूर। ग्रामीण, सामाजिक सीढ़ी में वे

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनकी पहचान सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में की जाती है। एक बार फिर ग्रामीण आंध्र प्रदेश से स्पष्ट करते हुए, कोई भी आसानी से पहचान सकता हैजाति समूह, जैसे, कोम्मारस (जो पारंपरिक रूप से जारी रखते हैं)

काले स्मिथों का कब्जा), कुम्मारिस (जो पारंपरिक रूप से जारी रखते हैं

कुम्हारों का व्यवसाय), वडेरा (जो पारंपरिक रूप से पत्थर तोड़ने का व्यवसाय करते हैं), मंगली (जो पारंपरिक रूप से नाई का व्यवसाय करते हैं) और बेस्टास (जो पारंपरिक रूप से मछुआरों का व्यवसाय करते हैं) आदि को केवल अपनी जातियों का उल्लेख करके पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाता है। यह सच है कि उन जाति या सामाजिक समूहों के कुछ सदस्यों ने काफी प्रगति की होगी और आर्थिक रूप से अग्रणी अगड़े वर्गों के साथ अनुकूल तुलना करने के लिए आगे बढ़े होंगे।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से। ऐसे मामलों में, शायद एक उच्च आय सीमा वर्ग के उन सदस्यों के लिए आरक्षण का लाभ सुरक्षित करेगी जो वास्तव में इसके हकदार हैं। लेकिन किसी को यह पूछने का अधिकार है कि आगे के वर्गों के गरीब वर्गों का क्या होगा? राज्य को 434 करना होगा और ऐसा करना राज्य का कर्तव्य है।



कला के तहत आरक्षण के अलावा उनकी सहायता करने के अन्य साधनों की खोज करें। 15 ( 4 ) और 16 (4)। यह सब केवल इस बात पर जोर देता है कि अंतिम विश्लेषण में, आर्थिक समानता की प्राप्ति ही अंतिम और संकटग्रस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। एक सदस्य की पहचान करने के लिए मानदंड के रूप में व्यक्तिगत गरीबी को अपनाने में भी एक खतरा हैपिछड़े वर्ग, जिन्हें इंगित करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान कैसे की जा सकती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? क्या वे सभी हैं जो किसी अधिकारी या विधायक या किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं कि उनकी पारिवारिक आय एक वर्ष से कम है?

ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे वर्ग जो कृषि आय पर कर नहीं लगाने के कारण कोई आयकर नहीं देते हैं। किसे यह मुश्किल लगेगा याइस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करना असंभव है? बेशक, वास्तव में निम्न वर्ग जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इसलिए वर्ग गरीबी, व्यक्तिगत गरीबी नहीं, प्राथमिक परीक्षा है। अन्य सहायक परीक्षण जीवन शैली, जीवन स्तर, सामाजिक पदानुक्रम में स्थान, आदतें और रीति-रिवाज आदि हैं। व्यक्तिगत अपवादों के बावजूद, व्यवसाय या किसी अन्य प्रमुख विशेषता के संदर्भ में जाति के संदर्भ में सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान करना संभव और आसान हो सकता है। जाति और उप-क्षेत्रवाद के प्रति हमारी घृणा के बावजूद, ये जीवन के ऐसे तथ्य हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि वे गरीबी को दर्शाते हैं जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का प्राथमिक स्रोत है, तो उन्हें अन्य कम प्राथमिक स्रोतों के साथ मान्यता दी जानी चाहिए और गरीबी को पहचानने में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, चाहे आप इसे एक जाति समूह, एक उप-क्षेत्रीय समूह, एक व्यावसायिक समूह या किसी अन्य वर्ग के रूप में देखें। एक बार प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्रत्येक राज्य के लिए यह विचार करने का प्रश्न है कि रेखा कैसे और कहाँ खींची जाए क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ क्षेत्र से भिन्न होती हैं। एक बार जब प्रासंगिक शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और लोगों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाता है, तो इस मामले में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं होगा। लेकिन, ऐसा न हो कि कोई गलतफहमी हो, न्यायिक समीक्षा को दरकिनार नहीं किया जाएगा।

सेन। जे. शामिल प्रश्न के महत्व को देखते हुए, मैं अपने स्वयं के कुछ शब्द जोड़ना चाहूंगा।

· के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (सेन, जे.)

435

उठाया गया वास्तविक सवाल आरक्षण के लिए अत्यधिक आरक्षण का नहीं है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कला के तहत उन्नति। 15 ( 4 ) या किसी के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए

कला के तहत नागरिकों के पिछड़े वर्ग। 16 ( 4 ) जिनका, राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन सवाल उन नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के बारे में है जिनकी उन्नति के लिएराज्य कला के तहत विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 ( 4 ) जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अवधारणात्मक रूप से,

अनुच्छेद के तहत नागरिकों के पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना। 15 ( 4 ) और अनुच्छेद द्वारा परिकल्पित नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की प्रणाली। 16 ( 4 ) जैसा कि संविधान में गारंटी दी गई है, हमारे देश में सदियों पुरानी सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय

प्रतिबद्धता और एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अब तक तैयार की गई आरक्षण की नीति पर विराम लगा दिया गया।

नागरिकों के वर्ग जाति-उन्मुख होते हैं जबकि नीति आर्थिक मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। फिर अकेले बनाने में जाति का तत्व

इसे हटाया जा सकता है। वर्तमान में केवल विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के भीतर पिछड़े वर्ग अर्थात पिछड़े वर्गों के अग्रगामी वर्ग फसल काटते हैं।

इस तरह के आरक्षण के सभी लाभ जिसके परिणामस्वरूप सबसे कम

निम्न वर्ग गरीबी से ग्रस्त हैं और इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से

संवैधानिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद वे वंचित रहते हैं।कला के तहत प्रावधान। ( 15 ( 4 ) और 16 (4) उनके अग्रिम के लिए हैं।

मन में।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के 37 वर्षों के बाद ऐसा नहीं हो सकता है।

गंभीर रूप से विवादित है कि गरीबी सामाजिक और आर्थिक विकास का मूल कारण है

माइक पिछड़ेपन। समस्या पीठ की पहचान के बारे में हैवार्ड वर्ग जिनके लाभ के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है

कला के तहत। 15 ( 4 ) . या नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए

कला. 16 ( 4 ) . राज्य में व्यापक सार्वजनिक अशांति को देखते हुएहाल के दिनों में मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने

यह सच है कि केवल आर्थिक पिछड़ेपन से संतुष्ट नहीं होगा कला के तहत शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का परीक्षण। 15 ( 4 ) लेकिन

सवाल यह है कि किन मानदंडों को अपनाया जाना है। आर्थिक पिछड़ेपन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए केवल एक परीक्षा है

नेस। अगर वह परीक्षा सामाजिक और शिक्षा का एकमात्र मानदंड होना था

राष्ट्रीय पिछड़ेपन, इस तरह की प्रगति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष उपचार के लिए कक्षाएं विफल हो जाएंगी, 436

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

पूर्वावलोकन में, इस सवाल का जवाब कि कौन हैं

राज्य कला के तहत विशेष प्रावधान कर सकता है। 15 ( 4 ) अभी भी हमें छोड़ देता है। 'पिछड़े वर्ग' शब्द को समाज के कमजोर वर्गों का पर्याय क्यों नहीं माना जाना चाहिए? जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, क्या 'वर्ग' शब्द हिंदुओं के बीच किसी जाति या उप-जाति या किसी वर्ग या समूह को दर्शाता है? मुसलमान, ईसाई या अन्य धार्मिक समुदायों और संप्रदायों का क्या संबंध है? मेरी सुविचारित राय में, कला के तहत विशेष प्रावधान बनाने के लिए प्रमुख और एकमात्र कारक। 15 ( 4 ) या अनुच्छेद के तहत पदों और नियुक्तियों के आरक्षण के लिए। 16 ( 4 ) गरीबी होनी चाहिए, और जाति या उप-जाति या समूह का उपयोग केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के तुलनीय व्यक्तियों की पहचान के उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, जब तक कि पिछड़े वर्गों के ऐसे सदस्य ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेते हैं और उनके बीच गरीबी का उन्मूलन नहीं हो जाता है और वे हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नई सामाजिक व्यवस्था में समान भागीदार बन जाते हैं।

इस संदर्भ में, मुझे यह बताना चाहिए कि सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता या अन्यथा

में उस वर्ग के प्रतिशत के संदर्भ में निर्धारित किया गया

जनसंख्या और समग्र रूप से सेवा की कुल शक्ति। प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उस वर्ग के प्रतिशत के बिल्कुल अनुरूप नहीं होना चाहिए; यह केवल पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा, सेवाओं के मामले में सेवा में उस वर्ग के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व की सीमा पर विचार किया जाना चाहिए, चाहे वे आरक्षित या अनारक्षित पदों पर हों। हम अपने द्वारा किए गए अवलोकन के आलोक में आरक्षण के पूरे प्रश्न की तर्कसंगत जांच की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दे सकते। राज्य को दक्षता बनाए रखने और सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता के दोहरे संवैधानिक जनादेश को उचित महत्व और प्रभाव देना चाहिए। आरक्षणों की प्रकृति और विस्तार तर्कसंगत और उचित होना चाहिए। यह हो सकता है, और अक्सर न्यायालय के लिए पहले से रेखा खींचना मुश्किल होता है जो राज्य

पार नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय के लिए यह जानना कभी मुश्किल नहीं है कि

सीमा पार आक्रमण, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो, हुआ है। अदालतों के पास न तो विशेषज्ञता है और न ही समाजशास्त्रीय ज्ञान है जो यह निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है कि कला के अर्थ के भीतर 'नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' क्या हैं। 15 ( 4 ) डब्ल्यू. आई. एच. राज्य को कला के आदेश के बावजूद ऐसे वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है,

15 ( 2 ) कि राज्य 437 पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (सेन, जे.)

केवल धर्म, नस्ल, जाति, वंश, जन्म स्थान, निवास का आधार

या उनमें से कोई भी। कला. 340 'भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उन कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है जिनके तहत वे काम करते हैं और उन कदमों के बारे में सिफारिशें करते हैं जो संघ या किसी भी राज्य द्वारा ऐसी विषम संस्कृतियों को हटाने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए उठाए जाने चाहिए।' नागरिकों के किसी भी वर्ग के पिछड़ेपन की स्थिति एक तथ्य स्थिति है जिसकी जांच और निर्धारण की आवश्यकता एक तथ्य खोजने वाले निकाय द्वारा की जाती है जिसके पास प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए विशेषज्ञता और तंत्र है। संविधान में अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए इस तरह के आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 340 सिफारिशें करना और ऐसे पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना राज्य पर छोड़ना। न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए अक्षम है कि क्या नागरिकों का एक वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हालाँकि, इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह संविधान की व्याख्या करे और यह देखे कि इसका क्या अर्थ और इरादा है जब यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान करता है। इस स्थिति पर विचार करते हुए, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह वह संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इसके अलावा न्यायालय का बहुत कम या कोई कार्य नहीं है।

आरक्षण की वैधता या अन्यथा के बारे में सवाल हैं

इस न्यायालय के समक्ष कई बार आंदोलन किया गया और हल किया गया। जिस बार-बार और जोश के साथ ये सवाल उठाए जाते हैं, वह समाज में तनाव और बेचैनी का एक परेशान करने वाला संकेत है। जिस तरह से कला। 15 ( 4 ) और कला। 16 ( 4 ) राज्य द्वारा संचालित किए जाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के संकल्प को दर्शाती है

अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए: न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राज्य का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था लाना और उसे बनाए रखना है।

न्याय सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए यथोचित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। राज्य के तर्कहीन और अनुचित कदम धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से समाज के ताने-बाने को तोड़ देंगे। यह मुख्य रूप से राज्य का कर्तव्य और कार्य है कि वह लिए गए निर्णयों में संयम लाए

कला के तहत। 15 ( 4 ) और 16 (4), क्योंकि न्याय मनुष्यों के दिलों में रहता है और अन्याय और विपरीत भेदभाव की बढ़ती भावना, ईंधन मूर्खतापूर्ण राज्य कार्रवाई के नेतृत्व में, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय नष्ट कर देगा। अगर

राज्य कला के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करता है। 16 ( 1 ) और कला। 335 , इस न्यायालय को निश्चित रूप से अपना कर्तव्य निभाना होगा।

कला के तहत आरक्षण की सीमा। 15 ( 4 ) और कला। 16 ( 4 ) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. पी. एल. के भीतर आवश्यक रूप से राज्य से राज्य और क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होना चाहिए।

एस सी आर।

438

सरकार को पर्मा नियुक्त करने की व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिएराष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो

राज्य से लगातार समाजशास्त्रीय और आर्थिक अध्ययन करते रहें

किसी राज्य के भीतर राज्य और क्षेत्र से क्षेत्र तक। कला को लागू करके संविधान के निर्माता। 340 की स्थापना की स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई

इस तरह के एक उच्च शक्ति वाले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

केंद्र। इन समस्याओं को कभी भी अदालतों में मुकदमेबाजी के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत

कला में अंकित। 15 ( 4 ) और 16 (4) और अनुच्छेद का अधिदेश। 29 ( 2 )

इसे किसी विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राज्य मौजूद है

अपने लोगों की सेवा करें। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनमें विशेषज्ञता और कौशल होता है। वे सार हैं। उदाहरण के लिए, राज्य द्वारा संचालित अस्पताल सेवा प्रदान करता है।

जनता के बीमार सदस्य जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। चिकित्सा सेवाएँ लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं और उनसे निपटती हैं।

जनता। पेशेवर विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुभव का आधार, उच्च स्तर का तकनीकी ज्ञान और परिचालन कौशल है

पायलटों और विमानन इंजीनियरों की आवश्यकता। नागरिकों का जीवन ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर करता है। सरकार के अन्य समान क्षेत्र भी हैं।

ऐसी गतिविधि जहाँ व्यावसायिक, तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य विशेष कौशल की आवश्यकता हो। संघ या राज्यों के तहत ऐसी सेवाओं या पदों में, हम सोचते हैं कि पदों के आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है; नियुक्तियों के लिए केवल योग्यता ही एकमात्र और निर्णायक विचार होना चाहिए।

इस निर्णय के कारणों का पालन किया जाएगा।

वेंकटरमैया, जे. कुछ की संवैधानिक वैधता

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेशों में तकनीकी संस्थानों में कुछ सीटों और सरकारी सेवाओं में कुछ पदों के पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत क्रमशः कुछ जातियों, जनजातियों और समुदायों से संबंधित छात्र उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिए, जो राज्य सरकार की राय में पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा) का गठन करते हैं।

ये याचिकाएँ।

इन मामलों में शामिल प्रश्न नाजुक होते हैं और

इसलिए, बहुत सावधानी से निपटा जाना चाहिए। यहाँ उठाए गए मुद्दों और उन पर दिए गए निर्णय का एक महान ई होना तय है।



समाज पर प्रभाव। वे वास्तव में अत्यधिक संवेदनशील मुद्दे हैं। इसलिए, समस्या के लिए एक सतही दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए। इन प्रश्नों को उन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति के साथ निपटाया जाना चाहिए जिन्हें वास्तव में राज्य के हाथों सौम्य सहायता की आवश्यकता है और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। " अपनी आबादी के 'पिछड़े वर्गों' के पक्ष में 'सुरक्षात्मक' या 'क्षतिपूर्ति' भेदभाव के साथ भारत का विशाल और अद्वितीय प्रयोग एक ऐसी उदारता और दूरदर्शिता को दर्शाता है जो दुर्लभ है।

राष्ट्रों के बीच। इस तरह के अधिमानी सिद्धांत के संचालन में नीति-निर्माण और प्रशासन का भारी बोझ शामिल है।

विज्ञान, शिकागो विश्वविद्यालय, जिन्होंने भारतीय पिछड़े वर्गों की समस्याओं का विशेष अध्ययन किया है। तथ्य यह है किसरकारी एजेंसियों और 'सबसे बढ़कर अदालतों को समतावादी दबावों के आलोक में संवैधानिक सिद्धांतों की जांच करने के लिए बाध्य किया गया है, जो शायद ही पहले से देखी गई जटिलताओं को खोलते हैं जो समानता के सिद्धांत में दबी हुई थीं'। जो समाज समानता के आदर्श को संजोता है, उसे समानता की अवधारणा के अर्थ और विषय-वस्तु को परिभाषित करना होगा और एक समतावादी समाज लाने के लिए उसके लिए विकल्प हमेशा राजनीतिक होंगे। लेकिन अदालतों को विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि जिस समाज के लिए उन्हें जवाब देना है, वह एक प्रसार जारी कर रहा है

माँगें। संक्षेप में, जो हो रहा है, वह चेतना का एक परिवर्तन है जो अन्याय की संवेदनाओं से भरा हुआ है और

शोषण '। अतीत में कई असमानताएँ लगभग प्रकृति के क्रम का हिस्सा प्रतीत होती थीं। इस प्रकार समानता की श्रेणियों को एक अर्थ में जागरूकता के स्तरों के अनुरूप देखा जा सकता है। शायद सभी असमानताओं को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है और यह निश्चित है कि कुछ को केवल नई असमानताओं और नई शिकायतों को पैदा करके ही ठीक किया जा सकता है। यह वही है जिसने न्यायपालिका को इस तरह के निरंतर तनाव का आधार बना दिया है क्योंकि यह न्यायपालिका है और सबसे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय है जिसका कर्तव्य है कि वह इन परस्पर विरोधी मांगों को संवैधानिक व्याख्या के चश्मे के माध्यम से समाज में वापस लाए। हालाँकि, अदालतें उन समस्याओं से निपटती हैं जो समाज प्रस्तुत करता है। विशेष ऐतिहासिक कारणों से अलग-अलग समय पर जागरूकता के स्तर और शिकायत की संबंधित इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं।

अक्सर [1985] एस. यू. पी. पी. एल. की ओर रुख करते हैं। एस सी आर।

440

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकजुट करने के बजाय समानता की श्रेणियों के बीच अंतर करना।

उन्हें पकड़ें। वर्ग, नस्ल, धर्म और लिंग की असमानताओं ने खुद को विभिन्न अवधियों में प्राथमिक शिकायतों के रूप में प्रस्तुत किया है। अवसर की समानता दो प्रमुख सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती है-(1) अवसर की समानता का पारंपरिक मूल्य और (2) परिणामों की समानता का नया प्रशंसित विचार। सामाजिक न्याय की मांग हो सकती है और राजनीतिक हित व्यक्तिगत सदस्यों के पक्ष में सुधार की नीति को समीचीन बना सकते हैं

अल्पसंख्यक या समुदाय। लेकिन इस बिंदु पर जब भी कोई कार्रवाई की गई, अवसर की व्यक्तिगत समानता के सिद्धांत ने अपनी दिशा खो दी। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई ने एक समूह के एक व्यक्ति को दूसरे समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि वर्तमान को अतीत के खिलाफ खेला। अतीत में औसत दर्जे की क्षमता वाले कई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को एक ऐसी प्रणाली से लाभ हुआ था जो निर्विवाद रूप से उच्च जातियों के पक्ष में पक्षपाती थी। ' व्यक्तिगत आकांक्षाएँ समाज के नियमों की सुरक्षा का दावा करती हैं। लेकिन वे हमेशा सामंजस्य में नहीं होते हैं और कभी-कभी कुछ प्रकार के नस्लीय या समूह संतुलन को प्राप्त करने में एक ही समाज के व्यापक हित के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन असंतुलन का सुधार भी कभी-कभी होता हैसमानता। समाज पूर्ण तर्कसंगतता पर काम नहीं करते हैं, तर्कसंगतता की अधिकता अक्सर मानव संबंधों को अमानवीय बना देती है। अदालतों को यह भी याद दिलाया जाता है कि जो लोग अविभाज्य अधिकारों से वंचित हैं, उनके लिए क्रमिकता कभी भी पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है क्योंकि जैसा कि राल्फ बंचे ने कहा कि अविभाज्य अधिकारों का आनंद मरणोपरांत नहीं लिया जा सकता है। हमारा 'दर्जे के लिए संघर्ष, लोकतंत्र को चर्मपत्र से हटाने और उसे जीवन देने का संघर्ष' है। सामाजिक अन्याय हमेशा अपनी पुस्तकों को लाल स्याही से संतुलित करता है। न तो व्यक्तिगत रुचि की

सनक और न ही निहित स्वार्थों की सुरक्षा किसी भी उचित रूप से योग्य व्यक्ति के अवसरों को सीमित करने के कारणों के रूप में खड़ी हो सकती है। ये ऐसे विचार हैं जो कभी-कभी

परस्पर विरोधी हो सकता है जिसे समानता के सिद्धांत से उत्पन्न मामलों से निपटने वाले न्यायालयों के साथ तोलना चाहिए। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि अदालतें अपने आप में समानता की अवधारणा को सार्थक कार्रवाई में लाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें लोगों, सरकार और विधायकों की इच्छा से समर्थन दिया जाना चाहिए। होना चाहिए। मानव समाज के सभी वर्गों की ओर से एकजुट कार्रवाई का उदय। यही सब कुछ नहीं है। मौजूदा आर्थिक स्तर के तहत समानता लाने की केवल इच्छाशक्ति स्थिति को और खराब कर सकती है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए।

संसाधन ताकि समानता का संचालन कम बोझिल हो के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (वेंकटरमैया, जे.) 441

और समाज के प्रत्येक सदस्य को एक उच्च सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ले जाया जाता है, जिससे कोई भी न्यूनतम से नीचे नहीं रह जाता है जो समाज के प्रत्येक सदस्य को सभी बुनियादी मानवीय जरूरतों की गारंटी देता है। यदि कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं होती है तो अदालतों द्वारा की गई घोषणाएं खोखले शब्द बन जाएंगी क्योंकि संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय में कई उच्च सिद्धांत दिए गए हैं। यह कई कारकों के कारण निकला है जिन्हें यहाँ विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पृष्ठभूमि में इस मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

इस मामले में, न्यायालय से कर्नाटक राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवा में प्रवेश के मामले में योग्यता सिद्धांत और क्षतिपूर्ति सिद्धांत के बीच संघर्ष को हल करने के लिए कहा जाता है। सभी प्रतियोगी अपने मामले के समर्थन में संविधान के किसी न किसी खंड पर निर्भर हैं। इसलिए समस्या यह है कि लाल रंग अधिक कठिन है।

जो लोग योग्यता के समर्थन में बहस करते हैं, उनका तर्क है कि राज्य को मानव-निर्मित सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए जो एक व्यक्ति के रास्ते में हैं और उसे अपने प्राकृतिक कौशल और बुद्धि पर भरोसा करते हुए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के माहौल में अपने लक्षय को प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए। क्षतिपूर्ति सिद्धांत के लिए बहस करने वालों का तर्क है कि प्रतिस्पर्धा 'निष्पक्ष और न केवल स्वतंत्र' हो, इसके लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों की असमान स्थिति पर ध्यान दे, जिसके कारण उनके बीच असमान क्षमताएं पैदा हुई हैं और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा की कठोरता पर ध्यान दे, जो जब तक राज्य द्वारा गौर नहीं किया जाता है, तब तक समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को अवसर की समानता से लगातार वंचित कर सकता है। यह तर्क इस अच्छी तरह से स्थापित धारणा पर आधारित है कि घर पर सांस्कृतिक जीवन की असमान स्थितियां समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित बच्चों के असमान सांस्कृतिक विकास का कारण बनती हैं। सामाजिक कार्रवाई की आवश्यकता पर्यावरण कारकों और संबंधित व्यक्तियों की जीवन स्थितियों के कारण आवश्यक है। भारतीय दृश्य योग्यता के सिद्धांत का उपयोग, अन्य विचारों से

अप्रभावित, अक्सर अमानवीय परिणामों का कारण बन सकता है। बर्नार्ड द्वारा दिया गया निम्नलिखित चित्रण

विलियम्स उपरोक्त कथन को स्थापित करते हैं:

" मान लीजिए कि एक निश्चित समाज में एक योद्धा वर्ग की सदस्यता के साथ बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जिसके कर्तव्यों के लिए बड़ी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस वर्ग को अतीत में कुछ अमीर परिवारों से भर्ती किया गया है 442

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल; लेकिन समतावादी सुधारों में परिवर्तन प्राप्त होता है

नियम, जिनके द्वारा सभी वर्गों से योद्धाओं की भर्ती की जाती है

समाज का, एक उपयुक्त प्रतिस्पर्धा के परिणामों पर।

लेकिन इसका प्रभाव यह है कि अमीर परिवार

अभी भी लगभग सभी योद्धाओं को प्रदान करते हैं, क्योंकि बाकी

कि उनकी शारीरिक शक्ति स्वास्थ्य की तुलना में कम है आपका और अच्छा-नहीं। : रोते हैं। सुधारकों का विरोध है कि

अवसर का लाभ वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया है; अमीर जवाब देते हैं कि वास्तव में यह है, और कि गरीब अब

योद्धा बनने का अवसर है-यह बहुत बुरा है

भाग्यशाली है कि उनकी विशेषताएँ ऐसी हैं कि वे नहीं

परीक्षा पास करें। ' हम नहीं हैं, 'वे कह सकते हैं,' बहिष्कृत कोई भी गरीब होने के कारण, हम लोगों को बाहर कर देते हैं

कमजोर, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गरीब हैं

कमजोर भी।'

यह जवाब ज्यादातर लोगों को कमजोर और यहाँ तक कि सनकी भी लगेगा। यह उन कारणों के लिए है जो पहले कानून के समक्ष समानता के संबंध में थे; कि अवसर की कथित समानता काफी खाली है-वास्तव में, कोई कह सकता है कि यह वास्तव में मौजूद नहीं है-जब तक कि इसे इससे अधिक प्रभावी नहीं बनाया जाता है। क्योंकि कोई जानता है कि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है: कोई भी यह जानता है कि गरीब होने और अल्पपोषित होने के बीच, और अल्पपोषित होने और शारीरिक रूप से कमजोर होने के बीच एक आकस्मिक संबंध है। आगे मान लीजिए कि कुछ किया जा सकता है-धन के वितरण को बदलने के लिए कल्पित समाज में जो भी आर्थिक परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, उनके अधीन। यह सब होने के कारण, अमीरों द्वारा गरीबों के 'दुर्भाग्य' के लिए की गई अपील निरर्थक प्रतीत होनी चाहिए।

मैसूर की पूर्व रियासत जो अब कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जिसमें सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रणाली शुरू की गई थी। 1918 में मैसूर के महाराजा ने पिछड़े वर्गों की समस्या की जांच और रिपोर्ट देने के लिए मैसूर के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर लेस्ली सी. मिलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उस समिति को भेजे गए प्रश्न थे (i) लोक सेवाओं में भर्ती के तत्कालीन मौजूदा नियमों में आवश्यक परिवर्तन; (ii) विशेष के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (जे. वेंकटरमैया) 443

पिछड़े वर्गों के सदस्यों के बीच उच्च और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं और (iii) कोई अन्य विशेष उपाय जो सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं।

दक्षता, शिक्षा के व्यापक प्रसार और बढ़ी हुई स्थिति की भावना से राज्य को प्राप्त होने वाली सामान्य भलाई के लिए भी उचित सम्मान दिया जा रहा है जो इस प्रकार पिछड़े समुदायों में उत्पन्न होगा। यह महत्वपूर्ण है कि 'पिछड़े वर्ग' और 'पिछड़े समुदाय' अभिव्यक्ति का उपयोग लगभग एक दूसरे के स्थान पर किया गया था और यह कि संविधान के अनुच्छेद 335 में निहित विचार कि किसी भी आरक्षण से दक्षता में कमी नहीं आनी चाहिए, संविधान के अधिनियमित होने से तीन दशक से अधिक समय पहले अनुमान लगाया गया था। समिति ने 1921 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उसकी राय थी कि ब्राह्मणों के अलावा राज्य के सभी समुदायों को पिछड़े समुदायों के रूप में समझा जाना चाहिए जिनके बारे में उसने कुछ सिफारिशें की थीं। उस रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए सरकारी आदेश 1956 तक लागू रहे, यानी राज्यों का पुनर्गठन जो पांच एकीकृत इकाइयों को एक साथ लाया-पूर्व मेसूर राज्य (बेल्लारी जिला सहित), कुर्ग, बॉम्बे के चार जिले, हैदराबाद राज्य के कुछ प्रांत और दक्षिण कनारा जिला और कोल्लेगल तालुक जो पहले मद्रास राज्य का हिस्सा थे। पाँच एकीकृत इकाइयों में पिछड़े समुदायों की अलग-अलग सूचियाँ थीं और राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी उन्हें कुछ समय के लिए जारी रखने की अनुमति दी गई थी। एकता लाने के लिए राज्य सरकार ने 1959 की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों की सूची वाली एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना की वैधता

और उसी विषय पर उसके बाद जारी एक अन्य अधिसूचना के बारे में जो राज्य सरकार के अनुसार ब्राह्मणों, बनियों और कायस्थों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को पिछड़े समुदायों के रूप में माना गया था

रामकृष्ण में मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई

सिंह बनाम। मैसूर राज्य। ( 1) दोनों अधिसूचनाओं को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि विवादित अधिसूचनाओं में राज्य की 95 प्रतिशत आबादी के पिछड़े वर्गों और ब्राह्मणों, बनियों और कायस्थों के अलावा सभी हिंदू समुदायों और एंग्लो-इंडियंस और पारसियों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी गैर-हिंदू समुदायों की सूची शामिल है, इसलिए उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भेदभाव होता है सामाजिक और सामाजिक विकास के लिए प्रावधान करने के बजाय कुल आबादी का लगभग 5 प्रतिशत वाले कुछ बहिष्कृत समुदायों के खिलाफ।

( 1 ) ए. आई. आर. 1960 माई. 338 .

444

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। उच्च न्यायालय ने कहा कि

तथाकथित अग्रगामी समुदाय प्रावधान करने के बराबर नहीं थे। उन समुदायों के लिए जिन्हें वास्तव में अनुच्छेद के तहत सुरक्षा की आवश्यकता थी

15 ( 4 ) संविधान से। इसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क

ऐसा मामला जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग किसी भी मामले में ऐसा नहीं कर सकते

हालाँकि, जाति के आधार पर निर्धारित किया जाना अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद

उपरोक्त निर्णय उच्च न्यायालय, राज्य सरकार द्वारा दिया गया था

सरकार ने 8 जनवरी, 1960 को डॉ. आर. नागन गौड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

राज्य में पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए मानदंड निर्धारित करनानिम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ: ( 1 ) मानदंड का सुझाव देने के लिए

यह निर्धारित करने के लिए कि राज्य में किस वर्ग के लोगों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए और (2) यह सुझाव देना चाहिए कि इस प्रकार बताए गए मानदंडों का पालन किस तरह किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार उन व्यक्तियों को निर्धारित कर सके जो तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के संबंध में ऐसी वरीयता प्राप्त कर सकें जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाए और सरकारी सेवाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। उक्त समिति ने 19 फरवरी, 1960 को

अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकार ने 9 जून, 1960 को एक आदेश पारित किया जिसमें पेशेवर और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए 22 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं और शेष 60 प्रतिशत सीटों को योग्यता के आधार पर भरने की अनुमति दी गई। उपरोक्त सरकारी आदेश को एस. ए. पार्थ और अन्य में मैसूर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। वी. मैसूर राज्य और अन्य। ( 1) उच्च न्यायालय ने पाया कि सरकार में निहित निर्देश

इस आशय का आदेश कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोई सीट या सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें अन्य पिछड़े उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

वर्ग असंवैधानिक थे। इसने आरक्षण के कोटे की गणना करने के तरीके के बारे में कुछ निर्देश भी दिए। इसके बाद 16 मई, 1961 को नागन गौड़ा समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 10 जुलाई, 1961 को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य के लिए एक आदेश जारी किया। उस आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने 81 वर्गों के लोगों को पिछड़े वर्गों के रूप में और 135 वर्गों के लोगों को अधिक पिछड़े वर्गों के रूप में निर्दिष्ट किया और 30 प्रतिशत लोगों को आरक्षित किया।

( 1 ) ए. आई. आर. 1961 माई. 220 .



पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में सीटें। 15 % और 3 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं और शेष 52 प्रतिशत सीटों को योग्यता के आधार पर भरने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त आदेश को अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य से 31 जुलाई, 1962 को बनाए गए एक नए सरकारी आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस नए आदेश के अनुसार, 28 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्गों के लिए, 22 प्रतिशत अधिक पिछड़े वर्गों के लिए, 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 3 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत 68 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं और केवल 32 प्रतिशत सीटें योग्यता के आधार पर भरने के लिए उपलब्ध थीं। इस आदेश को एम. आर. बालाजी और अन्य मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। वी. मैसूर राज्य। ( 1) उस मामले में दिए गए निर्णय में जिसे संवैधानिक उच्चारणों में महत्वपूर्ण माना जाता है -

इस न्यायालय, न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर, (जैसा कि वे तब थे) ने पृष्ठों 459-461 पर संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में दिखाई देने वाले 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग' शब्द का अर्थ इस प्रकार समझाया:

" कला के तहत पिछड़ेपन। 15 ( 4 ) सामाजिक होना चाहिए

और शैक्षिक। यह या तो सामाजिक या शैक्षिक नहीं है, लेकिन

यह सामाजिक और शैक्षिक दोनों है और यह हमें इस स्थिति में ले जाता है

सवाल यह है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन कैसे तय करना पड़ता है।

आइये पहले सामाजिक पिछड़ेपन के सवाल को लेते हैं।

किस परीक्षण से यह तय किया जाएगा कि क्या कोई विशेष

वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा है या नहीं? नागरिकों का समूह

जिनके लिए अनुच्छेद 15 (4) लागू होता है, उन्हें 'वर्गों के रूप में वर्णित किया गया है

नागरिक ', नागरिकों की जातियों के रूप में नहीं। एक वर्ग के अनुसार

शब्दकोश के अर्थ में, समाज के विभाजन को दर्शाता है

स्थिति, पद या जाति के अनुसार। हिंदू समाज में

संरचना, जाति, दुर्भाग्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

नागरिक की स्थिति का निर्धारण करना। हालांकि इसके अनुसार

समाजशास्त्रियों और वैदिक विद्वानों के लिए, जाति व्यवस्था हो सकती है

मूल रूप से व्यावसायिक या कार्यात्मक रूप से शुरू किया है

मूल कार्यात्मक और व्यावसायिक आधार बाद में समाप्त हो गया था।अनुष्ठान के आधार पर शुद्धता के विचारों के साथ बोझिल

( 1 ) ( 1963 ] सप. एस. सी. आर 439

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवधारणाएँ और जो इसके प्रभावों को जन्म देती हैं जो परिचय कमजोर लचीलेपन और कठोरता। यह कृत्रिम वृद्धि

अनिवार्य रूप से श्रेष्ठता की भावना पैदा करने की प्रवृत्ति और हीनता और संकीर्ण जाति वफादारी को बढ़ावा देना। इसलिए,

नागरिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं, हो सकता है कि ऐसा न होउक्त समूह की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक है

नागरिक। तथापि, इस संबंध में यह आवश्यक है कि -

ध्यान रखें कि विशेष प्रावधान पर विचार किया गया है

नागरिकों के वर्गों के लिए और व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नहीं

इस तरह, और इसलिए, हालांकि नागरिकों के समूह की जाति

प्रासंगिक हो सकता है, इसके महत्व को अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए।

यदि नागरिकों के पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण था

केवल नागरिक की जाति के आधार पर, यह हमेशा नहीं हो सकता है

तार्किक हो और शायद स्थायी का दोष हो सकता है

जातियों को स्वयं।

इसके अलावा, अगर नागरिकों के समूह की जाति थी

सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने का एकमात्र आधार बनाया

उक्त समूह का नेस, वह परीक्षण अनिवार्य रूप से टूट जाएगा

भारतीय समाज के कई वर्गों के संबंध में जो

ज्ञात पारंपरिक अर्थों में जातियों को मान्यता न देंहिंदू समाज के लिए। कोई कैसे तय करेगा कि

मुसलमान, ईसाई या जैन, या यहाँ तक कि लिंगायत भी

सामाजिक रूप से, पिछड़े या नहीं? जातियों की परीक्षा होगी

उन समूहों के लिए लागू नहीं है, लेकिन यह शायद ही होगा

कला के संचालन से इन समूहों के बहिष्कार को उचित ठहराएँ। 15 ( 4 ) . यह संभावना नहीं है कि कुछ में

कुछ मुसलमानों या ईसाइयों या जैनों का गठन बताते हैं

समूह सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि

समूहों या नागरिकों के वर्गों का पिछड़ेपन, यह नहीं हो सकता हैउस ओर से एकमात्र या प्रमुख परीक्षा बनाई जाए।

सामाजिक पिछड़ेपन का परिणाम अंतिम विश्लेषण पर है। गरीबी, बहुत हद तक। नागरिकों के वर्ग

जो दयनीय रूप से गरीब हैं, वे अपने आप सामाजिक रूप से गरीब हो जाते हैं

पीछे की ओर। उन्हें समाज में कोई दर्जा नहीं मिलता है औरइसलिए, पीछे की सीट लेने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। यह.

यह सच है कि सामाजिक पिछड़ेपन के परिणामस्वरूप के विचार से गरीबी बढ़ने की संभावना है

जाति जिससे गरीब नागरिक संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वह के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (वेंकटरमैया, जे.)

केवल जाति और गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है

नागरिकों के पिछड़ेपन का निर्धारण करना।

नागरिकों के व्यवसाय भी नागरिकों के वर्गों को सामाजिक रूप से पिछड़े बनाने में योगदान दे सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हीन माना जाता है और इन व्यवसायों का पालन करने वाले नागरिकों के वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े होने के लिए उपयुक्त हैं। अधिवास का स्थान भी व्यक्तियों के समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने में एक छोटी भूमिका नहीं निभाता है। एक तरह से सामाजिक पिछड़ेपन की समस्या ग्रामीण भारत की समस्या है और इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग कला के दायरे में आते हैं। 15 ( 4 ) . यह निर्धारित करने की समस्या है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं

संदिग्ध रूप से बहुत जटिल। समाजशास्त्रीय, सामाजिक और

आर्थिक विचार हल करने में भूमिका निभाते हैं

समस्या और निर्धारण के लिए उचित मानदंड विकसित करना

कौन से वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कठिन कार्य है; इसके लिए एक विस्तृत जांच और डेटा के संग्रह और शून्य और वैज्ञानिक तरीके से उक्त डेटा की जांच करने की आवश्यकता होगी। यह उस राज्य का कार्य है जो कला के तहत कार्य करना चाहता है। 15 ( 4 ) . वह सब जो इस न्यायालय को करने के लिए कहा जाता है जो वर्तमान याचिकाओं को यह तय करने के लिए किया जाता है कि क्या विवादित आदेश द्वारा लागू किए गए परीक्षण कला के तहत मान्य हैं। 15 ( 4 ) . यदि यह प्रतीत होता है कि उस ओर से आदेश द्वारा लागू किया गया परीक्षण तात्कालिक और अमान्य है,

तो उस परीक्षण के आधार पर सामाजिक रूप से पिछड़े वार्ड वर्गों का वर्गीकरण कला की आवश्यकताओं के साथ असंगत माना जाएगा। 15 ( 4 ) . ”

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण के प्रश्न से निपटने के लिए, गजेंद्रगढ़कर, जे. (जैसा कि उन्होंने उसी मामले में पृष्ठों 463-464 पर इस प्रकार कहा था:

" यह स्वीकार किया जा सकता है कि नागरिकों के एक वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने में जनगणना रिपोर्ट द्वारा प्रदान की गई साक्षरता परीक्षा पर्याप्त नहीं हो सकती है; लेकिन यह संदेहपूर्ण है कि क्या पिछली तीन हाई स्कूल कक्षाओं में छात्र आबादी के औसत की परीक्षा पर्याप्त नहीं है।

शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण में उपयुक्त। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं, यह 448 मई को हो सकता है।

[ 1985 ] एसयूपीपीएल।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परीक्षण को उतना ऊंचा रखना आवश्यक या उचित नहीं है जितना है समिति द्वारा किया गया। लेकिन यह मानते हुए भी कि

लागू किया गया परीक्षण तर्कसंगत है और कला के तहत अनुमेय है। 15 ( 4 ) ,

सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या यह वैधानिक होगा। जाति या समुदायों के साथ व्यवहार करने के लिए साथी जो ठीक नीचे हैं

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में राज्य का औसत। अगर

राज्य का औसत 6.9 प्रति हजार है, एक समुदाय जो

उक्त परीक्षण को संतुष्ट करता है या उक्त परीक्षण से ठीक नीचे है

पिछड़े माने जाते हैं। यह केवल ऐसे समुदाय हैं जो

राज्य के औसत से काफी नीचे जिसे उचित रूप से माना जा सकता है

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में। के वर्ग

जिन नागरिकों की छात्र आबादी का औसत नीचे काम करता है50 राज्य के औसत का प्रतिशत स्पष्ट रूप से शिक्षा है।

नागरिकों के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। इसलिए, हमारे

राय, राज्य में शामिल करने में उचित नहीं था

पिछड़े वर्गों, जातियों या समुदायों की सूची जिनकी

प्रति हजार छात्र आबादी का औसत थोड़ा था

राज्य के औसत से ऊपर या बहुत करीब या उससे ठीक नीचे।

( हमारे द्वारा रेखांकित)

उपरोक्त नियम को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि समावेशन

बैकवी की सूची में लिंगायत समुदाय के सदस्यकक्षाएँ गलत थीं। आरक्षण की सीमा के प्रश्न पर, इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पी 469-471 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

" विद्वान महाधिवक्ता ने सुझाव दिया है कि

कमजोरों के लिए बड़ी संख्या में सीटों का आरक्षणसमाज के वर्ग गहराई को प्रभावित नहीं करेंगे

या छात्रवृत्ति की दक्षता, और इसके समर्थन में तर्क, उन्होंने द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है

पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली

मद्रास, आंध्र, त्रावणकोर-कोच्चि और

मैसूर जहाँ से उम्मीदवारों की भर्ती की प्रणालीआरक्षित कोटे में अन्य पिछड़े वर्ग हैं

कई दशकों से प्रचलन में है। समिति ने आगे कहा

देखा कि उच्च वर्गों के प्रतिनिधियों ने किया

कार्यालयों में दक्षता की कमी की शिकायत न करें

आरक्षण द्वारा भर्ती (पी। 135)। लेकिन यह राय, स्पष्ट रूप से असंगत है जो होने के लिए बाध्य है

उच्च विश्वविद्यालय में आरक्षण का अपरिहार्य परिणाम

शिक्षा. अगर पेशेवर और तकनीकी में प्रवेश

महाविद्यालयों का अनुचित रूप से उदारीकरण किया जाता है तो के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (वेंकटरमैया, जे.) का विरोध करना बेकार होगा।

ताकि हमारे स्नातकों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आरक्षण को अपनाया नहीं जाना चाहिए; समाज के कमजोर वर्गों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण को अपनाया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इस संबंध में विशेष उपाय करने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य समुदायों के योग्य और योग्य उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश से बाहर न किया जाए। कला द्वारा परिकल्पित एक विशेष प्रावधान। 15 ( 4 ) जैसे अनुच्छेद द्वारा अनुध्यात पदों और नियुक्तियों का आरक्षण। 16 ( 4 ) उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों के हितों को, जो राज्यों और केंद्र पर पहली जिम्मेदारी है, समग्र रूप से समुदाय के हितों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। इन प्रतिस्पर्धी दावों का समायोजन है

निस्संदेह एक कठिन मामला है, लेकिन यदि एक विशेष प्रावधान करने की आड़ में, एक राज्य व्यावहारिक रूप से सभी कॉलेजों में उपलब्ध सभी सीटों को आरक्षित करता है, तो यह स्पष्ट रूप से कला के उद्देश्य को नष्ट कर देगा। 15 ( 4 ) . इस मामले में फिर से, हम निश्चित रूप से क्या कहने के लिए अनिच्छुक हैं

यह एक उचित प्रावधान होगा। आम तौर पर और व्यापक रूप से, एक विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस विशेष मामले में, यह उल्लेखनीय है कि जब राज्य ने 10 जुलाई, 1961 को अपना आदेश जारी किया, तो उसने दृढ़ता से अपनी राय व्यक्त की कि नागन गोवाड़ा समिति द्वारा अनुशंसित 68 प्रतिशत आरक्षण राज्य के व्यापक हित में नहीं होगा। 10 जुलाई, 1961 और 31 जुलाई, 1962 के बीच जो हुआ, वह रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन राज्य ने अपना मन बदल लिया और अपने पहले के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि उक्त सिफारिश राज्य के व्यापक हितों के विपरीत थी। हमारी राय में, जब राज्य कला में निर्दिष्ट समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। 15 ( 4 ) , इसे अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से और तर्कसंगत तरीके से करना होगा। निस्संदेह, इसे कमजोर तत्वों की प्रगति में मदद करने के लिए उचित और यहां तक कि उदार कदम उठाने होंगे; समस्या की सीमा को तौलना होगा, इसकी आवश्यकताओं को समझना होगा।

बड़े पैमाने पर समुदाय को ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक सूत्र विकसित किया जाना चाहिए जो कई प्रासंगिक विचारों के बीच एक उचित संतुलन बनाएगा।

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1985] एसयूपीएल। एस सी आर।

450

हम संतुष्ट हैं कि 68 प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया गया है।

आक्षेपित क्रम से असंगत है स्पष्ट रूप से कला. 15 ( 4 ) . " ( जोर दिया गया)

इस तरह इस अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

इसके बाद 26 जुलाई, 1963 का सरकारी आदेश आया जिसमें निर्देश दिया गया कि पेशेवर और तकनीकी में 30 प्रतिशत सीटें

महाविद्यालयों और संस्थानों को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि उस क्रम में परिभाषित किया गया है और 18 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। द.

सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए उस क्रम में निर्धारित मानदंड दो गुना थे- आय और व्यवसाय। इसमें कहा गया है कि जो लोग कृषि, लघु व्यवसाय के व्यवसायों का पालन करते थे,

निम्न सेवा, शिल्प या अन्य व्यवसाय जिनमें शारीरिक श्रम शामिल है और जिनकी पारिवारिक आय रुपये से कम थी। 1,200 / - उनम के अनुसार पिछड़े वर्गों से संबंधित माना जाना था। यह आदेश था

डी. जी. विश्वनाथ बनाम में उच्च न्यायालय के समक्ष पूछताछ की गई। सरकार. मैसूर और ओआरएस। (1) विभिन्न आधारों पर कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा। उक्त याचिकाओं को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि

जाति के संदर्भ के बिना पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूरी तरह से सही नहीं था और इसने आशा व्यक्त की कि राज्य एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण करेगा ताकि इसकी प्रामाणिकता न हो।

बालाजी के मामले में निर्णय के साथ असंगत (ऊपर)। बालाजी के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई प्रासंगिक टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद ( ऊपर), जे. सुब्बा राव, (जैसा कि उन्हें तब देखा गया था) पृष्ठों 386-387 पर इस प्रकार देखा गया:

" उक्त टिप्पणियों से दो सिद्धांत प्रमुखता से सामने आते हैं, अर्थात् (i) नागरिकों के एक समूह की जाति उनकी सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है; और (ii) हालांकि यह नागरिकों के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है, लेकिन यह उस दिशा में एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं हो सकती है।

( 1 ) ए. आई. आर. 1964 माई. 132 . ( 2 ) [ 1964 ] 6 एस, सी. आर.

368 , के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.)

उच्च न्यायालय के निर्णय में निकाली गई टिप्पणियाँ

न्यायालय इस न्यायालय की टिप्पणियों के साथ टकराव में प्रतीत होता है। जबकि इस न्यायालय ने कहा कि जाति केवल एक प्रासंगिक परिस्थिति है और यह नागरिकों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने में प्रमुख परीक्षा नहीं हो सकती है,

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आधार हैपिछड़े हिंदुओं के वर्ग का निर्धारण करना और कि

सरकार को जाति को एक परीक्षा के रूप में अपनाना चाहिए था। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों से प्राधिकरण के मन में कुछ भ्रम पैदा हो सकता है संबंधित जिसे कर्तव्य सौंपा जा सकता है

कला के अर्थ के भीतर नागरिकों के वर्ग। 15 ( 4 ) संविधान के अनुसार, हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी करेंगे किजाति केवल एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक प्रासंगिक परिस्थिति है और निर्णय में कुछ भी नहीं है

इस न्यायालय का आदेश जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के एक समूह के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकता है यदि वह जाति के संदर्भ के बिना ऐसा कर सकता है। यद्यपि इस न्यायालय ने नागरिकों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने से जाति को बाहर नहीं किया है, लेकिन इसने इसे एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक आधार प्रदान करने वाली मजबूर करने वाली परिस्थितियों में से एक नहीं बनाया है। इसे रखने के लिए

अलग तरह से, संबंधित प्राधिकरण व्यक्तियों के समूह के पिछड़ेपन का पता लगाने में जाति को ध्यान में रख सकता है; लेकिन, यदि ऐसा नहीं होता है, तो उसका क्रम उस कारण से खराब नहीं होगा, यदि वह अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर व्यक्तियों के समूह के पिछड़ेपन का पता लगा सकता है।

( हमारे द्वारा रेखांकित)

आगे बढ़ते हुए, जे. सुब्बा राव (जैसा कि वे उस समय थे) आयु 388-389 को इस प्रकार व्यक्त करते हैं:

" कला में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कारक। 5 ( 4 ) यह है कि यह जातियों की बात नहीं करता है, बल्कि केवल वर्गों की बात करता है। अगर संविधान निर्माताओं का इरादा जातियों को लेना था

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की इकाइयों के रूप में भी उन्होंने ऐसा ही कहा होगा जैसा कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में कहा है। हालांकि यह

यह सुझाव दिया जा सकता है कि व्यापक अनुभव "वर्ग" का उपयोग सी. एल. में किया जाता है। ( 4 ) कला की। 15 क्योंकि जातियों के बिना समुदाय हैं, अगर जाति के साथ वर्गों की बराबरी करने का इरादा था, तो 452



संविधान के चिह्नों को कुछ भी नहीं रोकता था

"पिछड़े वर्ग या जातियाँ" अभिव्यक्ति का उपयोग करना।

"पीछे की ओर" अभिव्यक्ति का संयोजन

कला में वर्ग "और" अनुसूचित जाति "। 15 ( 4 ) लीड्स

यह एक उचित निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अभिव्यक्ति " "वर्ग" जातियों का पर्याय नहीं है। हो सकता है कि

यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई विशेष नागरिक या एक समूह

जाति की कुछ प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन यह भी नहीं हो सकतीसुनिश्चित करने के लिए एकमात्र या प्रमुख मानदंड

जिस वर्ग से वे संबंधित हैं।

यह व्याख्या के इरादे को पूरा करेगी

उपरोक्त अनुच्छेदों में व्यक्त संविधान। यह मदद करता है।

इसके बजाय वास्तव में पिछड़े वर्गों या इंट को बढ़ावा देना

व्यक्तियों या समूहों के अवशेष जो, हालांकि वे संबंधित हैं

किसी ऐसे राज्य में जाति जो संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा हो। यह हो सकता है कि हालांकि उस में अधिकांश लोग

जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, एक प्रभावी

अल्पसंख्यक सामाजिक और शैक्षिक रूप से कहीं अधिक विज्ञापन हो सकते हैं

एक अन्य छोटी-उप-जाति की तुलना में कुल संख्या

"वर्गों" को "जातियों" के रूप में व्यक्त करना संविधान का उद्देश्य है टच्यूशन निराश होगा और जो लोग नहीं करते हैं

किसी भी साहसिक सहायता के लायक होने के कारण इसे बहिष्कृत किया जा सकता है

जो वास्तव में योग्य हैं। यह विसंगति उत्पन्न नहीं होगी यदि,

जाति को वर्ग के साथ तुलना किए बिना, जाति को केवल माना जाता है

यह पता लगाने के लिए विचार में से एक कि क्या कोई व्यक्ति

पिछड़े वर्ग से संबंधित है या नहीं। दूसरी ओर, यदि

पूरी उप-जाति, मोटे तौर पर, पिछड़ी हुई है, हो सकता है

अनुमोदन का पालन करके अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया

संविधान द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रक्रिया "।

1972 में राज्य सरकार ने कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की।

एल. जी. हवानूर ने एक विस्तृत जांच के बाद 19 नवंबर, 1975 को चार विशाल खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पहले खंड में दो भाग थे। यह कहा गया है कि आयोग ने 378 गाँवों और कस्बों/शहर ब्लॉकों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की गणना की, जिसमें 453 से संबंधित 3,55,000 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया।



171 425 से अधिक की सहायता से जातियाँ और समुदाय

जांचकर्ता और पर्यवेक्षक। आयोग द्वारा लगभग 365 गवाहों से पूछताछ की गई। आयोग की रिपोर्ट सारणीबद्ध बयानों से भरी हुई है और यह समाजशास्त्रियों, डेमो ग्राफर्स, न्यायविदों और सामाजिक विज्ञान में पारंगत व्यक्तियों के कई लेखन का उल्लेख करती है। आयोग के काम की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि राज्य में अब तक पिछड़े वर्गों की स्थितियों की इतनी व्यापक जांच नहीं की गई थी। शायद किसी अन्य भाग की तुलना में

भारत, इस तरह की विस्तृत जांच कई सूक्ष्म विवरणों के संदर्भ में की गई थी। आयोग ने सिफारिश की कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को तीन समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए।( क) 15 जातियों वाले पिछड़े समुदाय, (ख) 128 जातियों वाली पिछड़ी जातियाँ और (ग) 62 जनजातियों वाली पिछड़ी जनजातियाँ। संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए, आयोग ने पिछड़े वर्गों को (ए) 9 जातियों वाले पिछड़े समुदायों में विभाजित किया। ( ख) 115 जातियों वाली पिछड़ी जातियाँ और (ग) 61 जातियों वाली पिछड़ी जनजातियाँ।

जनजातियाँ। आयोग के अनुसार, पिछड़े समुदाय वे जातियाँ थीं जिनका 1972 में प्रति हजार जनसंख्या पर एस. एस. एल. सी. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का छात्र औसत राज्य के औसत से कम था (जो प्रति हजार 1.69 था) लेकिन राज्य के औसत का 50 प्रतिशत से अधिक और पिछड़ी जातियाँ और पिछड़ी जनजातियाँ वे जातियाँ और जनजातियाँ थीं जिनका छात्र औसत राज्य के औसत से 50 प्रतिशत से कम था, सिवाय डोम्बर और वोद्दारों के और जो खानाबदोश और अधिसूचित जनजातियाँ थीं। आयोग के अनुसार इन पिछड़े वर्गों (अन्य तत्कालीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) की कुल आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 45 प्रतिशत थी। दोनों सूचियों के बीच अंतर एक

अनुच्छेद 15 (4) के तहत और दूसरा संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत कुछ समुदायों, जातियों और जनजातियों के बहिष्कार के कारण था जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे लेकिन जिनका अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य से तैयार की गई सूची से सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। आयोग ने अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) दोनों के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रतिशत की सिफारिश की:

आरक्षण:

|

( (i) पिछड़े समुदाय

16 प्रतिशत

( (ii) पिछड़ी जातियाँ

10 प्रतिशत

( (iii) पिछड़ी जनजातियाँ

6 प्रतिशत

32 प्रतिशत

कुल:



18 प्रतिशत के साथ 32 प्रतिशत का उपरोक्त आरक्षण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा की कुल राशि

कुल सीटों या पदों का 50 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो। आयोग ने आगे सिफारिश की कि यदि पिछड़े जनजातियों को आवंटित कोटे में सीटें/पद नहीं भरे जाते हैं, तो उन्हें पिछड़े समुदायों और पिछड़ी जातियों को सौंप दिया जाना चाहिए। इसी तरह अगर पिछड़ी जातियों को आवंटित कोटे में सीटें/पद खाली रहते हैं,

उन्हें पिछड़े समुदायों और पिछड़ी जनजातियों को सौंप दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि उन तीन श्रेणियों में से किसी को आवंटित कोटे में सीटें/पद खाली रहते हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सौंप दिया जाना चाहिए। इनमें से किसी भी श्रेणी द्वारा सीटें/पद खाली रहने की स्थिति में, उन्हें सामान्य पूल में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 22 फरवरी, 1977 को एक आदेश जारी किया, जिसका सामग्री भाग इस प्रकार है:

" 1 .

विभिन्न सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद

आयोग, सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:

I. इस आदेश से जुड़ी सूची में उल्लिखित पिछड़े समुदायों, पिछड़ी जातियों और पिछड़ी जनजातियों को उद्देश्यों के लिए पिछड़ा वर्ग माना जाएगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)। केवल इन पिछड़े वर्गों के ऐसे नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से प्रति वर्ष पारिवारिक आय रु। 8,000 ( केवल आठ हजार रुपये) और उससे कम इन अनुच्छेदों के तहत विशेष उपचार के हकदार होंगे।

II. निम्नलिखित पाँच श्रेणियों के नागरिकों को एक विशेष समूह माना जाएगा और ऐसे नागरिक विशेष समूह जिनकी पारिवारिक आय रु। 4,800 ( केवल चार हजार आठ सौ रुपये) और प्रति से कम

वर्ष इन अनुच्छेदों के तहत विशेष उपचार के लिए पात्र होगा:

( (i) एक वास्तविक कृषक;

( (ख) एक कारीगर;

( (ग) एक छोटा व्यापारी; ई. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमलाह, जे.)

455

( (iv) सरकार में या तो नियुक्ति रखने वाला व्यक्ति

सेवा या संबंधित सेवाएँ

आकस्मिक श्रम सहित निजी रोजगार; तथा

( (v) कोई भी व्यक्ति जो स्व-नियोजित है या शारीरिक श्रम से जुड़े किसी भी व्यवसाय में लगा हुआ है।

उपरोक्त उप-पैरा I और II के तहत पारिवारिक आय पर ध्यान दें।अर्थात् नागरिक और उसके माता-पिता की आय और यदि दोनों में से कोई एक

माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका कानूनी अभिभावक। III. संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े वर्गों और नागरिकों के विशेष समूह के संबंध में 40 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने के लिए, आवंटन निम्नानुसार है:

( क) पिछड़े समुदाय

20 ( बीस प्रतिशत)

10 ( दस प्रतिशत)

( ख) पिछड़ी जातियाँ

5 ( पाँच प्रतिशत)

( ग) पिछड़ी जनजातियाँ

5 ( पाँच प्रतिशत)

( घ) विशेष समूह

सरकारी आदेश में उल्लिखित पिछड़े समुदायों की सूची में, राज्य सरकार ने 'मुसलमानों' को शामिल किया, जिससे कुल 16 पिछड़े समुदाय बन गए। पिछड़ी जातियों की सूची में 129 जातियाँ थीं जिनमें ईसाई धर्म में परिवर्तित लोग भी शामिल थे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दूसरी पीढ़ी तक और 62 अनुसूचित जनजाति। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 40 प्रतिशत था और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 18 प्रतिशत के साथ, सीटों/पदों का कुल आरक्षण 58 प्रतिशत हो गया और योग्यता पूल के लिए केवल 42 प्रतिशत बचा। एक दिनांकित आदेश द्वारा

1 मई, 1979 को अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था। 27 जून, 1979 के एक आदेश द्वारा राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) दोनों के उद्देश्यों के लिए विशेष समूह के लिए आरक्षण को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके 22 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेश को संशोधित किया। इस प्रकार आज की तारीख में, अनुच्छेद 15 (4) के उद्देश्यों के लिए 68 प्रतिशत और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए कुल आरक्षण 66 प्रतिशत है। केवल 32 प्रति 456 हैं।

[ 1985 ] एसयूपीएफएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेशेवर और तकनीकी कॉलेजों में प्रतिशत सीटें और सरकारी सेवाओं में 34 प्रतिशत पद जो योग्यता के आधार पर भरे जा सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इन रिट याचिकाओं में

22 फरवरी, 1977 के उपरोक्त सरकारी आदेशों को

1 मई, 1979 और 27 जून के सरकारी आदेशों द्वारा संशोधित,

1979 चुनौती दी जाती है।

यहां यह कहा जाना चाहिए कि 22 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेशों और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों के लिए जारी 4 मार्च, 1977 की एक अन्य अधिसूचना को भी कई मामलों में चुनौती दी गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं का

एस. सी. सोमशेखरप्पा और अन्य में कर्नाटक का उच्च न्यायालय। वी. राज्य

कर्नाटक और अन्य। ( 1) उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति दी आंशिक रूप से। इसने 'अरासु' समुदाय को सूची में शामिल करने को रद्द कर दिया

' अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े समुदाय और

अनुच्छेद 16 (4)। इसने (i) बालजा, (ii) देवाडिगा, (iii) गंगिया, (iv) नयिंडा, (v) राजपूत और (vi) सतानी को पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल करने और (1) बन्हा, (2) गोरखा,

अनुच्छेद 16 के तहतः 4 ) राज्य को स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए रद्द कर दिया गया था सरकार तदनुसार आरक्षण की सीमा निर्धारित करेगी

कानून के साथ। अन्य मामलों में वर्गीकरण और आरक्षण को बरकरार रखा गया। एस. एल. पी 1979 का (सिविल) सं. 6656 उक्त के विरुद्ध दायर किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय का निर्णय। 1 मई, 1979 और 27 जून, 1979 के दो सरकारी आदेश, जिनमें पहले के शासन आदेशों को संशोधित करने का उल्लेख किया गया था, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद पारित किए गए थे, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था पर खंड लिखे गए हैं। जाति (वर्ण) की उत्पत्ति प्राचीन काल से हुई है। इसका उल्लेख हम वैदिक कथाओं और महान महाकाव्यों, स्मृतियों और पुराणों में पाते हैं। पुरुष सूक्त चार वर्णों (पूर्व) की व्यापकता को संदर्भित करता है (ऋग्वेद X-90-12 देखें)। भगवान कहते हैं कि

( 1 ) 1977 की रिट याचिका संख्या 4371 और संबंधित रिट याचिकाओं का 9 अप्रैल, 1979 को निपटारा किया गया।



भगवदगीता (IV-, 13) ने कहा कि गुण और कर्म के अलग-अलग वितरण से उनके द्वारा चार गुना जाति का निर्माण किया गया था। कई प्राचीन संधियों में वर्ण धर्म का गुणगान किया गया है। शुरुआत में समाज का विभिन्न जातियों में विभाजन भले ही प्रशंसनीय रहा हो, लेकिन बाद की कई शताब्दियों के दौरान ये जातियां भयभीत हो गईं और एक जाति से दूसरी जाति में जाना लगभग असंभव हो गया। व्यक्ति की जाति उसके जन्म से जानी जाती थी। समय के साथ जाति व्यवस्था पर एक सामाजिक पदानुक्रम का निर्माण हुआ। आई अपने पूरे जीवन के दौरान निम्न जाति का कलंक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था।

सभी परिचर नुकसानों के साथ। महाभारत के दुखद नायक करुआ का जन्म हालांकि एक क्षत्रिय राजकुमारी से हुआ था, लेकिन उन्हें पीड़ा उठानी पड़ी अपने पूरे जीवनकाल के दौरान उन्हें अपमानित किया गया क्योंकि उन्हें निम्न जाति के एक सारथी (सुता) के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें यह कहने के लिए कहा गया था कि 'मैं एक सारथी या एक सारथी का बेटा हो सकता हूं। मैं कोई भी शरीर हो सकता हूँ। यह क्या मैट करता है। एर? (उच्च) जाति में पैदा होना ईश्वर की इच्छा है लेकिन वीरता मेरी है। ( भट्ट नारायण की वेणी समारा देखें)।

में विभिन्न श्रेणियों की कई उप-जातियाँ थीं

पदानुक्रम। कुछ लोगों को अछूत भी माना जाता था। निम्न जातियों के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की। इस प्रकार वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हो गए। भारतीय इतिहास का यह हिस्सा वास्तव में निराशाजनक है। इतिहास का एक पृष्ठ तर्क के एक खंड के लायक है।

हम भारत में जाति, नस्ल या जनजाति या धार्मिक अल्पसंख्यकों के अर्थों से अवगत हैं। जाति एक संघ है

जो परिवार अंतर्विवाह की प्रथा का पालन करते हैं अर्थात जो केवल ऐसे परिवारों के सदस्यों के बीच विवाह की अनुमति देता है। जाति के नियम इसके सदस्यों को उनकी जाति के बाहर शादी करने से रोकते हैं। जातियों के बीच ऐसे उपसमूह हैं जो कभी आपस में शादी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। एक जाति विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, कभी-कभी यह एक वर्ग, एक जाति या एक जातीय इकाई हो सकती है। जाति का धन से कोई लेना-देना नहीं है। व्यक्ति की जाति परिवार में उसके जन्म से नियंत्रित होती है। अनुष्ठानिक शुद्धता के कुछ विचार प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट हैं। कभी-कभी जाति प्रथाओं के कारण गाँवों में समान जातियों का अलगाव भी हो जाता था। यहाँ तक कि जातियों के सदस्यों के व्यवसाय का चुनाव भी कई मामलों में पूर्व निर्धारित किया गया था, और एक विशेष जाति के सदस्यों को अन्य प्रकार

के आह्वान, पूर्वधारणा या व्यवसायों में खुद को शामिल करने से प्रतिबंधित किया गया था। कुछ व्यवसायों को अपमानजनक या अशुद्ध माना जाता था। कई मामलों में एक निश्चित मात्रा में कठोरता विकसित हुई और कई जो

:



सामाजिक व्यवस्था में निचली जातियों से संबंधित लोगों को कई प्रतिबंधों, विशेषाधिकारों और अपमानों का सामना करना पड़ा। कुछ जातियों के सदस्यों के खिलाफ अस्पृश्यता का अभ्यास किया जाता था। कुछ मामलों में अंतर भोजन प्रतिबंधित था। जाति को नियंत्रित करने वाले इनमें से किसी भी नियम का किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता या उसकी क्षमता से कोई लेना-देना नहीं था। उनके स्वामित्व वाली संपत्ति उन्हें संबंधित सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कई सामाजिक भेदभावों से नहीं बचाएगी। उच्च जातियों के लिए। इस जाति-ग्रस्त वातावरण में पले-बढ़े बच्चों को स्वाभाविक रूप से कई सामाजिक नुकसानों का सामना करना पड़ा, इसके अलावा उन्हें उसी तरह के वातावरण में रहने का अवसर नहीं मिला, जिसमें उच्च जाति के लोग रहते थे। पिछली दो शताब्दियों में कई समाज सुधारकों ने जाति के उस कलंक को दूर करने का प्रयास किया है जिससे निचली जातियों में पैदा हुए लोग पीड़ित थे। कुछ अमानवीय जाति प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले कई कानून भी पारित किए गए। संविधान के अनुच्छेद 15 (2) में प्रावधान है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या (ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उपयोग जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित हैं। अनुच्छेद 16 (2) में घोषणा की गई है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या वंश के आधार पर किसी भी नागरिक पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 17 ने 'अस्पृश्यता' और किसी भी रूप में इसकी प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर भी विभिन्न निचली जातियों के कई लोग जिन नुकसानों से पीड़ित थे, वे अभी भी इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनमें से कुछ ने आर्थिक रूप से प्रगति की है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न सामाजिक समस्याओं पर लिखते हैं जो विशिष्ट हैं -

उन शब्दों में भारत:

" जाति की अवधारणा और प्रथा कुलीन आदर्श को मूर्त रूप देती थी और स्पष्ट रूप से डेमो के खिलाफ थी।क्रेटिक अवधारणाएँ। इसमें कुलीन दायित्व की अपनी मजबूत भावना थी, बशर्ते लोग अपने वंशानुगत स्टेशनों पर रहें और स्थापित व्यवस्था को चुनौती न दें। भारत की सफलता और उपलब्धियाँ पूरी तरह से

उच्च वर्गों तक ही सीमित थीं; जो निम्न स्तर पर थे, उनके पास बहुत कम अवसर थे और उनके अवसर पूरी तरह से सीमित थे। ये उच्च वर्ग छोटे सीमित समूह नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में थे और उनमें शक्ति, अधिकार और प्रभाव का प्रसार था। इसलिए वे सफलतापूर्वक आगे बढ़े!



बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन जाति व्यवस्था और भारतीय सामाजिक ढांचे की चरम कमजोरी और विफलता यह था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मनुष्यों का अपमान किया और उन्हें शैक्षिक, सांस्कृतिक या आर्थिक रूप से उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं दिया। उस अवमूल्यन ने गिरावट लाई, जिसमें इसके दायरे में उच्च वर्ग भी शामिल थे। इसने पेट्रिफिकेशन को जन्म दिया जो भारत की अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता बन गई

और जीवन। इस सामाजिक संरचना और अतीत में कहीं और मौजूद लोगों के बीच अंतर बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन पिछली कुछ पीढ़ियों के दौरान दुनिया भर में हुए परिवर्तनों के साथ वे दूर हो गए हैं।

अधिक स्पष्ट। आज के समाज के संदर्भ में,जाति व्यवस्था और इसके साथ जो कुछ भी जाता है वह पूरी तरह से असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और जाति के पक्ष में बाधाएं हैं। इसके ढांचे के भीतर स्थिति और अवसर में कोई समानता नहीं हो सकती और न ही राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है।

और बहुत कम आर्थिक लोकतंत्र। इन दो अवधारणाओं के बीच संघर्ष अंतर्निहित है और उनमें से केवल एक ही जीवित रह सकता है। ( जवाहरलाल नेहरू: ' द डिस्कवरी ऑफ इंडिया '1974 एडन। पीपी में अध्याय VI। 256-257 ) .

भारतीय सामाजिक स्थितियों की पृष्ठभूमि में प्रश्न की जांच से पता चलता है कि अभिव्यक्ति 'पिछड़े' संविधान में उपयोग किए जाने वाले वर्ग केवल उन लोगों के लिए संदर्भित हैं जो थे

विशेष जातियों में पैदा हुए, या जो विशेष जातियों या जनजातियों या धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित थे जो पिछड़े थे।

अब संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 338 (3) और अनुच्छेद 340 में पाए जाने वाले 'पिछड़े वर्ग' अभिव्यक्ति के सही अर्थ का पता लगाना आवश्यक है। अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 340 संविधान के भाग XVI में 'विशेष' के हकदार हैं।

कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। प्रारूप संविधान में संबंधित भाग भाग XIV था जिसका शीर्षक था 'अल्पसंख्यकों से संबंधित विशेष प्रावधान' जिसमें नौ अनुच्छेद, अनुच्छेद 292 से 301 शामिल थे। संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 292 में लोकसभा में अल्पसंख्यकों, मुस्लिम समुदाय और अनुसूचित

जातियों, कुछ अनुसूचित जनजातियों और भारतीय ईसाई समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का उल्लेख किया गया है। संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 293 में इस संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है -

लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। संविधान के मसौदे का अनुच्छेद 295 आरक्षण से संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

राज्य विधानमंडलों में मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जातियों, कुछ अनुसूचित जनजातियों और भारतीय ईसाई समुदाय के लिए सीटें। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 295 ने राज्यपाल को कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के लिए अधिकृत किया। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 296 में संघ और राज्यों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी

राज्य सेवाओं में सभी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सदस्य लगातार प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हैं। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 297 में संघ को कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी जैसा कि उसमें कहा गया है और प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 298 में एक निश्चित निर्दिष्ट अवधि में एंग्लो-इंडियन समुदाय को कुछ शैक्षिक रियायतों का प्रावधान किया गया था। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 299 में राष्ट्रपति को संघ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी और राज्यपाल को राज्य के लिए अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 300 द्वारा कुछ अनुसूचित जनजातियों का कल्याण राष्ट्रपति को सौंपा गया था और इसने उस उद्देश्य के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया था। प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 301 ने राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया

कक्षाएँ। वह इस प्रकार है:

" 301. ( 1 ) राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों से युक्त एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उन कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जो वे श्रम करते हैं और उन कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए जो संघ या किसी राज्य द्वारा ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए जाने चाहिए और उन अनुदानों के बारे में जो संघ या किसी राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन ऐसे अनुदान दिए जाने चाहिए, और ऐसे आयोग की नियुक्ति का आदेश आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगा।

( 2 ) इस प्रकार नियुक्त आयोग उन्हें भेजे गए मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को एक -

रिपोर्ट उनके द्वारा पाए गए तथ्यों को निर्धारित करती है और ऐसी सिफारिशें करती है जो वे उचित समझते हैं।

टी.

461

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.)

( 3 ) ¡ राष्ट्रपति इस प्रकार रिपोर्ट की एक प्रति लाएंगे

प्रस्तुत, एक ज्ञापन के साथ समझाते हुए

उस पर की गई कार्रवाई को संसद के समक्ष रखा जाएगा।

संविधान सभा की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

भाग में निहित प्रावधानों पर अपनी सिफारिशें करने के उद्देश्य से 24 जुलाई, 1947 को नियुक्त सलाहकार समितिऊपर उल्लिखित प्रारूप संविधान के XIV ने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अपनाया जो इस प्रकार है:

" संकल्प लिया कि संविधान सभा आगे बढ़ेगी

11 मई की रिपोर्ट पर विचार करना

1949 कुछ राजनीतिक सुरक्षा उपायों के विषय पर

सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त अल्पसंख्यक

24 जनवरी को विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा पारित

1 47 .

1

आगे हल किया गया

( (i) पहले से लिए गए किसी भी निर्णय के बावजूद

इस संबंध में संविधान सभा द्वारा उपबंधभारत के संविधान के प्रारूप के भाग XIV का ऐसा होना चाहिए

की सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया उक्त रिपोर्ट में निहित सलाहकार समिति; और

( (ख) पूर्वी पंजाब में निम्नलिखित वर्ग, अर्थात् -

मजहबी, रामदासिया, कबीरपंथी और सिकलीगर हों।

प्रांत के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल

ताकि वे प्रतिनिधि के लाभ के हकदार हों।

विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों को दिया गया। ( बी. शिवा द्वारा 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीटयूशन' का वीडियो

राव, वॉल्यूम। IV पी। 606 ) .

संशोधित प्रारूप संविधान में जिसे प्रस्तुत किया गया था

3 नवंबर, 1949 को संविधान सभा, संबंधित प्रावधान

अल्पसंख्यकों को भाग XVI में शामिल किया गया था और उसका शीर्षक

भाग को 'अल्पसंख्यकों से संबंधित विशेष प्रावधान' के रूप में पढ़ा जाता है और यह

तेरह अनुच्छेद, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान और कुछ

लोक स्नभा और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है

राज्यों की विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण। लेख

331 और अनुच्छेद 333 के प्रतिनिधियों के वर्चस्व से संबंधित था

आई 462

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एंग्लो-भारतीय समुदाय क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए। अनुच्छेद 334 ने वह अवधि निर्धारित की जिसके दौरान उपरोक्त अनुच्छेदों के तहत आरक्षण और नामांकन किए जा सकते थे। अनुच्छेद 335 संघ और राज्यों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को संघ या राज्यों द्वारा नियुक्तियों में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ लगातार मान्यता देने की अपेक्षा करता है, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद 336 में संविधान के प्रारंभ के बाद पहले दो वर्षों के

दौरान कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान था और अनुच्छेद 337 में एक निश्चित अवधि के दौरान एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान था। संविधान के प्रारंभ के बाद की अवधि। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 338 (3) में कहा गया है कि अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भों को ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भों के रूप में माना जाना चाहिए जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने पर निर्दिष्ट कर सकते हैं और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए भी। अनुच्छेद 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उनके श्रम की कठिनाइयों की जांच करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में बताया गया है कि 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' शब्दों का क्या अर्थ है। उपरोक्त आरती क्लेस (कला। 330 से कला। संविधान के संशोधित मसौदे के 342) को अंततः संविधान सभा द्वारा इस संशोधन के साथ पारित किया गया कि 'अल्पसंख्यक' शब्द के लिए जहां भी यह भाग XVI में आया है, 'कुछ वर्गों' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए। इसलिए, भाग के शीर्षक को 'कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान' में बदल दिया गया था।

यह महत्वपूर्ण है कि पिछड़े वर्गों में प्रयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति

संविधान के भाग XVI और अनुच्छेद 338 (3) में विशेष का उपयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो-इंडियन समुदाय के साथ किया जाता है। मूल संविधान के मसौदे में भाग XVI में मुस्लिम समुदाय और भारतीय ईसाई समुदाय का भी उल्लेख किया गया था। बहस के दौरान इन समुदायों के साथ-साथ सिख समुदाय के सदस्यों के सवाल पर भी विचार किया गया। इसलिए पिछड़े वर्गों का अर्थ उससे पहले के अन्य शब्दों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाना चाहिए। यह वैधानिक निर्माण का एक नियम है कि जहां हैं

विशेष और विशिष्ट शब्दों के बाद आने वाले सामान्य शब्द, सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक सीमित होना चाहिए जो निर्दिष्ट हैं। यह सच है कि यह नियम जिसे एजुस्डेम जेनेरिस रूल या के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.) कहा जाता है।

463

नियम यह है कि एक समाज को बहुत दूर नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन उस नियम को लागू करना एक कारण है जहां विशिष्ट शब्द एक अलग जीनस या श्रेणी को संदर्भित करते हैं। अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ, जातियाँ और जनजातियाँ या जातियों, जातियों और जनजातियों के भीतर या समूहों के हिस्से हैं जो राष्ट्रपति द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना में निर्दिष्ट हैं।

अनुच्छेद 341 (1) '। इसी तरह अनुसूचित जनजातियाँ वे जनजातियाँ या आदिवासी हैं।

जनजातियों या जनजातियों के भीतर के समुदाय या भाग या समूहद्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना में निर्दिष्ट समुदाय

अनुच्छेद 342 (1) के तहत राष्ट्रपति। यह परिभाषाओं से स्पष्ट है

अनुच्छेद 366 (24) में 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' और

अनुच्छेद 366 (25)। , अनुच्छेद 341 के तहत जारी अधिसूचनाएं और अनुच्छेद 342 को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

( अनुच्छेद 341 (2) और अनुच्छेद 342 (2) के अनुसार। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भाग XVI

संविधान कुछ रियायतों से संबंधित है जो कुछ लोगों को दी गई हैं।

जातियाँ, जनजातियाँ और जातियाँ जो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित हैं

जनजातियों और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए। उपरोक्त संदर्भ में यदि

अनुच्छेद 338 (3) और अनुच्छेद 340 का अर्थ लगाया गया है, अभिव्यक्ति 'पीछे'वार्ड वर्ग केवल कुछ जातियों, नस्लों, जनजातियों या समुदाय को संदर्भित कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य राज्य या उनके भाग और एंग्लो-इंडियन समुदाय, जो पिछड़े हैं। इस प्रकार देखें

लक्षयों और उद्देश्यों के संबंध में संकल्प से भी समर्थन प्राप्त होता है

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया संविधान

13 दिसंबर, 1946 को राज्य सभा। उन्होंने कहा:

" मैं स्थानांतरित करने के लिए भीख माँगती हूँ:

( 1 ) यह संविधान सभा अपनी संस्था घोषित करती है और

भारत को स्वतंत्र घोषित करने का गंभीर संकल्प

संप्रभु गणराज्य और उसके भविष्य के लिए तैयार होने के लिए

शासन एक संविधान;

( 2 ) जिन क्षेत्रों में अब अंग्रेज शामिल हैं

भारत, वे क्षेत्र जो अब भारतीय राज्यों का निर्माण करते हैं।

और भारत के ऐसे अन्य भाग जो अंग्रेजों से बाहर हैं।

राज्यों के साथ-साथ ऐसे अन्य क्षेत्रों में भारत

स्वतंत्र में गठित होने के लिए तैयार हैं

संप्रभु भारत, उन सभी का एक संघ होगा; और

( 3 ) जहाँ उक्त क्षेत्रों में, चाहे उनके पूर्व के साथ

भेजी गई सीमाएँ या ऐसे अन्य के साथ जो हो सकता है

संविधान सभा द्वारा निर्धारित और वहाँ

संविधान के कानून के अनुसार, 464



स्वायत्त इकाइयों का दर्जा प्राप्त करना और बनाए रखना,अवशिष्ट शक्तियों के साथ, और सभी का प्रयोग करें

शक्तियाँ, और सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करें जैसा कि हैं

संघ में निहित या सौंपा गया है, या जैसा कि अंतर्निहित है

या संघ में निहित या उसके परिणामस्वरूप; और

( 4 ) जिसमें संप्रभु की सारी शक्ति और अधिकार है

स्वतंत्र भारत, इसके घटक भाग और अंग

सरकार, लोगों से बहक जाती है; और

( 5 ) जिसमें सभी के लिए गारंटी और सुरक्षित किया जाएगा

भारत के लोग न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिस्थिति की समानता, अवसर की, और इससे पहले

कानून, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास की स्वतंत्रता,

पूजा, व्यवसाय, संगठन और कार्य, के अधीन

कानून और सार्वजनिक नैतिकता; और

( 6 ) जिसमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र, और दलित

और अन्य पिछड़े वर्ग; और

( 7 ) जिसमें क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखा जाएगा।

समुद्र, और न्याय और कानून के अनुसार हवासभ्य राष्ट्र; और

( 8 ) यह प्राचीन भूमि अपना अधिकार और सम्मान प्राप्त करती है।

दुनिया में जगह और अपने पूर्ण और इच्छुक कॉन बनाओ

विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए क्लेश और

मानव जाति का कल्याण। " ( हमारे द्वारा रेखांकित)

उपरोक्त संकल्प का खंड (6) जिसे बाद में पारित किया गया था

संविधान सभा ने 'अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों' के लिए संविधान में पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का संकल्प लिया। उपरोक्त प्रस्ताव और संविधान सभा द्वारा संविधान के भाग XVI के अधिनियमन के इतिहास से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछड़े वर्ग

केवल वे जातियाँ, जातियाँ, जनजातियाँ या समुदाय हैं, जो जन्म से पहचाने जाते हैं, जो पिछड़े हैं। इससे पहले, यह मानना मुश्किल है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जो केवल पिछड़े हैं

आर्थिक कारणों से गरीबी के खाते को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और भाग XVI के उद्देश्यों के लिए पिछड़े वर्ग के रूप में भी माना जा सकता है।



'पिछड़े' शब्द 'वर्ग' शब्दों से पहले नहीं था।

संविधान के मूल मसौदे के अनुच्छेद 10 (3) में नागरिक (वर्तमान अनुच्छेद 16 (4))। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने जानबूझकर इसे पेश किया। डॉ. अम्बेडकर ने उस शब्द को इस प्रकार पेश करने का कारण बताया:

" उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी समुदाय या समुदायों के समूह के लिए आरक्षण किया गया था, कुल

जिनमें से कुछ राज्य के तहत कुल पदों का 70 प्रतिशत था और केवल 30 प्रतिशत को अनारक्षित के रूप में रखा गया है, क्या कोई यह कह सकता है कि सामान्य प्रतिस्पर्धा के लिए खुले के रूप में 30 प्रतिशत का आरक्षण पहले सिद्धांत को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से संतोषजनक होगा, अर्थात् अवसर की समानता होगी? यह मेरे निर्णय में नहीं हो सकता है। इसलिए आरक्षित की जाने वाली सीटें, यदि आरक्षण अनुच्छेद 10 के उपखंड (1) के अनुरूप होना है, तो कम सीटों तक ही सीमित होनी चाहिए। तभी पहला सिद्धांत संविधान में अपना स्थान पा सकता है और प्रभावी (एस. आई. सी.) हो सकता है। यदि माननीय सदस्य इस स्थिति में खड़े हैं तो हमें दो चीजों की रक्षा करनी होगी, अर्थात्, अवसर की समानता का सिद्धांत और साथ ही उन समुदायों की मांग को पूरा करना होगा जिनका राज्य में अब तक प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मुझे यकीन है कि वे इस बात पर सहमत होंगे कि जब तक आप "पिछड़े" के रूप में कुछ योग्यता वाले वाक्यांश का उपयोग नहीं करते हैं, तब तक आरक्षण के पक्ष में किया गया अपवाद अंततः नियम को पूरी तरह से खा जाएगा। नियम का कुछ भी नहीं रहेगा। ( संविधान के माध्यम से

विधानसभा बहस, 1948-1949, खंड। VII, पीपी। 701-702 ) .अभिव्यक्ति वर्गों को अर्हता प्राप्त करके मसौदा समिति

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में 'पिछड़े' नागरिकों ने तीन अलग-अलग दृष्टिकोणों को मिलाने की कोशिश की और एक व्यवहार्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया

प्रस्ताव जो सभी को स्वीकार्य था, तीन दृष्टिकोण थे: (1) सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए और किसी विशेष पद के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को उस पद के लिए आवेदन करने, परीक्षाओं में बैठने और अपनी योग्यता का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह पद के लिए योग्य है या नहीं और कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, अवसर की समानता के सिद्धांत के संचालन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए; (2) यदि अवसर की समानता का सिद्धांत लागू होना था तो किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए या 466



समुदाय और यह कि सभी नागरिक यदि योग्य हैं तो होना चाहिए

जहां तक सार्वजनिक सेवाओं की बात है, उन्हें समानता के समान आधार पर रखा गया है(3) यद्यपि अवसर की समानता का सिद्धांत

कुछ समुदायों के प्रवेश के लिए बनाया गया है जो अब तकप्रशासन के बाहर। में चर्चा की पूरी अवधि

संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण देने की ओर इशारा किया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित जनसंख्या

जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे। चर्चा के दौरान, संविधान

(प्रथम संशोधन) विधेयक जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 (4) प्रस्तुत किया गया था,

वर्ग कुछ और नहीं बल्कि कुछ जातियों का संग्रह है '(परिला) मेंटरी डिबेट 1951, तीसरा सत्र, भाग II खंड। बारहवीं पी। 9007 ) .

यह कथन एक उचित निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि यह था जिसका अर्थ है कि संविधान सभा ने किसी भी स्थान पर वर्गों को सौंपा है

जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, दर।

बालाजी के मामले में (ऊपर) और चित्रलेखा के मामले में (ऊपर) यह

न्यायालय ने 'वर्ग' अभिव्यक्ति की बराबरी करने में बहुत हिचकिचाहट दिखाई

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए 'जाति' के साथ

संविधान। इसने देखा, जैसा कि पहले कहा गया है, कि जबकि जाति हो सकती है

एक पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है

हालाँकि, प्रमुख परीक्षण नहीं होना चाहिए। न देने के कारणों में से एक

जाति को हिंदू समुदाय के रूप में स्वीकार करना जिसमें जाति व्यवस्था

एक निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख परीक्षण के रूप में प्रचलित था

पिछड़े वर्ग का कहना था कि चूंकि जातियों के बिना समुदाय थे, इसलिए संविधान निर्माताओं को अभिव्यक्तियों का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सका

सायन 'पिछड़े वर्ग या जातियाँ'। उपरोक्त दो निर्णयों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 15 में 'पिछड़े वर्ग' और 'अनुसूचित जाति' अभिव्यक्ति के संयोजन से यह निष्कर्ष निकला कि 'वर्ग' अभिव्यक्ति का पर्याय नहीं था।

' जाति '। न्यायालय ने ये टिप्पणियां करते समय जाति व्यवस्था की बुराइयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जिसके कारण कुछ जातियों के लोग पिछड़े हुए थे और संविधान के भाग XVI और अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के अधिनियमन से पहले बहस हुई थी। वास्तव में भारतीय सामाजिक संस्थानों के इतिहास की अनदेखी की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माता बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसी कई जातियाँ हैं जिनके सदस्यों की शर्तें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों की शर्तों के लगभग समान थीं और उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में दिए जाने की आवश्यकता थी

उनके के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.) के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए सुरक्षा

467

प्रगति जो इतनी गरीबी के कारण नहीं थी, बल्कि एक विशेष जाति में उनके जन्म के कारण थी। जैसा कि इस फैसले के दौरान कहीं और उल्लेख किया गया है। 'वर्ग' शब्द को प्रतिस्थापित किया गया था संविधान सभा द्वारा अंतिम समय में शब्द 'समुदाय'। 'समुदाय' शब्द का अर्थ था हिंदुओं या मुसलमानों, या भारतीय ईसाइयों या एंग्लो-इंडियंस के बीच एक जाति। भाग XVI को गरीब वर्गों की स्थितियों को कम करने के उद्देश्य से अधिनियमित नहीं किया गया था, जिसका ध्यान संविधान के भाग IV के प्रावधानों और विशेष रूप से अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद द्वारा रखा गया था। 15 ( 1 ) और कला। 16 : 1 ) संविधान जिसने सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवहार के लिए आर्थिक आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण की अनुमति दी।

यह महत्वपूर्ण है कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार,

तथापि, माइनर पी. राजेंद्रन बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा संशोधित किया गया। मद्रास राज्य और अन्य।, ( 1) आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र। वी. पी. सागर, (1) त्रिलोकी नाथ और अन्र। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। ( 3) ए. पीरियाकरुप्पन आदि। टॉमिल नाडु और अन्य राज्य। ( 1) और आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य। वी. यू. एस. वी. बलराम आदि (5) राजन में

द्रान का मामला (ऊपर) यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उस जिले के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आवंटन, जिससे कोई उम्मीदवार संबंधित है, अनुच्छेद द्वारा वारंट नहीं था। 15 ( 4 ) , न्यायालय ने कहा कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है तो अनुच्छेद के तहत ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण दिया जा सकता है। 15 ( 4 ) सागर के मामले में (ऊपर) सीटों का बंटवारा पूरी तरह से जाति या समुदाय के आधार पर किया गया था। इस तथ्य का कोई निर्धारण नहीं हुआ कि क्या ऐसी जातियों या समुदायों के सदस्य वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। अदालत ने आरक्षण को रद्द कर दिया क्योंकि

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के बाहर होना। अदालत। हालांकि,

पृष्ठ 600 पर इस प्रकार देखा गया है:

" जिस संदर्भ में यह अभिव्यक्ति "वर्ग" होती हैइसका अर्थ है लोगों का एक सजातीय वर्ग

कुछ समानताओं या सामान्य लक्षणों के कारण एक साथ

और जिन्हें कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है जैसे कि

किसी स्थान, जाति में स्थिति, पद, व्यवसाय निवास के रूप में,

( 1 ) [ 1968 ] 2 एससीआर 786।

( 2 ) [ 1968 ] 3 एससीआर 595।

( 3 ) ( 1969 ] 1 एस. सी. आर 103

( 4 ) [ 1971 ] 2 एस. सी. आर 430

( 5 ) [ 1972 ] 3 एस. सी. आर. 247, [1985] एस. यू. पी. पी. एल.

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धर्म और इसी तरह। यह निर्धारित करने में कि क्या एक पार्टी

कुलर वर्ग एक वर्ग बनाता है, जाति को बाहर नहीं किया जा सकता है

कुल मिलाकर। लेकिन एक वर्ग का निर्धारण केवल एक परीक्षा है

जाति या समुदाय के आधार पर भी सफलता नहीं मिल सकती है।

टेड। सीएल द्वारा। ( 1 ) , कला. 15 राज्य को विवाद करने से रोकता है केवल धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ खनन,

जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी। सीएल द्वारा। ( 3 )

कला की। 15 राज्य, प्रावधानों के बावजूद है

सी. एल. में निहित। ( 1 ) , विशेष प्रावधान करने की अनुमति

महिलाओं और बच्चों के लिए। सीएल द्वारा। ( 4 ) एक विशेष प्रावधान

किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति के लिए

नागरिकों के पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के लिए

और अनुसूचित जनजाति सी. एल. के दायरे से बाहर है। ( 1 ) .

लेकिन सी. एल. ( 4 ) सीएल के लिए एक अपवाद है। ( 1 ) . अपवाद होने के नाते, यह

गारंटी को नष्ट करने के लिए प्रभावी रूप से बढ़ाया नहीं जा सकता है

सी. एल. ( 1 ) . संसद ने सी. एल. को अधिनियमित किया है। ( 4 ) ध्यान दें।

नागरिकों की समानता के अधिकार के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए

लोगों के कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताएँ

उनकी प्रगति के लिए प्रावधान करने की अनुमति देकर। ताकि यह प्रभाव सी. एल. को दिया जा सके। ( 4 ) , होना ही चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष प्रावधान के लाभार्थी हैं

ऐसे वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं और

वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अलावा अन्य हैं।

जनजातियाँ, और यह कि किया गया प्रावधान उनके अग्रिम के लिए है

मन में। आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए अपनाया जा सकता है

समाज के कमजोर वर्गों के हित, लेकिन ऐसा करने में,

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह योग्य और योग्य है।

पिछड़ेपन केवल धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान और पिछड़ेपन

सामाजिक और शैक्षिक होने के लिए समान होना चाहिए

पिछड़ेपन जिससे अनुसूचित जातियाँ और

अनुसूचित जनजातियाँ पीड़ित होती हैं "। ( जोर दिया गया)

त्रिलोकी नाथ के मामले में (ऊपर) जो एक ऐसा मामला था जिसमें ए. आर.

विचार के लिए आई, इस सी की एक संविधान पीठ

पृष्ठ 105 पर इस प्रकार लिखा है:

" अनुच्छेद 16 पहली बार में सी. एल. द्वारा। ( 2 ) जमीन पर, अन्य बातों के साथ-साथ, धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, निवास के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और एक अपवाद को के. सी. वी. के. वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.) होने की अनुमति देता है।

पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के मामले में किया गया

नागरिकों के वर्ग। "पिछड़ा वर्ग" अभिव्यक्ति का उपयोग "पिछड़ी जाति" या "पीछे" के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है।

वार्ड समुदाय "। एक पूरी जाति के सदस्य या

किसी दिए गए समय में मूल्यों का पैमाना पिछड़ा हो सकता है और उस कारण से इसे पिछड़े वर्ग के रूप में माना जा सकता है, लेकिन यह इसलिए नहीं है क्योंकि वे एक जाति या समुदाय के सदस्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक वर्ग बनाते हैं। अपने सामान्य अर्थ मेंअभिव्यक्ति "वर्ग" का अर्थ है लोगों का एक समरूप वर्ग जो कुछ समानताओं या समानताओं के कारण एक साथ समूहीकृत है।

सामान्य लक्षण, और जो कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे स्थिति, पद, व्यवसाय, निवास द्वारा पहचाने जा सकते हैं स्थानीयता, नस्ल धर्म और इसी तरह। लेकिन इस उद्देश्य के लिए

कला की। 16 ( 4 ) यह निर्धारित करने में कि क्या कोई वर्ग एक वर्ग बनाता है, पूरी तरह से जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर एक परीक्षा को अपनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सीधे संविधान का उल्लंघन करेगा।

यह "। ( जोर दिया गया)

पीरियाकरुप्पन के मामले में (ऊपर) हेगड़े। जे. में देखा गया

इस प्रकार:

" एक जाति को हमेशा एक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। "महामहिम के विषयों के वर्ग" अभिव्यक्ति को जोड़ते हुए

एस में पाया गया। 153 - भारतीय दंड संहिता का ए, वासूदेव,

जे. नारायण वासुदेव बनाम में देखा गया। सम्राट ए. आई. आर. 1943

बम। 379 .

" मेरी राय में संहिता की धारा 153-ए में 'महामहिम के विषयों के वर्ग' अभिव्यक्ति का उपयोग प्रतिबंधात्मक अर्थों में एक सामान्य और विशिष्ट पदनाम वाले व्यक्तियों या समूहों के संग्रह को दर्शाने के रूप में किया जाता है और यह भी कि सामान्य और अनन्य चरित्र भी होते हैं जो उनकी उत्पत्ति, नस्ल या धर्म से जुड़े हो सकते हैं, और यह कि उस खंड के भीतर 'वर्ग' शब्द अपने साथ संख्यात्मक शक्ति का विचार रखता है जो इतना बड़ा है कि एक में समूहीकृत किया जा सकता है।एकल सजातीय समुदाय "।

पिछड़े वर्गों के पैराग्राफ 10, अध्याय 5 में कहा गया है: एस रिपोर्ट में, यह देखा गया है:

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" हमने जाति से बचने की कोशिश की लेकिन हमें यह मुश्किल लगता है

वर्तमान परिस्थितियों में जाति की उपेक्षा करें। हम.

काश सामाजिक पिछड़ेपन से अलग होना आसान होता

वर्तमान समय में। आधुनिक समय में

सिलाई को अपनाते हुए, जाति से दर्जी नहीं बनता, न ही ब्राह्मण के रूप में उनकी सामाजिक स्थिति कम हुई है। ए.

ब्राह्मण बूट और जूते बेचने वाला हो सकता है, और फिर भी

इससे उनकी सामाजिक स्थिति कम नहीं होती है। सामाजिक

इसलिए, आज पिछड़ेपन के कारण नहीं है

एक व्यक्ति का विशेष पेशा, लेकिन हम नहीं कर सकते

सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए जाति से बचना

भारत में "

उस रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में कहा गया है:

" यह मान लेना गलत नहीं है कि सामाजिक पिछड़ेपन

शैक्षणिक पिछड़ेपन में काफी योगदान दिया है

बड़ी संख्या में सामाजिक समूह "।

अंत में अनुच्छेद 13 में समिति निम्नलिखित के साथ समाप्त होती है -

टिप्पणियाँ:

" यह सब साबित करता है कि सामाजिक पिछड़ेपन

जातीय, जनजातीय, जाति और संप्रदायों पर आधारित मतभेद "।

इसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 444 पर कहा:

" इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि कई हैं

इस देश में ऐसी जातियाँ जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से

पीछे की ओर। उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना तथ्यों को नजरअंदाज करना है।

जीवन से। इसलिए हम विवाद को बनाए रखने में सक्षम हैं।

कि विवादित आरक्षण कला के अनुसार नहीं है।

15 ( 4 ) . लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।

इस आधार पर आगे बढ़ें कि एक बार एक वर्ग के रूप में माना जाता है पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग बना रहना चाहिए

हर समय के लिए। इस तरह का दृष्टिकोण बहुत ही शुद्ध को हरा देगा।

आरक्षण की स्थिति क्योंकि एक बार एक वर्ग एक चरण तक पहुँच जाता है

प्रगति जिसे कुछ आधुनिक लेखक टेक ऑफ स्टेज कहते हैं

तब उनकी भविष्य की प्रगति के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है।सरकार को हमेशा समीक्षा में रहना चाहिए

सीटों और केवल 471 वर्गों के आरक्षण का सवाल

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.)

वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने चाहिए

आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति। सीटों के आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों ने सामान्य पूल में लगभग 50 प्रतिशत सीटें हासिल की हैं, यह दर्शाता है कि प्रश्न की नए सिरे से व्यापक परीक्षा का समय आ गया है। यह याद रखना चाहिए कि इस संबंध में सरकार का निर्णय न्यायिक है

समीक्षा "।

बलराम के मामले (ऊपर) में राज्य अपीलार्थी था। यह आंध्र उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील में आया था

जिस प्रदेश ने अनुच्छेद 15 (4) के तहत सीटों के आरक्षण के अपने आदेश को रद्द कर दिया था। इस न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान सरकारी आदेश, जे. वैद्यलिंगम को बरकरार रखते हुए अपील को स्वीकार कर लिया।

पृष्ठ 280 पर इस प्रकार देखा गया है:

" कला. 15 ( 4 ) नागरिकों के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए प्रभावी होना होगा, जैसा कि राज्य ने किया हैइस तरह के कर्तव्य के लिए आरोपित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम जानते हैं कि इस खंड के तहत किया गया कोई भी प्रावधान अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं के भीतर होना चाहिए और केवल जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और इस तरह की जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो सकती है। अगर इकट्ठा करने के बाद

आवश्यक तिथि पर, यह पाया जाता है कि समग्र रूप से जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है, हमारी राय में, ऐसे व्यक्तियों के आरक्षण को इस तथ्य के बावजूद बनाए रखना होगा कि उस समूह के कुछ व्यक्ति सामाजिक और शैक्षिक रूप से सामान्य औसत से ऊपर हो सकते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में कई जातियां हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और इसलिए राज्य को कला में आरोप के अनुसार एक उपयुक्त प्रावधान करना होगा। 15 ( 4 ) उनके हितों की रक्षा करने के लिए।

विद्वान न्यायाधीश ने महसूस किया कि पिछड़े वर्ग आयोग, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आदेश पारित किया गया था, ने अपनी सिफारिशों के समर्थन में अच्छे कारण दिए थे। तदनुसार सरकारी आदेश को बरकरार रखा गया।

472

[ 1985 ] एसयूपीपीएल। एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अगर हम इस दृष्टिकोण से अलग होते हैं कि जाति या समुदाय एक है

सामाजिक और शैक्षिक निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़ेपन

संविधान, कई विकृतियों का पालन करने की संभावना है और हो सकता है

हमें एकमात्र उद्देश्य से दूर ले जाएँ जिसके लिए वे संवैधानिक हैं

प्रावधान लागू किए गए। शारीरिक अक्षमता जैसे कई कारक,

गरीबी, निवास का स्थान, स्वतंत्रता से संबंधित होने का तथ्य

योद्धा का परिवार, एक सदस्य के परिवार से संबंधित होने का तथ्य

प्रत्येक सशस्त्र बल के उद्देश्य के लिए एक एकमात्र कारक बन सकता है

अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) जिसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था

राज्य द्वारा राहत देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया

मामले। जबकि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 14 के तहत राहत दी जा सकती है,

अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) एक तर्कसंगत सिद्धांत को अपनाते हुए

उन्हें। अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) लाभ के लिए हैं। जो जातियों/समुदायों से संबंधित हैं जो पारंपरिक रूप से

जिसे नापसंद किया गया है और जिसने सामाजिक भेदभाव का सामना किया है

अतीत। ऊपर वर्णित अन्य कारक कभी भी समकालीन नहीं थे।

इन खंडों को अधिनियमित करते समय संविधान निर्माताओं का गठन।

डी. एन. चंचला बनाम मैसूर राज्य और ओआरएस। आदि (1) एक वर्गीकरण

इनमें से कुछ कारकों के आधार पर अनुलेखन को बरकरार रखा गया था, लेकिन अनुच्छेद 15 (4) के तहत नहीं। केरल राज्य बनाम में किया गया अवलोकन। कुमार टी. पी. रोशना और अन्र। ( 2) आरक्षण का सिद्धांत

मालाबार जिले के भौगोलिक क्षेत्र के लिए महत्व उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के समर्थन में हमारी मंजूरी है जो अनुच्छेद 15 (4) के दायरे से बाहर है, भले ही इसे अनुच्छेद 14 के तहत बनाए रखा जा सके। जबकि जाति या समुदाय सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को रोकने में एक प्रासंगिक कारक है, यह नहीं कहा जा सकता है।

कि एक जाति के सभी सदस्यों को पिछड़े के रूप में माना जाना चाहिए और अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण का हकदार होना चाहिए। जाति-सह-साधन परीक्षण उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक तर्कसंगत परीक्षण होगा जो उन प्रावधानों के लाभ के हकदार हैं। इस सिद्धांत को कुमारी के. एस. जयश्री और अन्र में इस न्यायालय के हाथों स्वीकृति मिली है। वी. केरल राज्य और ए. एन. आर. , ( 3) उस मामले में केरल राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए नियुक्त एक आयोगउस राज्य के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और

( 1 ) [ 1971 ) सप. एससीआर 608। ( 2 ) [ 1979 ] 2 एस सी आर 974। ( 3 ) [ 1977 ] 1 एस सी आर 194.

यह सिफारिश करने के लिए कि लोगों के किन वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत लाभ दिया जाना चाहिए, पाया गया कि कुछ जातियों या समुदायों में से केवल अमीर ही पहले किए गए आरक्षण का लाभ उठा रहे थे। इसलिए, यह सिफारिश की गई है

लोगों के उन वर्गों को निर्धारित करने के लिए एक साधन-सह-जाति/सामुदायिक परीक्षण को अपनाना जिन्हें इसके तहत लाभ दिया जाना चाहिए। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया कि वे आवेदक जो कुछ जातियों के सदस्य थे

या ऐसे समुदाय जिनकी पारिवारिक आय रुपये से कम थी। 10,000 प्रति वर्ष केवल अनुच्छेद 15 (4) के तहत आरक्षण के हकदार थे। उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता जो ऐसे ही एक समुदाय से था, लेकिन जिसकी पारिवारिक आय रुपये से अधिक थी। 10,000 प्रति वर्ष केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर आदेश पर सवाल उठाया गया कि पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा लागू करना असंवैधानिक था। याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसकी अनुमति दी। द.

हालाँकि, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और याचिका को खारिज कर दिया। अपील पर, यह न्यायालय पृष्ठ 199-200 पर सामाजिक पिछड़ेपन के प्रश्न पर उपरोक्त मामले में खंड पीठ के निर्णय की पुष्टि करते हुए इस प्रकार है:

" नागरिकों के एक वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में नागरिकों के समूह की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। हालाँकि जाति को एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं बनाया जा सकता है। सामाजिक पिछड़ेपन टी में है

उनकी जाति के विचारों से उत्तेजित होना। यह नागरिकों के पिछड़ेपन को रोकने में जाति और गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है। गरीबी अपने आप में सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारक कारक नहीं है। गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन के संदर्भ में प्रासंगिक है। आयोग ने पाया कि निम्न आय समूह

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का गठन करता है। आरक्षण का आधार आय नहीं है, बल्कि प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर निर्धारित सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन है। यदि नागरिकों के पिछड़े वर्गों का कोई भी वर्गीकरण पूरी तरह से नागरिकों की जाति पर आधारित है तो यह जाति व्यवस्था की बुराई को कायम रखेगा। एक बार फिर, यदि वर्गीकरण पूरी तरह से गरीबी पर आधारित है तो यह तर्कसंगत नहीं होगा। समाज लोगों के उत्थान के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे कार्य समूहों या वर्गों में जो सामाजिक और 474 हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को समाज द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कि

यह हमारे संविधान का दर्शन है। इस संदर्भ में

वह सामाजिक पिछड़ेपन जो गरीबी के कारण होता हैजाति संबंधी विचारों से बड़े होने की संभावना है। व्यवसाय

राज्य, निवास स्थान भी प्रासंगिक कारक हो सकते हैं

यह निर्धारित करना कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से कौन पिछड़े हैं

कक्षाएँ। सामाजिक और आर्थिक विचार आते हैं

समस्या को हल करने और उचित को विकसित करने में संचालन सामाजिक रूप से कौन से वर्ग हैं, यह निर्धारित करने के मानदंड और

शैक्षिक रूप से पिछड़े। इसलिए हमारा संविधान सामाजिक और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान

जातियाँ और जनजातियाँ। यह केवल समाज को निर्देशित करके औरराज्य उन्हें सामाजिक और सामाजिक सुविधाओं के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

शिक्षा का उत्थान कि समस्या का समाधान हो गया है। इसमें यह है कि

संदर्भ कि आयोग ने वर्तमान मामले में पाया

परिशिष्ट VIII उनके निर्धारण में एक प्रासंगिक कारक था।सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन "।

जब एक बार जाति की प्रासंगिकता का पालन नहीं किया जाता है तो कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में निर्णय से देखा जा सकता है। प्रदीप टंडन और ओआरएस।, ( 1) उस मामले में न्यायालय को एक सरकारी आदेश की वैधता की जांच करनी थी जिसने

अनुच्छेद 15 (4) के तहत दो वर्गों के छात्रों के पक्ष में सीटों का आरक्षण-(1) वे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए थे और (2) वे जो पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तराखंड से आए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुभाष चंद्र बनाम में उक्त आरक्षण को बरकरार रखा। यू. पी. और अन्य का राज्य। ( 2) लेकिन दिलीप कुमार बनाम में बाद के एक मामले में उन्हें मार दिया। यू. पी. और अन्य की सरकार। ( 3) सुभाष चंद्र के मामले में अपने पहले के फैसले पर ध्यान दिए बिना (ऊपर) जब राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील में यही सवाल इस अदालत के समक्ष आया, तो राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों के वर्गीकरण को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया कि यह एक कुख्यात तथ्य था कि ग्रामीण, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश के लिए छात्रों का वर्गीकरण किया गया था।

उत्तराखंड क्षेत्र अत्यधिक गरीबी के कारण सामाजिक रूप से पिछड़े थे; कि वे क्षेत्र शैक्षिक रूप से पिछड़े थे क्योंकि

( 1 ) [ 1975 ] 2 एस. सी. आर 761 ( 2 ) ए. आई. आर. 1973 ऑल। 295 . ( 3 ) ए. आई. आर. 1973 ऑल। 592 .



साक्षरता का स्तर खराब था और शैक्षिक सुविधाओं की कमी थी और उक्त क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी थी।

वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए उक्त क्षेत्रों में भौगोलिक, क्षेत्रीय, ऐतिहासिक और आर्थिक स्थितियों पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में v. पी. दीप टंडन के मामले (ऊपर) अदालत ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया कि पी: कला के उद्देश्यों के लिए वर्गीकरण का आधार हो सकता है। 1 ( 4 ) पृष्ठ 7 पर इन शब्दों में:

" बालाजी के मामले (ऊपर) में न्यायालय ने कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन का अंतिम विश्लेषण इसका परिणाम है -काफी हद तक गरीबी और पिछड़े वर्गों की समस्या वास्तव में ग्रामीण भारत की समस्या है। इन टिप्पणियों को निकालते हुए महान्यायवादी

उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी न केवल प्रासंगिक है बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने वाले तत्वों में से एक है। हम गरीबी की परीक्षा को सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए निर्णायक कारक के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

तब इसने माना कि गरीबी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण असंवैधानिक था। ऐसा करते हुए यह पृष्ठ 769 पर देखा गया

इस प्रकार:

" ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण इस आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरक्षण राज्य की बहुसंख्यक आबादी के लिए बनाया गया है। 80 राज्य की आबादी का प्रतिशत एक सजातीय वर्ग नहीं हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण का समर्थन करने के लिए वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती है। भारत के सभी हिस्सों में गरीबी पाई जाती है। सीटों के आरक्षण के निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि आवेदन पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों से आरक्षित सीटों के लिए एक उम्मीदवार को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिससे वह संबंधित था और उसका वहां स्थायी घर था, और वह वहां रह रहा है या वह भारत में पैदा हुआ था और उसके माता-पिता और अभिभावक अभी भी वहां रह रहे हैं और वहां अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म की घटना है

बुनियादी योग्यता प्राप्त की। जन्म स्थान के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

लेकिन इसने पहाड़ी के पक्ष में किए गए आरक्षण को बरकरार रखा और

पृष्ठ 767 पर इन टिप्पणियों के साथ उत्तराखंड क्षेत्र:

" उत्तर प्रदेश में पहाड़ी और उत्तराखंड आर्कस

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के उदाहरण हैं

इन कारणों से कक्षाएं। पिछड़ेपन का आकलन किया जाता है

आर्थिक आधार कि प्रत्येक क्षेत्र का अपना मापने योग्य है

मानव संख्या के रखरखाव की संभावनाएँ,

जीवन और अचल संपत्ति के मानक। एक से

आर्थिक दृष्टिकोण से नागरिकों के वर्ग वापस आ गए हैं

वार्ड जब वे संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं करते हैं।

जब भूमि के बड़े क्षेत्र एक विरल, अव्यवस्थित बनाए रखते हैं

और अनपढ़ आबादी जिनकी संपत्ति कम है और सामाजिक पिछड़ेपन का तत्व न के बराबर देखा गया है।

जब प्रभावी क्षेत्रीय विशेषज्ञता संभव नहीं है

संचार और तकनीकी साधनों का अभाव

पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों की प्रक्रियाएँ

वे नागरिकों के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं। उपेक्षा की गई

अवसर और दूरदराज के लोग दीवारें उठाते हैं

लोगों का सामाजिक पिछड़ेपन।

शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाया जाता है

इन कारकों का संदर्भ। जहाँ लोगों के पास पारंपरिक हैसामाजिक और पर्यावरण के कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता

मानसिक स्थितियाँ या व्यावसायिक बाधाएँ, यह एक

शैक्षिक पिछड़ेपन का चित्रण। पहाड़ी और

उत्तराखंड क्षेत्र दुर्गम हैं। की कमी है

शैक्षणिक संस्थान और शैक्षणिक सहायता से लोग

पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्र शैक्षिक रूप से दर्शाते हैंशिक्षा की कमी के कारण नागरिकों के पिछड़े वर्ग

सुविधाएँ उन्हें स्थिर रखती हैं और उनका कोई मतलब नहीं है

शिक्षा के लिए न तो जागरूकता और न ही मूल्य।

उपरोक्त परिच्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि

निर्णय के एक भाग और दूसरे भाग के बीच असंगति है। न्यायालय ऊपर निर्धारित दो अलग-अलग निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आग्रह किए गए कई कारण लगभग समान थे। यह पहले के दृष्टिकोण के कारण है

न्यायालय द्वारा इस प्रश्न को अपनाया गया। अगर जाति को लिया गया होता

एक प्रासंगिक परीक्षा के रूप में विचार जिसे अनुच्छेद 15 (4) और कला के लाभ के हकदार वर्गों का निर्धारण करने में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 16 ( 4 ) , उपरोक्त के लिए कोई जगह नहीं होगी

असंगतता।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.)

477

संविधान के अनुच्छेद 14 के दो भाग हैं। यह पूछता है

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करने के लिए भी कहता है। कानून के समक्ष समानता कानून में किसी भी भेदभाव के अभाव को दर्शाती है। समान सुरक्षा की अवधारणा के लिए राज्य को सभी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार करने की आवश्यकता थी। यह इस नियम का आधार है कि समानता के सिद्धांत, जो हमारे संविधान की आधारशिलाओं में से एक है, को

विधिवत लागू करना है तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। असमान लोगों के बीच न्याय करने के लिए, राज्य को क्षतिपूर्ति या सुरक्षात्मक भेदभाव का सहारा लेना पड़ता है, संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) को सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों को राहत देने के लिए क्षतिपूर्ति या सुरक्षात्मक भेदभाव के उपायों के रूप में अधिनियमित किया गया था। इनके तहत, केवल ऐसे व्यक्तियों को ही शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण का प्रावधान करना संभव है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों से संबंधित नहीं हैं और

अल्पसंख्यक लेकिन जो अन्यथा कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, गरीबी, निवास स्थान, समान अवसर की कमी आदि के कारण सवाल उठता है कि क्या ऐसा आरक्षण संविधान के किसी अन्य प्रावधान जैसे अनुच्छेद 14 के तहत उनके पक्ष में किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 (1), अनुच्छेद 16 (1) या अनुच्छेद 46। केरल और अन्र राज्य में निर्णय। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। ( 1) जिसे इस न्यायालय के सात विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था

उपरोक्त प्रश्न के साथ। उस मामले के तथ्य ये थे: केरल राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के नियम 13 (ए) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एस. एस. आर. वी. एस. या किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास ऐसी विशेष योग्यता न हो और उसने ऐसी विशेष परीक्षाएँ उत्तीर्ण नहीं की हों जो विशेष नियमों में उस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं। अपर डिवीजन क्लर्क के अगले उच्च पद पर लोअर डिवीजन क्लर्क की पदोन्नति के लिए, सरकार ने कुछ विभागीय परीक्षा निर्धारित की। नियम 13ए द्वारा, जिसे बाद में पेश किया गया था, दो साल की अवधि के लिए अस्थायी छूट दी गई थी। उस नियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि एक कर्मचारी जिसने परीक्षा शुरू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर एकीकृत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे निचले पद पर वापस भेज दिया जाएगा और आगे कहा जाएगा कि वह उस नियम के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इस नियम के प्रावधान (2) ने संबंधित उम्मीदवारों के मामले में दो साल की विस्तारित अवधि के लिए अस्थायी छूट दी।

( 1 ) [ 1976 ] 1 एससीआर 906।



जाति और अनुसूचित जनजाति और वे जो दिए गए उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं थे, उदाहरण के लिए न्यूनतम योग्यताओं में से एक यानीदो साल की आगे की अवधि के दौरान निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना। रे, सी. जे. ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण को बरकरार रखते हुए नियम को बरकरार रखा। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने पृष्ठ 933 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

" समानता के लिए सभी वैध तरीके उपलब्ध हैं

अनुच्छेद 16 (1) के तहत सेवाओं में अवसर। अनुच्छेद 16 (1)

अनुच्छेद 16 (1) में सन्निहित समानता। अनुच्छेद 16 (1) का उपयोगअभिव्यक्ति "समानता" इसे सभी के लिए संबंधित बनाती है।

नियुक्ति के माध्यम से रोजगार के मामले

कानून या राज्य की कार्रवाई के उद्देश्य और उद्देश्य के अलावाद्वारा निषिद्ध भेदभाव से संबंधित वर्गीकरण

इसमें वर्गीकरण शामिल है। वर्गीकरण की वैधताकानून के उद्देश्य के संदर्भ में निर्णय लिया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में वर्गीकरण उचित है क्योंकि 479

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमलाह, जे.)

वर्गीकरण का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को सीमित सीमा तक पदोन्नति द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। दृष्टिकोण से

दान देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है।

उन्हें दक्षता के अनुरूप समानता "।

न्यायमूर्ति खन्ना, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, का विचार था कि चूंकि विवादित नियम को अनुच्छेद 16 (4) का संरक्षण नहीं मिलता है, जो एकमात्र प्रावधान था जिसके तहत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों को पूर्व क्रूर व्यवहार दिया जा सकता था, इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता था। विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 939-940 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

" अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि व्यवहार की समानता उचित वर्गीकरण को मना नहीं करती है। फिक्शन। इस संदर्भ में इस सर्वमान्य सिद्धांत का उल्लेख किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है लेकिन वर्गीकरण को मना नहीं करता है। अनुमेय वर्गीकरण, यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है, एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं और अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जो वांछित है।

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किया गया। यह आग्रह किया जाता है कि यही सिद्धांत तब लागू होना चाहिए जब न्यायालय राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता से संबंधित हो। इस संबंध में मैं यह देख सकता हूं कि इस न्यायालय ने उन मामलों में अनुच्छेद 16 के खंड (1) के संदर्भ में वर्गीकरण के सिद्धांत को मान्यता दी है जहां नियुक्तियां दो अलग-अलग स्रोतों से होती हैं, जैसे कि गार्ड और स्टेशन मास्टर, पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती, डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक इंजीनियर। [ अखिल भारतीय देखें

स्टेशन मास्टर्स और सहायक। स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन। और ओआरएस। वी. महाप्रबंधक, मध्य रेलवे और अन्य। [ 1960 ] 2 एस. सी. आर. 311, एस. जी. जयसिंहानी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। [ 1967 ] 2 एस. सी. आर. 703 और जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खेसा और अन्य। [ 1974 ] 1 एस. सी. आर. 771) हालाँकि, हम जिस प्रश्न से चिंतित हैं, वह है सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एसयूपीपीएल।

एस.

क्या हम वर्गीकरण के उपरोक्त सिद्धांत का विस्तार कर सकते हैं

कर्मचारियों को अधिमान्य व्यवहार की अनुमति देने के लिए यह आधार कि वे अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं

और अनुसूचित जनजातियाँ। जहाँ तक इस सवाल का सवाल है

मेरा विचार है कि तरजीही व्यवहार का प्रावधान

पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए, जिनमें

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, वह है जो निहित है

अनुच्छेद 16 के खंड (4) में जो आरक्षण की अनुमति देता है -

उनके लिए पोस्ट। इस तरह की वर्तनी की कोई गुंजाइश नहीं है।

के खंड (1) की भाषा से अधिमान्य उपचार

अनुच्छेद 16 क्योंकि उस खंड की भाषा नहीं है किसी भी नागरिक को किसी अन्य नागरिक के खिलाफ वरीयता का आश्वासन देता है

नागरिक। अनुच्छेद 16 के खंड (4) के प्रारंभिक शब्द कि

नियुक्तियों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करना या नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों का संकेत

कि लेकिन खंड (4) के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होता

नियुक्तियों या पदों का कोई आरक्षण करने के लिए

नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग का पक्ष लेना।

खन्ना, जे. ने पृष्ठ 944 पर इस प्रकार अवलोकन किया:

" मामले को दूसरे से भी बंद किया जा सकता है।

कोण। यदि अनुकूल उपचार देने की अनुमति थी

अनुच्छेद के खंड (1) के तहत पिछड़े वर्गों के सदस्यों को

16 , खंड डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती

( 4 ) अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में खंड (4)

घटना को पूरी तरह से अनावश्यक माना जाना चाहिए और

अनावश्यक। व्याख्या का सामान्य नियम यह है कि नहीं

संविधान के प्रावधान को पुनर्स्थापित माना जाना चाहिए

गंदी और अनावश्यक। अतः न्यायालय यह होगा कि एक दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक जिसका प्रभाव होगा

अनुच्छेद 16 के खंड (4) को निरर्थक बनाना औरअनावश्यक "।

मैथ्यू, जे. रे, सी. जे. से कमोबेश सहमत थे। उन्होंने पी.

955 इस प्रकार:

" ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद 16 (4) विशेष रूप से प्रदान करता है

पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण के लिए

जो इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार होगा

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (जे. वेंकटरमैया) में आरक्षण देने की राज्य की शक्ति शामिल करें।

पदोन्नति का चरण भी और इसलिए अनुच्छेद 16 (1)

इसके दायरे में कानून द्वारा या अन्यथा पिछड़े वर्गों को कोई साहसिक सहायता देने की शक्ति शामिल नहीं की जा सकती है जो सख्त संख्यात्मक समानता से अपमानजनक होगी। यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए रोजगार के मामले में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए या तो प्रारंभिक चरण में या पदोन्नति के चरण में या दोनों में आरक्षण आवश्यक है

लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि अनुच्छेद 16 (1) के तहत इसकी अनुमति क्यों नहीं है, क्योंकि केवल यही उन्हें अवसर की समानता से उत्पन्न होने वाले परिणाम को प्राप्त करने के मामले में अग्रगामी समुदायों के साथ समानता पर रख सकता है। अवसर की समानता का अंदाजा लगाया जा सकता है या नहीं।

केवल परिणाम में प्राप्त समानता से। औपचारिक

अवसर की समानता केवल अधिक शिक्षा और बुद्धि वाले लोगों को सभी पदों पर कब्जा करने और शिक्षा और प्रतिभा में कम भाग्यशाली लोगों को जीतने में सक्षम बनाती है, भले ही प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हो। परिणाम की समानता परीक्षा है

अवसर की समानता "।

बेग, जे. (जैसा कि वे तब थे) खन्ना के दृष्टिकोण से सहमत थे कि वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रकृति के मामलों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता था, लेकिन नियम को पूरी तरह से एस. सी. अनुच्छेद 16 (1) के भीतर आने के रूप में बरकरार रखा। उन्होंने पृष्ठ 959 पर कहाः

" कड़ाई से कहें तो, मेरे विद्वान भाई खन्ना द्वारा अपनाया गया विचार, कि "सार्वजनिक सेवा से संबंधित मामलों में अवसर की समानता" के विशेष संरक्षण का दायरा, जिसे नागरिकों के पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है, अनुच्छेद 16 द्वारा समाप्त हो गया है।

( 4 ) संविधान अपरिहार्य प्रतीत होता है। आखिरकार, अनुच्छेद 16 उनके द्वारा अपनाए गए महान सिद्धांतों का एक पहलू है।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 14। यह गारंटी देता हैः " सार्वजनिक नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता "। यह पूर्ण रूप से ऐसा करता है। यह एक आवश्यक परिणाम है औरएक महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुच्छेद 14 का विशेष अनुप्रयोग जहां अवसर की समानता से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 16 (1) सकारात्मक पहलू को निर्धारित करता है

राज्य द्वारा रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 (2) संविधान के अनुच्छेद 16 (1) द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में अनुच्छेद 16 (2) में दिए गए आधारों पर भेदभावपूर्ण राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रतिबंधित करता है।

अनुसूचित जातियाँ अनुच्छेद 16 (2) के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन नागरिकों के "पिछड़े वर्ग" के रूप में, प्रत्यक्ष निषेध से बचती हैं क्योंकि अनुच्छेद के प्रावधान हैं।

16 ( 4 ) उनके लिए इस तरह के पलायन को संभव बनाएं। वे सकारात्मक के आवश्यक परिणामों से भी बच सकते हैं।

अनुच्छेद 16 (1) का अधिदेश यदि वे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में निहित एकमात्र अपवाद के भीतर आते हैं। मैं सम्मानपूर्वक अपने विद्वान भाई खन्ना से सहमत हूँ।

इस क्षेत्र में अवसर की समानता का सिद्धांत अनुच्छेद 16 (4) द्वारा इसका व्यक्त संवैधानिक अधिकार '।

बेग, जे. (जैसा कि वे तब थे) पेज पर पकड़ रखने के लिए आगे बढ़े

" एक पिछड़े वर्ग के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव कहा जा सकता है यदि गंभीर परीक्षण निर्धारित किए गए थे उन्हें। लेकिन, हमारे सामने मामले में यह स्थिति नहीं है।

किसी भी वर्ग, जाति या पंथ से संबंधित सभी पदोन्नतों को समान रूप से एक ही प्रकार और मानक के दक्षता परीक्षण के अधीन किया जाता है। विवादित नियम किसी भी वर्ग या समूह के लिए इन परीक्षणों को समाप्त नहीं करते हैं। वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए, यहां तक कि एक पिछड़े वर्ग के रूप में भी इस तरह के परीक्षण नहीं किए जा सकते थे। यह सब होता है। यहाँ यह है कि कर्मचारियों के पिछड़े वर्ग को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने और इस तरह के परीक्षणों द्वारा निर्धारित अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक समय दिया जाता है। इसमें है।

इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में पर्याप्त समानता है। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि यदि अनुच्छेद 16 (1) की व्याख्या थोड़ी कम कठोरता और अधिक उदारता से की जा सकती है तो इसमें शामिल भेदभाव इसके बाहर नहीं आएगा। भले ही यह एक स्थायी दृष्टिकोण था, मैं यहां दिए गए सभी कारणों के लिए, यदि यह संभव है, तो अनुच्छेद 16 (4) के स्पष्ट प्रावधानों में औचित्य खोजना पसंद करूंगा क्योंकि यहीं पर इस तरह का औचित्य वास्तव में निहित होना चाहिए।”

कृष्ण अय्यर, जे. केरल के अधिवक्ता का बयान दर्ज करने के बाद कि नियम को बनाए नहीं रखा जा सका अनुच्छेद 16 (4) ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत इसे बरकरार रखा।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यों के लिए

ईएस। शायद उन्होंने नियम को रद्द कर दिया होता अगर लाभ होता।

शासन का विस्तार अन्य पिछड़े वर्गों तक किया गया था जो हो सकता है

पृष्ठ 981 पर आने वाले निम्नलिखित अंश से:

" अगर कला। 14 उचित वर्गीकरण को स्वीकार करता है, इसलिए करता है

कला. 16 ( 1 ) और इस न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। वर्तमान में

मामला, आर्थिक प्रगति और संवर्धन

घोर रूप से कम प्रतिनिधित्व और दयनीय रूप से दावे

उपेक्षित वर्ग, अन्यथा अनुसूचित जाति के रूप में वर्णित

और अनुसूचित जनजातियाँ, लगातार रखरखाव के साथ

प्रशासनिक दक्षता, उद्देश्य है, संवैधानिक रूप से

कला में तारीख। 16 ( 1 ) . अंतर इतना जोर से बाधा डालने वाला है, हरिजनों का निराशाजनक सामाजिक परिवेश है। निश्चित रूप से यह

ऊपर दी गई वस्तु के साथ एक तर्कसंगत संबंध। मुझे करना ही पड़ेगा।

पहले दिए गए सावधानी के नोट को दोहराएँ। सभी जातियाँ नहीं

इस सूत्र में पिछड़ेपन को पहचाना जाता है। ऐसा करने के लिए

दोनों कलाओं का विध्वंसक। 16 ( 1 ) और (2)। द सोशल डिस

समानता इतनी गंभीर और पर्याप्त होनी चाहिए कि एक के रूप में काम करे

सौम्य भेदभाव की नींव। अगर हम खोजते हैं ऐसा वर्ग, हम इसके अलावा कोई बड़ा खंड नहीं पा सकते हैं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। कोई और।जाति, कला से छूट प्राप्त करना। 16 ( 1 ) और (2) द्वारा

राजनीतिक दबाव या अन्य प्रभाव डालना, चलाएगा

असंवैधानिक भेदभाव का उच्च जोखिम। अगर असली

वर्गीकरण का आधार जाति है जो पिछड़े वर्ग के रूप में छिपी हुई है, न्यायालय को इस तरह के सांप्रदायिक हेरफेर पर प्रहार करना चाहिए।

दूसरा, संविधान केवल के दावों को मान्यता देता है

कला की रूपरेखा। 46 कमोबेश एक ही है। तो, हम कर सकते हैं आसानी से मान लें कि जातिवाद पीछे से वापस नहीं आ सकता है

दरवाजा और, असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों को छोड़कर, कोई अन्य वर्ग नहीं

हरिजन 'समान अवसर' की बाजी मार सकते हैं।

गारंटी। उनकी एकमात्र आशा कला में है। 16 ( 4 ) " . ( जोर दें।

प्रदान किया गया)।

गुप्ता, जे. एग्री ने आम तौर पर खन्ना, जे. के साथ काम किया और

उच्च न्यायालय का आदेश। गुप्ता, जे. अनुच्छेद 335 का उल्लेख करने के बाद

= पृष्ठ 986 पर लिखा है:

" यह अनुच्छेद सदस्यों में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एसयूपीपीएल।

8 .

वे सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के मामले में दावा कर सकते हैं; उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16 (4), उन्हें स्वीकार किए गए दावों का पता लगाने के लिए कहीं और देखना होगा। अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि ऐसे दावों पर प्रशासनिक दक्षता के साथ लगातार विचार किया जाएगा, इस प्रकार यह एक ऐसा प्रावधान है जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के रूप में उनके दावों को व्यापक नहीं बनाता है, लेकिन उन्हें योग्य बनाता है। अनुच्छेद 335, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, अनुच्छेद 16 (1) की समझ के लिए कोई संकेत प्रदान नहीं कर सकता है।

फज़ल अली, जे. ने अनुच्छेद 1 के तहत विवादित नियम को भी बरकरार रखा विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 1001 पर इस प्रकार कहा:

" संविधान के अनुच्छेद 335 में राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर लगातार विचार करने और प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का आदेश दिया गया है। पदोन्नति पाने वालों को विशेष रियायतें देकर सरकार द्वारा इस व्यक्ति तिथि का पालन करने की कोशिश की जाती है। प्रतिवादी नंबर 1 के वकील श्री टी. एस. कृष्णमूर्ति अय्यर ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद में दिया गया जनादेश। 335 इसका उल्लंघन किया जाता है क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को छूट देने से सेवाओं की दक्षता का स्तर प्रभावित होगा। हालाँकि, हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 और पदोन्नत दोनों एक ही सेवा के सदस्य थे और

वे काफी लंबे समय से लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। पदोन्नति प्राप्त करने वाले जो योजनाबद्ध जातियों और जनजातियों के सदस्य थे, वे निश्चित रूप से नंबर 1 का जवाब देने के लिए वरिष्ठ हैं और उन्होंने अधिक अनुभव प्राप्त किया है। इसके अलावा नियम पदोन्नत व्यक्तियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूरी छूट नहीं देता है; यह केवल उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाने के लिए समय देने का प्रावधान करता है। इन परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि आर को शामिल करने में राज्य की कार्रवाई। 13 - एए किसी भी तरह से कला में निहित जनादेश का उल्लंघन करता है। 335. इन परिस्थितियों में, इसलिए, मैं स्पष्ट रूप से संतुष्ट हूं कि आर में दिया गया निष्कर्ष।

13 - एए एक उचित वर्गीकरण के बराबर है जो कर सकता है कला के तहत बनाया जाए। 16 ( 1 ) संविधान के अधीन है और यह प्रतिवादी संख्या 1 के चयन के बराबर नहीं है।

शत्रुतापूर्ण भेदभाव ताकि कला का उल्लंघन हो। 16 भारत का संविधान ", 485

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.)

लेकिन जे. फजल अली का विचार था कि अनुच्छेद 16 (4)

जहाँ तक पदों के आरक्षण की बात है, संविधान की एक पूर्ण संहिता थीचिंतित था। विद्वान न्यायाधीश ने पृष्ठ 1002 पर इस प्रकार टिप्पणी की:

" कला का खंड (4)। 16 संविधान नहीं हो सकता है

कला. 16 ( 1 ) & ( 2 ) . मान लीजिए कि कई पिछड़े हैं वर्ग जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं

देश लेकिन ठीक से या पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि नहीं है

राज्य के तहत सेवाओं में प्रश्न जो उत्पन्न होता है

क्या किया जा सकता है ताकि वे सेवाओं में शामिल हो सकें

और समान भागीदारी की भावना रखें। एक कोर्स है

कला के तहत एक उचित वर्गीकरण करना। 16 ( 1 ) में

जिस तरह से मैं पहले ही बहुत विस्तार से बता चुका हूँ।

लक्षय प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह हो सकता है किपिछड़े वर्गों के लिए इस तरह से उपयुक्त आरक्षण

ताकि पिछड़े वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो

वर्गीकरण जिसे आरक्षण के रूप में संदर्भित किया जाता है, मेरे में है राय, स्पष्ट रूप से कला द्वारा कवर की गई। 16 ( 4 ) संविधान का

जो इस मुद्दे पर पूरी तरह से निंदनीय है। वह यह है कि कला का खंड (4) कहें। 16 कला कोई अपवाद नहीं है। 14 में

इस अर्थ में कि जो भी वर्गीकरण किया जा सकता है

केवल कला के खंड (4) के माध्यम से किया गया। 16. कला का खंड (4)।

16 , हालाँकि, एक विस्तृत व्याख्या है

और आरक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान जो एक है

वर्गीकरण के रूप। इस प्रकार कला का खंड (4)। 16

विशेष रूप से आरक्षण से संबंधित है न कि अन्य रूपों से

वर्गीकरण जो कला के तहत किया जा सकता है। 16 ( 1 ) स्वयं।

चूँकि खंड (4) आरक्षण के संबंध में एक विशेष प्रावधान है।

यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यह कला को ओवरराइड करता है। 16 ( 1 ) इसके लिए

कला के तहत कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है। 16 ( 1 ) " .

( जोर दिया गया)

परिणाम यह है कि कम से कम चार विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार

खन्ना; बेग, गुप्ता और फजल अली, जेजे। पदों का कोई आरक्षण नहीं हो सकता है

सहित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में किया जाना

अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

16 ( 1 ) . कृष्ण अय्यर के अनुसार, जे. तरजीही व्यवहार जैसा कि था

इस मामले में वर्गीकरण के आधार पर आमतौर पर किया जा सकता है

अनुच्छेद 16 (1) के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिया गया

केवल जनजातियाँ। अपवाद को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग ऐसा नहीं कर सके।

दुर्लभ मामलों को समान लाभ दिया जाए और उनकी एकमात्र आशा थी

संविधान का अनुच्छेद 16 (4)।



अब रेसर बनाने के लिए सरकार की शक्ति पर लौटना

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत, हम

यह इस प्रकार कहा जा सकता है: इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या किसी जाति या समूह या समुदाय के सदस्य वापस आ गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजन के लिए वार्ड इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान सरकार पर छोड़ दिया गया है। लेकिन यह खुला नहीं है।

सरकार को किसी भी जाति या समूह या समुदाय को वापस बुलाने के लिए

अपनी मीठी इच्छा और आनंद के अनुसार कार्य करें और लाभों का विस्तार करें।

जो उन प्रावधानों के तहत ऐसी जाति या समूह को दिया जा सकता है या

समुदाय। सरकार द्वारा अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग

इस संबंध में राजनीतिक पक्षपात हो सकता है जिससे इनकार किया जा सकता है

उन वर्गों की न्यायसंगत आवश्यकताएँ जो वास्तव में पिछड़े हैं। शक्ति। किसी भी जाति या समूह या समुदाय को वर्गीकृत करने के लिए सरकार का

पिछड़े को दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए कि संविधान से आसानी से एकत्र किया जा सकता है। अब यह स्वीकार किया जाता है कि

अभिव्यक्ति 'शहर के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

अनुच्छेद में 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति'

15 ( 4 ) संविधान के कुल मिलाकर पिछड़े वर्गों के बराबर हैं

अनुच्छेद 16 (4) में नागरिकों का। इस सवाल से निपटना कि क्या कोई

विशेष जाति या समूह या समुदाय को सामाजिक रूप से माना जा सकता है

और अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजनों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े, न्यायालय

बालाजी के मामले (ऊपर) में पृष्ठ 465 पर इस प्रकार देखा गया है:

" इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि राज्य को उचित ठहराया गया थायह विचार रखने में कि ऐसे समुदाय या जातियाँ जिनके

छात्रों की आबादी का गुस्सा उतना ही था, या उससे ठीक नीचे,

राज्य का औसत, शैक्षिक रूप से वापस माना जाना चाहिएनागरिकों के वार्ड वर्ग। यदि परीक्षण लागू किया जाना है ए

छात्र जनसंख्या के राज्य औसत के संदर्भ में,

वैध दृष्टिकोण यह होगा कि नागरिकों के वर्ग

जिनका औसत राज्य से काफी या काफी नीचे है।

औसत को शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा सकता है।यह आगे शाह, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) द्वारा समझाया गया था।

सागर का मामला (ऊपर) जब उन्होंने देखा कि निरोध के लिए मानदंड

पिछड़ेपन का खनन केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित नहीं होना चाहिए और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन के समान होना चाहिए। एक संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने जानकी प्रसाद परिमू और अन्य में उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया। आदि। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। जिसमें इसे पृष्ठ 252 पर इस प्रकार देखा गया था:

( 1 ) [ 1973 ] 3 एस. सी. आर 236



" यह बालाजी के मामले में पूर्व में बताए गए सिद्धांत के दूसरे हिस्से के लिए जिम्मेदार है जो बताता है कि पिछड़े

जिन वर्गों के लिए सुधार का विशेष प्रावधान था

अनुच्छेद 15 (4) द्वारा अनुध्यात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ तुलनीय होना चाहिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के उदाहरण हैं।

यह विचार 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान के उद्देश्यों और उद्देश्यों के संबंध में प्रस्ताव के अंतर्निहित खंड (6) के इरादे के अनुरूप है, जिसमें संविधान सभा से अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य नीच वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक संविधान बनाने के लिए कहा गया था और संविधान के अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के साथ भी। जब तक सरकार पर उपरोक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तब तक सरकार के लिए किसी भी जाति या समूह या समुदाय को पिछड़े के रूप में कहना संभव हो जाएगा, जो राज्य में एक शक्तिशाली राजनीतिक लॉबी का गठन करता है, भले ही वास्तव में यह एक उन्नत जाति या समूह या समुदाय हो, लेकिन किसी अन्य अगड़े समुदाय के ठीक नीचे। ऐसी उन्नत जातियों या समूहों या समुदायों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नहीं किए जाने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर ऐसी जातियां या समूह और समुदाय जो काफी उन्नत हैं और जो वास्तव में पिछड़े हैं और जो निचले स्तर पर हैं, उन्हें एक साथ पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से अधिक उन्नत वर्गों द्वारा खाया जाएगा और वास्तव में योग्य वर्ग व्यावहारिक रूप से लाभान्वित होंगे।

बिना किसी लाभ के जाएं क्योंकि उनमें से अधिक उन्नत जातियों या समूहों या समुदायों के बच्चों की अधिक संख्या ने अधिक पिछड़ी जातियों या समूहों या समुदायों के बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। उस स्थिति में आरक्षण का पूरा उद्देश्य निराश हो जाएगा। यह कहा गया है कि इस विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचने के लिए, देवराज उर्स की सरकार को अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से सिफारिशें करने के लिए हवनूर आयोग नियुक्त करना पड़ा था। इसलिए जहां तक संभव हो, पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करते समय राज्य सरकार को उपरोक्त सिद्धांत को एक मार्गदर्शक कारक के रूप में ध्यान में रखना होगा। उपरोक्त सिद्धांत को अपनाने से उन व्यक्तियों की संख्या में अनुचित रूप से कमी नहीं आएगी जो संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जातियों का स्तर कम हुआ है।

और अनुसूचित जनजातियाँ भी कई उपचारात्मक 488 के कारण बढ़ रही हैं।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उनके संबंध में किए गए उपाय। साथ ही, यह वास्तव में पिछड़ी जातियों, समूहों और समुदायों को कई पिछड़े समूहों की पकड़ से भी मुक्त करेगा, जिन्हें लगभग तीन दशकों से वास्तव में पिछड़े वर्गों के साथ आरक्षण का लाभ मिला है। यह समय है कि उन जातियों और समूहों पर अधिक ध्यान दिया जाए जो सभी नुकसान और अक्षमताओं (शायद अस्पृश्यता को छोड़कर) से पीड़ित सबसे निचले स्तर पर रहे हैं, जिनसे कई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उजागर किया गया है, लेकिन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने से होने वाले समान या समान लाभ ।चूँकि आर्थिक स्थिति भी एक प्रासंगिक मानदंड है, इसलिए पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण के रूप में 'साधन परीक्षण' को शामिल करना उचित होगा जैसा कि केरल सरकार ने जयश्री के मामले (उपरोक्त) में किया था। ये दो परीक्षण, अर्थात् कि जाति या समूह या समुदाय की स्थितियाँ कमोबेश उन स्थितियों के समान होनी चाहिए जिनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति स्थित हैं और यह कि जिस परिवार से उम्मीदवार संबंधित है, उसकी आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है, अनुच्छेद 15 (4) के तहत किए जाने वाले किसी भी आरक्षण के लाभार्थियों को निर्धारित करने में उपयोगी मानदंड के रूप में काम करेगा। तथापि, अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजन के लिए, यह भी दिखाया जाना चाहिए कि विचाराधीन पिछड़ा वर्ग सरकार की राय में सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।

एक अन्य आधार है जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए किए गए वर्गीकरण को चित्रलेखा के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की मंजूरी मिली है। उस मामले में न्यायालय आर्थिक स्थिति और व्यवसाय के आधार पर तैयार की गई पिछड़े वर्गों की सूची से संबंधित था। उस सरकारी आदेश के अनुसार, जिन व्यक्तियों के परिवार की आय रु। 1,200 प्रति वर्ष या उससे कम और जो इसमें लगे हुए थे

कृषि, लघु व्यवसाय, घटिया सेवाओं, शिल्प या शारीरिक श्रम से जुड़े अन्य व्यवसायों को पिछड़े वर्गों से संबंधित माना जाता था। उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने उक्त वर्गीकरण की वैधता को चुनौती नहीं दी। लेकिन राज्य की ओर से की गई प्रस्तुति परसरकार, न्यायालय ने वर्गीकरण की विधि के लिए अपनी सामान्य स्वीकृति व्यक्त की। यहां तक कि अब हमारे सामने भी, 'विशेष समूह' के रूप में शैलीबद्ध वर्गीकरण के तहत आने वाले सदस्यों के पक्ष में पदों की 15 प्रतिशत सीटों का आरक्षण है जो इसी तरह के ई. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटक (वेंकटरमैया, जे.) पर आधारित है।

489

व्यवसाय-सह-आय पर विचार। यहां भी किसी भी पक्ष द्वारा उक्त वर्गीकरण पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं की जाती है, जिसमें निर्धारित परीक्षाओं को संतुष्ट करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के लिए पात्र माना जाता है। यह स्पष्ट है कि यह 'विशेष समूह' सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकता का एक प्राणी है। चूंकि उपरोक्त आधार पर किए गए वर्गीकरण को समान संख्या वाली संविधान पीठ की मंजूरी मिल गई है और इसकी शुद्धता को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए हम इस वर्गीकरण को वैध मानते हैं, भले ही इस तरह के वर्गीकरण की आलोचना की गई हो, न कि अन्यायपूर्ण रूप से जैसा कि अब हम करते हैं।

डी. जी. विश्वनाथ के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा देखें। ( 1) यहवर्गीकरण में सभी बिल्लियों, समूहों के व्यक्ति और

समुदायों ने दो परीक्षण प्रदान किए, अर्थात् व्यवसाय परीक्षण औरआय परीक्षण संतुष्ट हैं।

इसके बाद की सीमा से संबंधित परेशान करने वाला सवाल आता है

आरक्षण जो कला के तहत किया जा सकता है। 15 ( 4 ) और कला। 16 ( 4 ) में से

संविधान। बालाजी के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने विचार लिया

कि चूंकि अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद है और

अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) और (2) के लिए एक अपवाद है।

अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत किया गया प्रावधान इससे अधिक नहीं होना चाहिए।

50 सीटों या पदों की कुल संख्या का प्रतिशत, जैसा भी मामला हो सकता है बनो। न्यायालय ने कहा कि 68 प्रतिशत सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 15 (4) जो एक विशेष प्रावधान था, अमान्य था। अदालत ने

आगे कहा गया कि 'आम तौर पर और व्यापक तरीके से बोलना एक विशेष

प्रावधान 50 प्रतिशत से कम, 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए। प्रतिशत प्रासंगिक मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा

प्रत्येक मामले में। इस कथन को एक संविधान पीठ ने समझा।

टी. देवदासन बनाम में इस न्यायालय का। भारत संघ और एएनआर। ( 3) के रूप में

यह नियम निर्धारित करना कि अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद के तहत आरक्षण

16 ( 4 ) 50 प्रतिशत से अधिक सीटें या पद नहीं हो सकते थे। में।उस मामले में जे. मुधोलकर ने बहुमत की ओर से कहा कि

पृष्ठ 698:

" भले ही सरकार ने प्रावधान किया था

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पदों का आरक्षण

रिक्तियों का प्रतिशत आरक्षण भरा जाएगाविशेष वर्ष या अधिक रिक्तियों का आरक्षण

50 प्रतिशत, बालाजी के निर्णय के अनुसार

मामला, संवैधानिक नहीं "।

( 1 ) ए. एल. आर. 1964 माई. 132 . ( 2 ) [ 1964 ] 4 एससीआर 680।

लेकिन केरल और अन्र राज्य में। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य।

( उपर्युक्त) आरक्षण की अनुमेय सीमा से संबंधित प्रश्न विचार के लिए, रे, सी. जे. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बेग, जे. (जैसा कि वे तब थे) उनका भी यही दृष्टिकोण था। फ़ज़ल अली, जे. ने पृष्ठ 1005 पर अवलोकन किया

इस प्रकार:

" इसका मतलब है कि आरक्षण इसके भीतर होना चाहिए।

अनुमेय सीमाएँ और सभी को भरने के लिए एक लबादा नहीं होना चाहिए

नागरिकों के एक विशेष वर्ग से संबंधित पद और

इस प्रकार कला का उल्लंघन होता है। 16 ( 1 ) अप्रत्यक्ष रूप से संविधान। में।

उसी समय कला का खंड (4)। 16 कोई सीमा तय नहीं करता है

आरक्षण देने की सरकार की शक्ति पर।

चूँकि खंड (4) कला का एक भाग है। 16 संविधान का

यह स्पष्ट है कि राज्य को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है अत्यधिक आरक्षण में ताकि नीति को विफल किया जा सके

कला में नाद। 16 ( 1 ) . क्या उपयुक्त होगा

अनुमेय सीमा के भीतर आरक्षण इस पर निर्भर करेगा कि

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और कोई कठोर और कठोर नहीं

त्वरित नियम निर्धारित किया जा सकता है और न ही इस मामले को कम किया जा सकता है।

एक गणितीय सूत्र के लिए ताकि सभी में पालन किया जा सके

मामले। इस न्यायालय के निर्धारित मामलों में कोई संदेह नहीं हैकि आरक्षण का प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए

50 प्रतिशत से अधिक। जैसा कि मैंने अधिकारियों को पढ़ा, यह है, हालांकि, सावधानी का एक नियम और सभी को समाप्त नहीं करता है

श्रेणियाँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य में एक विशाल राज्य है।

नागरिकों के पिछड़े वर्गों की संख्या जो

80 जनसंख्या और सरकार का प्रतिशत, मेंउन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने का आदेश, आरक्षित 80 प्रति

उनके लिए नौकरियों का प्रतिशत, क्या यह कहा जा सकता है कि

कला के खंड (4) की सीमाएँ। 16 ? इसका जवाब मिलना चाहिए।अनिवार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए। की प्रमुख वस्तु

यह प्रावधान अपर्याप्त बनाने के लिए कदम उठाने के लिए है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ”

कृष्ण अय्यर, जे. इसी मामले में पृष्ठ 981 पर देखा गया है।

इस प्रकार:

" मैं अपने विद्वान भाई जे. फजल अली से सहमत हूँ।

के. सी. वी. कुमार वी. कर्नाटका (वेंकटरमैया, जे.) में 50 प्रतिशत की अंकगणितीय सीमा

491

कुछ पहले के फैसलों द्वारा निर्धारित वर्ष को शायद दबाया नहीं जा सकता है

बहुत दूर। किसी विभाग में समग्र प्रतिनिधित्व नहीं है

किसी विशेष वर्ष में भर्ती पर निर्भर करता है, लेकिन कुल एक कैडर की ताकत। मैं उनके निर्माण से सहमत हूँ

कला. 16 ( 4 ) और 'कैरी फॉरवर्ड' नियम के बारे में उनका दृष्टिकोण।

में सभी सात रायों को ध्यान से देखने के बाद

उपरोक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि इस न्यायालय का यह स्थिर दृष्टिकोण कि अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, इस मामले का निर्णय करने वाली पीठ के बहुमत से अस्थिर हो गया है। मैं इस मामले में इस बिंदु को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि यदि आरक्षण केवल उन पिछड़ी जातियों या वर्गों के पक्ष में किया जाता है जो इस मामले से तुलनीय हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 18 प्रतिशत सहित)।

अनुसूचित जनजाति और 15 प्रतिशत 'विशेष समूह' के लिए आरक्षित)

कर्नाटक राज्य में ऐसे पिछड़े वर्गों की कुल आबादी का दृश्य। हवानूर आयोग ने संख्या ली है

वर्ष 1972 में एस. एस. एल. सी. परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र

पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए आधार। औसत प्रति पास करता है

कर्नाटक राज्य की कुल जनसंख्या का एक हजार था

1.69 1972 में। अनुसूचित कैस्ट के मामले में औसत था

0.56 और अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह संख्या 0.51 थी। भले ही हम लें

सभी जातियाँ, जनजातियाँ और समुदाय जिनका औसत प्रति व्यक्ति 50 से कम है। राज्य के औसत का प्रतिशत अर्थात नीचे। 85 उन्हें वर्गीकृत करने के लिए प्रतिशत

आबादी के पिछड़े, बड़े हिस्से के रूप में जिन्हें अब माना जाता है

पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर जाना होगा।

नतीजतन आरक्षण की आवश्यकता जो ले जाएगी

अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत 50 से अधिक कुल आरक्षण

सीटों/पदों की कुल संख्या का प्रतिशत मौजूद होगा।

वर्तमान व्यवस्था पर पांच साल से अधिक समय से काम किया जा रहा है। पहले से ही। अब पीठ के सवाल को फिर से निर्धारित करना आवश्यक है।

उद्देश्यों के लिए विभिन्न जातियों, जनजातियों और समुदायों का संरक्षणनवीनतम आंकड़ों के आलोक में अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)

विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर एकत्र किया जाना और सीमा को संशोधित करना

अब अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत बनाया गया है लेकिन जो हो सकता है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के आधार पर 'विशेष समूह' का पता लगाया गया

सदस्यों द्वारा किसी भी स्थिति में व्यवसाय-सह-आय का लाभ उठाया जा सकता है। सभी समुदायों और जातियों से।

इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अगर एक नए मोड़ पर है

खनन कुछ जातियों या समुदायों को 492 की सूची से बाहर जाना पड़ता है

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एल. एस सी आर।

सरकार अभी भी कमजोरों को सुधारने की नीति अपना सकती है उनके बीच जनसंख्या के वर्गों के अनुसार

संविधान के अनुच्छेद 46 में निहित निर्देशक सिद्धांत। सभी जातियों और समुदायों में ऐसे गरीब लोग हैं जो अगर उन्हें पर्याप्त अवसर और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे अमीर वर्ग के व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। सरकार उन्हें छात्रवृत्ति, मुफ्त छात्रावस्था, मुफ्त भोजन और रहने की सुविधा, मुफ्त वर्दी, मुफ्त मध्यान्ह भोजन आदि प्रदान कर सकती है ताकि गरीब छात्रों का जीवन आरामदायक हो सके। सरकार अतिरिक्त शिक्षण सुविधाएं, लेखन सामग्री और किताबें निःशुल्क और पुस्तकालय सुविधाएं भी प्रदान कर सकती है। ये और अन्य कदम निचली कक्षाओं में उठाए जाने चाहिए ताकि जब तक कोई छात्र योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हो, तब तक वह अपनी पढ़ाई में उच्च स्तर की प्रवीणता प्राप्त कर सके।

राज्य सरकार अब इसका पुनर्निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगी

इस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) के तहत सीटों/पदों के आरक्षण का पूरा सवाल है।

एसआर.